चिंतन

वार्ता से ही निकलेगा सुलह का रास्ता

परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और छात्रों के 'चलो संसद' मार्च के दौरान पैदा हुए तनाव के बाद जिस प्रकार केंद्र सरकार ने बातचीत की पहल की और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, उसके बाद अभिजीत दीपके द्वारा अनशन समाप्त करने का निर्णय एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।नड्डा ने प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर चर्चा की। बातचीत में सोनम वांगचुक की रिहाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सहित परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दे उठाए गए। यह पहल संकेत देती है कि लंबे गतिरोध का समाधान टकराव के बजाय संवाद और सहमति के माध्यम से तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह भी सच है कि हा मुद्दे का समाधान वार्ता से ही निकलता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां नागरिकों को अपनी बात रखने, सरकार से सवाल पूछने और अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाने का संवैधानिक अधिकार है। यही अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवंत बनाते हैं। दूसरी ओर, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की होती है। इसलिए जब भी किसी आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती है, तब दोनों पक्षों से संयम और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। सरकार द्वारा प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित करना और आंदोलनकारियों द्वारा बातचीत का रास्ता स्वीकार करना इस दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत है। इससे यह संदेश जाता है कि लोकतंत्र में असहमति के बावजूद संवाद के द्वार कभी बंद नहीं होने चाहिए। यदि दोनों पक्ष पूर्वाग्रह छोड़कर समाधान की भावना से आगे बढ़ें तो कई ऐसे विवाद भी सुलझ सकते हैं जो सड़क पर लंबे गतिरोध का कारण बन जाते हैं। अब आवश्यकता केवल आश्वासन तक सीमित रहने की नहीं है। सरकार को परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस सुधार लागू करने होंगे। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं और आयोजकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आवाज रचनात्मक सुझावों के साथ आगे बढ़े और आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक बना रहे। इससे उनकी मांगों को अधिक व्यापक समर्थन भी मिलेगा और समाधान की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी मसलों को मिल बैठकर सुलझाना ही प्राथमिकता होना चाहिए। वहीं, विपक्ष का दायित्व केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक सुझाव देना और समाधान की दिशा में सहयोग करना भी है। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध देश के युवाओं और भविष्य से है। अंततः यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सड़क पर उतरना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन स्थायी समाधान हमेशा संवाद की मेज पर ही निकलता है। टकराव क्षणिक सुर्खियां दे सकता है, पर विश्वास और सहमति केवल बातचीत से ही बनती है।

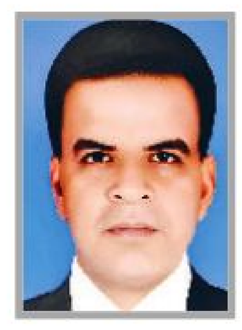

मुद्दा
कांतिलाल मांडोत

आंदोलन की आड़ में राजनीति अनुचित

परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में आयोजित 'चलो संसद' मार्च ने शिक्षा सुधार के मुद्दे के साथ-साथ आंदोलनों की प्रकृति और उनकी राजनीतिक भूमिका पर भी नई बहस छेड़ दी है। जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ते प्रदर्शन, पुलिस के साथ टकराव और विपक्षी दलों की सक्रिय मौजूदगी ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या यह केवल छात्रों की आवाज थी या फिर राजनीतिक दलों के लिए सरकार को घेरने का अवसर भी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब वह जनहित, संयम, संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में आगे बढ़े।

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए तथाकथित चलो संसद मार्च ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में हर आंदोलन वास्तव में जनहित के लिए होता है या फिर कुछ आंदोलन केवल राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए खड़े किए जाते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन को जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर समर्थन दिया, उससे यह आंदोलन एक स्वतंत्र जनआंदोलन कम और विपक्षी दलों के राजनीतिक मंचन का प्रयास अधिक दिखाई दिया। जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, कई लोग संसद मार्ग की ओर बढ़े और कुछ प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशनों तक पहुंच गए, जहां नारेबाजी भी हुई। ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और राजधानी में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, तब बिना अनुमति संसद की ओर मार्च निकालना स्वाभाविक रूप से कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाता है। शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान देता है, लेकिन उसके साथ कानून का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। लोकतंत्र अधिकार और जिम्मेदारी दोनों के संतुलन पर ही चलता है।

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना नागरिकों का अधिकार है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन संसद, राष्ट्रपति भवन या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगते हैं, तब प्रशासन के सामने सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि प्रदर्शनकारी और प्रशासन दोनों संयम बरतें। यदि कहीं अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहीं यदि कानून तोड़ने का प्रयास हुआ है तो उसके लिए भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि मंच पर और प्रदर्शन में कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह और अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि आंदोलन अब शिक्षा सुधार की मांग से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि यह वास्तव में छात्रों का आंदोलन था तो फिर विपक्षी दलों की इतनी सक्रिय भूमिका क्यों दिखाई दी। लोकतंत्र में राजनीतिक समर्थन असामान्य नहीं है, लेकिन जब किसी आंदोलन की पहचान उसके मूल मुद्दे से अधिक राजनीतिक दलों की उपस्थिति से होने लगे, तो उसके स्वरूप पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है। पेपर लीक का मुद्दा निश्चित रूप से गंभीर है और किसी भी परीक्षा में अनियमितता होने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती हैं और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और

पारदर्शिता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। लेकिन पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को विफल घोषित कर देना या हर परीक्षा को संदेह के घेरे में खड़ा कर देना भी उचित नहीं कहा जा सकता। लाखों विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम के बाद परीक्षाएं दीं और बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत का प्रमाण दिया।

ऐसे में यह कहना कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उन लाखों ईमानदार विद्यार्थियों की मेहनत का भी अपमान माना जा सकता है। सुधार की आवश्यकता स्वीकार करना और पूरे तंत्र को असफल घोषित कर देना दोनों अलग-अलग बातें हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। विपक्ष का यह अधिकार भी है और लोकतंत्र में उसकी जिम्मेदारी भी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि देश की शिक्षा व्यवस्था का बड़ा हिस्सा दशकों तक उन्हीं सरकारों के अधीन विकसित हुआ, जिनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया। यदि आज विपक्ष शिक्षा सुधार की बात करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए उसने कौन-सी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की थीं जो भविष्य की चुनौतियों का समाधान कर सकें। लोकतांत्रिक बहस तब अधिक प्रभावी होती है जब उसमें आत्ममंथन भी शामिल हो। यह भी देखने योग्य है कि इस पूरे आंदोलन में अभिजीत दीपके को प्रमुख चेहरा बनाया गया, जबकि राजनीतिक समर्थन विपक्षी दलों की ओर से प्रमुखता से दिखाई दिया। इससे ऐसी धारणा बनी कि आंदोलन का सामाजिक पक्ष धीरे-धीरे राजनीतिक रणनीति के साथ जुड़ गया। किसी भी जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता होती है। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि आंदोलन किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है, तो उसके मूल उद्देश्य पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने लगते हैं। देश इस समय आधारभूत संरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, परिवहन, विनिर्माण और वैश्विक कूटनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और आर्थिक संभावनाओं पर दुनिया की नजर है। ऐसे समय में सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ उसकी कमियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आलोचना तथ्यों, प्रमाणों और रचनात्मक सुझावों पर आधारित होनी चाहिए। केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से न तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और न ही विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान होगा। यह भी आवश्यक है कि सरकार ऐसे आंदोलनों को केवल राजनीतिक चुनौती मानकर खारिज न करे।

यदि छात्रों और युवाओं के बीच किसी विषय को लेकर असंतोष है तो उसके कारणों को समझना और समाधान निकालना भी सरकार की जिम्मेदारी है। संवाद किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। जहां संवाद समाप्त होता है, वहीं टकराव शुरू होता है। इसलिए सरकार और प्रदर्शनकारियों—दोनों को संवाद का रास्ता खुला रखना चाहिए। आज जरूरत केवल विरोध या समर्थन की राजनीति करने की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की है। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो, डिजिटल सुरक्षा मजबूत की जाए, पेपर लीक मामलों की समयबद्ध जांच हो और दोषियों को शीघ्र सजा मिले। इससे विद्यार्थियों का भरोसा मजबूत होगा और आंदोलन की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। वह समय के साथ यह तय करती है कि कौन-सा आंदोलन वास्तविक जनहित से प्रेरित है और कौन-सा राजनीतिक लाभ की संभावना से। शिक्षा सुधार पर गंभीर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए रचनात्मक संवाद, संस्थागत सुधार और ठोस नीति आवश्यक है, न कि केवल सड़क पर शक्ति प्रदर्शन।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

निर्णायक कदम
महेन्द्र तिवारी

शून्य उत्सर्जन की दिशा में भारतीय रेलवे का सफर

भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेल नेटवर्कों में से एक है। अपनी स्थापना के समय से लेकर आज तक भारतीय रेलवे ने समय के साथ अपनी तकनीक और कार्यप्रणाली में कई बड़े और परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं। कोयले से चलने वाले भाप इंजनों से लेकर डीजल और फिर व्यापक विद्युतीकरण तक का सफर रेलवे की निरंतर तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। इसी विकास यात्रा में अब एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन शुरू कर दिया है। नमो ग्रीन रेल के नाम से जानी जाने वाली यह अत्याधुनिक ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच पटरियों पर उतरी है। यह केवल एक नई ट्रेन का उद्घाटन मात्र नहीं है बल्कि यह ऊर्जा के स्वच्छ विकल्पों की ओर भारत के एक बड़े और निर्णायक कदम का प्रतीक है। इस ट्रेन का निर्माण रेलवे की चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है जो भारत की आत्मनिर्भरता और इंजीनियरिंग क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। इस ट्रेन के स्वरूप और क्षमता की बात करें तो इसमें दो विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार और आठ वातानुकूलित यात्री कोच शामिल किए गए हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ यह ट्रेन एक बार में लगभग छब्बीस सौ यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सुगमता से पहुंचाने में सक्षम है। गति के मोर्चे पर भी यह ट्रेन काफी उन्नत है। हालांकि इसकी अधिकतम डिजाइन गति एक सौ दस किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान प्रायोगिक चरण में इसे पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की सुरक्षित रफ्तार से संचालित किया जा रहा है। यह हाइड्रोजन ट्रेन अपनी बिजली खुद बनाती है। ट्रेन की छतों या विशेष डिब्बों में उच्च दबाव वाले मजबूत टैंक लगे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस सुरक्षित रूप से भरी होती है। यह गैस ट्रेन में लगे अत्याधुनिक फ्यूल सेल के भीतर जाती है। वहां यह गैस वायुमंडल से खींची गई ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रो रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है और यही वह बिजली है जो ट्रेन की भारी भरकम मोटरों को चलाकर उसे पटरियों पर आगे बढ़ाती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत और पर्यावरण के अनुकूल पहलू यह है कि इसमें कोई हानिकारक धुआं या कार्बन गैस वातावरण में नहीं घुलती है। जींद रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन में गैस भरने के लिए एक विशेष रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है जो इंजीनियरिंग का एक जटिल नमूना है। भविष्य में अगर इन ट्रेनों को पूरे देश में चलाना है तो ऐसे सैकड़ों स्टेशन बनाने होंगे। इसके लिए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा और उसे सुरक्षित रूप से देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए विशेष टैंकरों की व्यवस्था करनी होगी। भंडारण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना इस तकनीक का विस्तार संभव नहीं है। जब तक हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर उसके अंतिम वितरण तक का एक सस्ता और सुलभ तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता तब तक इस तकनीक का व्यावसायिक रूप से पूरे भारत में विस्तार करना एक बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती बनी रहेगी। रखरखाव और सुरक्षा के मामले में भी यह नई तकनीक रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव और चुनौती लेकर आई है। डीजल इंजनों के भारी भरकम यांत्रिक पुर्जों और तेल से अलग इस ट्रेन का रखरखाव मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक प्रणालियों की सटीकता पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही अधिक ज्वलनशील होती है इसलिए इसके जरा से भी रिसाव का पता लगाने के लिए ट्रेन के चप्पे चप्पे पर अति संवेदनशील सेंसर लगाए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वचालित प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इन सब अत्याधुनिक उपकरणों की नियमित जांच और मरम्मत के लिए भारतीय रेलवे को अपने तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों को सिरे से नया प्रशिक्षण देना होगा ताकि सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता न हो सके। संक्षेप में कहा जाए तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल धातु और तारों से बनी कोई सामान्य मशीन नहीं है बल्कि यह भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की एक स्पष्ट झलक है। जींद और सोनीपत के बीच चल रही यह प्रायोगिक ट्रेन अगर लागत समय की पाबंदी और सुरक्षा के कड़े पैमानों पर पूरी तरह से खरी उतरती है तो आने वाले कुछ ही वर्षों में हम हर कोने में ऐसी ट्रेनें दौड़ते हुए देख सकेंगे। यह न केवल भारतीय रेलवे का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगी बल्कि पूरी दुनिया को भी एक स्वच्छ सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन का रास्ता दिखाएगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शांति से दुखों को किया जा सकता है खत्म

संकलित
दर्शन

हम स्वयं शांति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु या स्थान शांति दे सकता है, यह एक काल्पनिक विचार है। हम स्वयं शांति से रह सकते हैं और दूसरों को भी शांतिपूर्वक रख सकते हैं। शांति एक मानवीय गुण तो है ही, लेकिन यह आत्मिक शक्ति है। शांति सभी सुखों की मूल है। इससे सभी वैभव एवं ऐश्वर्य की पूर्ति संभव है। शांति द्वारा सभी दुखों का शमन किया जा सकता है। इससे हर रोग का निदान होता है। शांति का माध्यम सभी समस्याओं का समाधान तैयार करता है। शांति ही देश का निर्माण करती है, वहीं अशांति से देश का पतन आरंभ होता है। शांति और अशांति के बीच समाज, समुदाय, वर्ग, कौम, जाति और संस्थाएं गतिहीन हो जाती हैं। देश की उन्नति, विकास और पुनर्निर्माण के लिए शांति का वातावरण अनिवार्य है। शांति एक शब्द मात्र नहीं है। शांति को मन मंदिर में बसाने वाले लोग देव तुल्य होते हैं। इसलिए स्वयं भी शांति के प्रहरी बनिए और दूसरों को भी शांति दूत बनाइए। यही संसार के मंगल का भेद है। शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। परिवार में शांति एक वट वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया में आनंद की अनुभूति पाई जा सकती है। अशांति कालांतर में अग्नि के समान जीवन के हर अंग को भस्म कर देती है। मानवता का मूल इसी शांति के गर्भ में स्थिर है। यदि जीवन को सुख और वैभव से संपन्न करना हो तो निश्चित ही शांति की पूजा करनी होगी। देश में जन सामान्य को शांति के सूत्र अपनाने चाहिए। सावधानी के साथ प्रेम का व्यवहार शांति के मार्ग को निष्कंटक करेगा।

बल प्रयोग अंतिम विकल्प

संकलित
प्रेरणा

एक चिड़िया का एक दाना पेड़ के कंदरे में कहीं फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया उस दाने को दे देने के लिए लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहां सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका दाना नहीं दे रहा। भला एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ कहां काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ दाना नहीं दे रहा। राजा ने उस नन्हीं चिड़िया को डांट कर भगा दिया कि कहां एक दाने के लिए वो उस तक पहुंच गई है। चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो महावत के पास गई कि अगली बार राजा जब हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और वही अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंढ़ में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहां से...बड़ी आई हाथी की सूंढ़ में घुसने को बोलने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने चींटी से कहा तुझे तो अपनी चोंच में डाल कर खा ही सकती हूँ। चींटी डर गई...भाग कर राजा के पास पहुंची। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया उससे कहा कि पेड़ काट दो नहीं तो सजा दूंगा। बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो। मैं चिड़िया को दाना लौटा दूंगा...! अंत में चिड़िया ने अपना दाना पेड़ से प्राप्त कर लिया और वो खुशी खुशी अपने घोंसले में चली गई।

अंतर्मन

आज की पाती

घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार का समय

भारत की सीमाओं की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लंबे समय से बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से होने वाली अवैध घुसपैठ देश के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। यह समस्या केवल अवैध रूप से देश में प्रवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ फर्जी दस्तावेज, मानव तस्करी, हवाला, नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का जाल भी जुड़ जाता है। इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए अब आधे-अधूरे नहीं, बल्कि निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन कराना, सीमा पर बाड़ लगाने की गति तेज करना और घुसपैठ रोकने के उपायों की समीक्षा बढ़िया कदम हैं। - *प्रतीक साहू, दुर्ग*

ट्रेंड

युवा इतिहास रच रहे

युवा आज इतिहास रच रहे हैं। नए स्टार्टअप अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं। मुझे बताया गया कि स्काईरूट कंपनी की जिस टीम ने यह कारनामा कर दिखाया है। उनकी औसत उम्र 28 साल है। हालांकि मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा। -**नरेंद्र मोदी**, पीएम

बटुकेश्वर दत्त को नमन

महान स्वाधीनता सेनानी एवं अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। उन्होंने भगत सिंह जी के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध पूरे देश में आजादी की अलख जलाई। कठोर यातनाएँ सहकर भी स्वाधीनता के संकल्प को अडिग रखा। -**अमित शाह**, गृहमंत्री

पीएम मोदी युवा विरोधी

प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं। वह इतने युवा-विरोधी हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक की घटनाओं से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी दोषी को सजा नहीं मिली। -**राहुल गांधी**, नेता विपक्ष

हमारी मांग स्पष्ट

हमारी मांग स्पष्ट है, जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। यह हमारी जायज मांग है और हमारा वैध अधिकार है। हम इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। केंद्र सरकार को हमारी मांग पूरी करनी होगी। -**फारूक अब्दुल्ला**, पूर्व सीएम, जम्मू-कश्मीर

करंट अफेयर

कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 930 लोगों की मौत

कांगो में इबोला के प्रकोप से कम से कम 930 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 37 लोगों की मौत शुक्रवार से शनिवार के बीच 24 घंटे के दौरान हुई। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शनिवार तक इबोला के 2,344 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 930 मरीजों की मौत हो चुकी है। पूर्वी कांगो में इबोला के प्रकोप की घोषणा 15 मई को की गई थी। यह रिकॉर्ड में, सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बन गया है। इस प्रकोप के लिए जिम्मेदार बंडिबुग्यो वायरस, इबोला बीमारी फैलाने वाले अन्य वायरस की तुलना में कम पाया जाता है और इसके लिए फिलहाल कोई मंजूरी प्राप्त टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। इबोला अत्यधिक संक्रामक बीमारी है और यह जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। यह बीमारी कई मामलों में जानलेवा साबित होती है। मौत के आंकड़ों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण सबसे अधिक प्रभावित प्रांत 'इतुरी' में राहत और बचाव अभियान पर असर पड़ा है। कुल पांच प्रांत प्रभावित हुए हैं और ये सभी पूर्वी इलाके में हैं, जहां विद्रोहियों का बोलबाला है।

ऑफ बीट

ग्रीक फायर: रोमन साम्राज्य का सबसे विनाशकारी हथियार

आधुनिक काल के सामूहिक विनाश के हथियारों से बहुत पहले एक ऐसा हथियार था, जिसे 'ग्रीक फायर' (इग्निस ग्रेकस) के नाम से जाना जाता है।

ग्रीक फायर का सूत्र इतना गोपनीय रखा गया था कि 1453 में बीजान्टिन साम्राज्य के ओटोमन साम्राज्य के हाथों पतन के साथ ही इसका रहस्य भी हमेशा के लिए खो गया। तब से लेकर आज तक अनेक रसायनविद, इतिहासकार, वैज्ञानिक और प्रायोगिक पुरातत्वविद इस रहस्यमयी हथियार का वास्तविक सूत्र जानने की कोशिश करते रहे हैं। ग्रीक फायर एक ज्वलनशील तरल पदार्थ था, जिसे बीजान्टिन युद्धपोतों के अगले हिस्से पर लगी पीतल या कांसे की नली (साइफन) के माध्यम से दुश्मन के जहाजों पर फेंका जाता था। यह तरल जिस सतह पर गिरता, उससे चिपक जाता था। यहां तक कि पानी पर भी यह जलता रहता था और उसे बुझाना लगभग असंभव था। नेपाम (नैप्थालीन और नारियल के तेल से बना पदार्थ) की तरह काम करने वाला यह हथियार बीजान्टिन नौसेना को अपने दुश्मनों पर बड़ा सामरिक लाभ देता था। सातवीं शताब्दी में उभरती हुई अरब शक्ति की समुद्री ताकत ने बीजान्टिन साम्राज्य के सामने नयी चुनौतियां खड़ी कर दी थीं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

प्रदर्शन और समझदारी

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जंतर मंतर से संसद भवन तक नाराज युवाओं ने जिस तरह से मार्च किया और पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को संभाला, इसकी चर्चा देश में स्वाभाविक ही है। सोमवार की सुबह एक वक्त ऐसा लगा था कि समाधान निकल आया है। सरकार की ओर से संवाद की पहल शुरू हुई थी और सोनम वांगचुक का नजरिया नरम पड़ा था। उन्होंने मूल रूप से तीन शर्तें रखीं, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल में मिली विफलताओं व पेपरलीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी, सांसद और सीजेपी के नेता संसद पहुंचें और सियासी दल इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दें। तीसरी, विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल में उनसे मिलने आएं और उन्हें भी यही आश्वासन दें। ऐसा माना गया कि वांगचुक की शर्तों को सरकार मान लेगी और यह भी माना गया कि सीजेपी ने अपनी शर्तों में ढील दे दी है। सरकार ने बात सुनने की शुरुआत की, तो सीजेपी के नेताओं ने अनशन तोड़ दिया।

बहरहाल, दिन ढलने से पहले ही सीजेपी की तीन बड़ी शर्तें सामने आ गईं। संसद मार्च के दौरान सीजेपी के दो प्रतिनिधि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले और अपनी तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, सोनम वांगचुक की रिहाई। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और तीसरी, नीट की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा। वांगचुक के नरम रुख के बाद सीजेपी के गरम रुख से बात उलझ गई। यह कहा जा सकता है कि इन मांगों को मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। फिर भी उसे संवाद से समाधान निकालने के प्रयास जारी रखने चाहिए। सोमवार को तो संवाद की शुरुआत भर हुई है। ध्यान रहे, आंदोलन तेज होने के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच यह पहला औपचारिक संवाद था। छात्रों और युवाओं को संतुष्ट करने की जरूरत है। संसद मार्च कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा बहुत कम हुआ है, जब कोई प्रदर्शन संसद भवन के इतने पास पहुंचा है। यह अपने आप में गंभीर प्रश्न है कि ऐसी नौबत क्यों आई? दुर्भाग्य से राष्ट्रीय राजधानी के एक हिस्से में भारी पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, धरपकड़ से यातायात की समस्या देखने में आई है। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने मार्च निकालने की मंजूरी नहीं दी थी, तब भी मार्च निकाला गया है, इससे स्वाभाविक ही हालात तनावपूर्ण हुए हैं। सरकार को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हालात और न बिगड़ें।

किसी भी लोकतांत्रिक प्रदर्शन में उग्रता और हिंसा सरासर गलत है। सरकार को छात्रों के साथ संवाद के जरिये समाधान निकालने के प्रयास तेज करने चाहिए।

दोनों ही पक्षों को सतर्कता बरतनी चाहिए। किसानों के आंदोलन के समय दिल्ली और लाल किले में जिस तरह से उपद्रव हुआ था, वैसा फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे आंदोलनों में असामाजिक या विपक्षी राजनीतिक संगठन जब शामिल हो जाते हैं, तब उग्रता की आशंका बढ़ जाती है। कोई दोराय नहीं कि अगर दिल्ली में उपद्रव होगा या बढ़ेगा, तो इससे प्रदर्शनकारियों ही नहीं, सरकार के प्रबंधन पर भी प्रश्न उठेंगे। वाकई, पेपर लीक भारत में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका समाधान सरकार को पूरी मुस्तैदी व कड़ाई से निकालना चाहिए। इतने बड़े देश में पेपर लीक के दोषियों के लिए ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल संसद सत्र चल रहा है, तो राजनीति से बचा नहीं जा सकता, पर सभी पक्षों को देश के सम्मान को सर्वोपरि रखना होगा। आज जरूरी है , इस आंदोलन को संवेदनशीलता से संभाला जाए, ताकि देश के अन्य शहरों या इलाकों में यह फैलने न पाए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 21 जुलाई, 1951

स्पेन और अमरीका

जनरल फ्रांको का स्पेन आज भी संयुक्त राष्ट्रों की बिरादरी से बहिष्कृत है। जनरल फ्रांको हिटलर और मुसोलिनी की मदद से स्पेन में सत्तारूढ़ हुए थे। इस उपकार का बदला उन्होंने द्वितीय महायुद्ध में चुकाया। उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति को खुले रूप में प्रकट किया और युद्ध में प्रकट भाग न लेते हुए हिटलर और मुसोलिनी को यथासंभव सहायता पहुंचाई थी। जनरल फ्रांको फासिस्ट मित्रों की सहायता से स्पेन की प्रजातंत्री सरकार का गला घोंटने के बाद स्पेन के तानाशाह बने हुए हैं। स्पेन के इस इतिहास को दृष्टि में रखकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य राष्ट्रों से स्पेन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित न करने का निर्देश दिया था। किन्तु जैसे-जैसे समय बीत रहा है, पश्चिमी राष्ट्रों का स्पेन के प्रति अपना रुख नरम होता जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्पेन के प्रति मित्रता जोड़ने में अमरीका सबसे आगे है और वह इस बारे में अपने मित्रराष्ट्रों की इच्छा-अनिच्छा या भावनाओं का लिहाज करने की जरूरत नहीं समझता। अमरीका के शासक तानाशाही राष्ट्रों के कट्टर विरोधी होने का दम भरते है, किन्तु अपनी इष्ट-सिद्धि के लिए तानाशाह जनरल फ्रांको को गले लगाने को प्रस्तुत नजर आते हैं।

अमरीका के सैनिक विशारदों ने यह अनुभव किया है कि सैनिक कारणों से पश्चिमी यूरोप की रक्षा-योजना में स्पेन का सहयोग प्राप्त किया जाये। उसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि उत्तरी अटलांटिक समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्रों में स्पेन को भी शामिल कर लिया जाये। किन्तु ब्रिटेन, फ्रांस आदि इस गुट के अन्य राष्ट्र इसके लिए सहसा प्रस्तुत नहीं हो सकते। अतः अमरीका ने घुमाकर नाक पकड़ने का विचार किया है। वह स्पेन के साथ अलग सैनिक संधि कर सकता है। स्पेन अमरीका को अपने देश में समुद्री और हवाई अड्डे कायम करने की इजाजत दे सकता है और बदले में अमरीका स्पेन को युद्ध-सामग्री और आर्थिक सहायता दे सकता है। इस विषय में स्पेन के साथ आरम्भिक वार्ता चलाने के लिए अमरीकी एडमिरल शेरमन ने हाल ही स्पेन की राजधानी की यात्रा की थी। अमरीकी राष्ट्रपति श्री ट्रमन में स्वीकार किया है कि स्पेन के प्रति अमरीका की नीति में एक हद तक परिवर्तन हुआ है। अमरीका के इस नीति-परिवर्तन पर अटलांटिक गुट के राष्ट्रों में खासी हलचल मची है।

फुटबॉल में सिरमौर कैसे बना स्पेन

अनादि बरुआ | पूर्व राष्ट्रीय कोच, फुटबॉल

स्पेन के युवा खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में फ्रांस के विरुद्ध छोटे-छोटे पास देने की जो रणनीति अपनाई थी, वही व्यूह-रचना फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ भी काम आई।

बीते चार फीफा कप में यह तीसरा मौका था, जब अर्जेंटीना की टीम फाइनल खेल रही थी। साल 2014 में वह जर्मनी के हाथों पराजित हो गई थी, तो 2022 में उसने फ्रांस को शिकस्त देकर विश्व विजेता का तमगा हासिल किया था। इस बार माना जा रहा था कि कप्तान लियोनेल मेसी का जादू चलेगा और चौथी बार उनकी टीम ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्पेन के फेरान टोरेस ने 'अतिरिक्त समय' में एकमात्र गोल करके अर्जेंटीना के प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया और इस तरह, जीत के साथ फुटबॉल से संन्यास लेने का मेसी का सपना भी टूट गया।

टूर्नामेंट के बाकी मैचों से तुलना करें, तो यह एक फीका फाइनल था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में 308 गोल हुए। फिर भी रविवार की रात एक अच्छा खेल देखने को मिला। स्पेन की टीम ने 'टिकी-टाका' और 'वन-टच' पर जोर दिया। टिकी-टाका में जहां छोटे-छोटे पास दिए जाते हैं, खिलाड़ियों का लगातार 'मूवमेंट' होता रहता है और बॉल पर कब्जा बनाए रखने पर जोर होता है, वहीं वन टच में पास की गति तेज होती है। इसे 'गिव ऐंड गो' भी कहते हैं और खिलाड़ी गेंद को रोकने या अपने पास रखने के बजाय सीधे दूसरे खिलाड़ी की ओर पास कर देता है। स्पेन ने इन दोनों शैलियों को आत्मसात कर लिया था। 90 मिनट तक एक भी गोल न करने के बावजूद उसके खिलाड़ियों ने अपना धैर्य नहीं खोया। सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ उन्होंने जो रणनीति अपनाई थी, वही व्यूह-रचना इस बार अर्जेंटीना के खिलाफ भी आजमाई गई, जो समान रूप से सफल साबित हुई।

स्पेन के खिलाड़ी पास देने में किस हद तक सक्रिय थे, इसका अंदाजा इससे भी लगता है कि पूरे मैच के दौरान उन्होंने एक-दूसरे को 803 बार पास दिए, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी इसके लिए जूझते दिखे। वे 445 बार ही बॉल साथी खिलाड़ी को दे सके। यही कारण रहा कि अर्जेंटीना का खेल काफी हद तक रक्षात्मक और

मुकाबले को धीमा करने वाला रहा। स्पेन के साथ अच्छी बात यह भी रही कि उसके खिलाड़ी अर्जेंटीना की तुलना में युवा हैं। फाइनल खेलने वाले लामिन यमाल तो महज 19 साल के हैं, जबकि अर्जेंटीना के कप्तान मेसी 39 साल के हो चुके हैं। मुकाबले के बाद जब यमाल रोते हुए मेसी के गले लगे, तो उसका महत्व काफी ज्यादा था। यह एक से दूसरी पीढ़ी को जिम्मेदारी की बागडोर सौंपने का संकेत था।

हालांकि, मेसी को लेकर स्पेन की रणनीति इस बार कुछ अलग थी। पहले हमने देखा है कि विपक्षी टीम के दो-तीन खिलाड़ी मेसी को घेरे रहते थे, ताकि फुटबॉल उनसे छीनी जा सके, लेकिन स्पेन ने बजाय इसके कोशिश यह की कि फुटबॉल उनके पास पहुंचे ही नहीं। स्पेन के खिलाड़ी एक-दूसरे को पास देते हुए अर्जेंटीना के गोलपोस्ट के आसपास खेलते रहे। इस तरह, मेसी स्पेन के गोलपोस्ट के नजदीक होने के बावजूद विरोधी टीम के लिए बड़ा खतरा न बन सके।

अर्जेंटीना की हार का एक कारण एंजो फर्नांडीज को रेड कार्ड मिलना भी था, जिसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा। गौरतलब है, पूरे टूर्नामेंट में स्पेन सिर्फ एक गोल खाया, वह भी क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम द्वारा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उसके खिलाड़ी हमेशा एक टीम के रूप में खेलते रहे। इसी वजह से फर्नांडीज का 'डगआउट' में आना अर्जेंटीना की मुश्किलें बढ़ा गया।

देखा जाए, तो यह पूरा टूर्नामेंट एक्शन और रोमांच से भरा रहा। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका था, जब 48 टीमें मुकाबले में उतरी थीं। 200 से अधिक फीफा सदस्य टीमों ने एक-दूसरे से मुकाबला करके फुटबॉल के इस महाकुंभ में खेलने का अधिकार हासिल किया था। चूंकि इसमें एक से बढ़कर दूसरी टीमें थीं, इसलिए टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट राउंड तक मुकाबले रोमांचक रहे। नतीजों के साथ-साथ खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा।

इसमें एशियाई टीमों की प्रशंसा लाजिमी है। इस विश्व कप में एशिया ने अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। जापान, ईरान, इराक, कतर, जॉर्डन, कोरिया, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान के हाथों में एशिया की बागडोर थी, जिनमें से जापान और ईरान ने खासतौर से चौंकाया। जापान की टीम ने नीदरलैंड के साथ ड्रॉ खेला, स्वीडन को बराबरी पर रोकने में वह सफल रही, ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया, यहां तक कि 32वें मुकाबले में उसने ब्राजील को करीब-करीब रोक ही दिया था। उस मुकाबले में उसे 2-1 से जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

रही बात ईरान की, तो वह बेशक अभी जंग के मैदान में अमेरिका और इजरायल के सामने है, लेकिन खेल के मैदान में भी उसके जुझारूपन की खूब तारीफ हो रही है। उसने अपनी सूझ-बूझ और खेल-कौशल का भरपूर परिचय दिया। यही वजह है कि ग्रुप मुकाबलों में ईरानी टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया और न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र से मुकाबला ड्रॉ करवाया। इसे फीफा की उपलब्धि ही कहेंगे कि राजनीतिक मतभेदों वाले देशों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से मैदान में मुकाबला किया। यह इस बात को पुष्ट करता है कि खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है और निष्पक्षता खेल की सच्ची भावना का प्रतीक है।

फुटबॉल का बुखार भारतीयों के भी सिर चढ़कर बोला। खासकर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फुटबॉल प्रेमियों ने रात-रात भर जागकर मैच देखे। फाइनल के बाद तो कुछ लोग स्पेन की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। निस्संदेह, मेसी के प्रति हम भारतीयों में विशेष लगाव है, लेकिन स्पेन की जीत ने लाखों प्रशंसकों को मिडफील्डर रोड्री, फेरान टोरेस और युवा सनसनी पाउ कुबारसी का मुरीद बना दिया है।

हमारे देश में भी फुटबॉल-प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में कई अच्छे खिलाड़ी दिख जाते हैं। अगर उनका सही तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास किया जाए, यानी उन्हें स्काउटिंग मिले और जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए, तो कई भारतीय युवा खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप का यह रोमांच भारतीय फुटबॉल के नीति-नियंताओं को भी विशिष्ट प्रयास करने को प्रेरित करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जलवायु आपदा पर दक्षिण के राज्यों में मंथन शुरू

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

इस वर्ष देश में खेती-किसानी गंभीर संकट से गुजर रही है। इसकी मूल वजह 'अल नीनो' की वापसी है। मौसम विभाग ने इसके कारण 15 जुलाई तक देश के 60 प्रतिशत जिलों में कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। पूरे भारत में असमान और अनियमित वर्षा के कारण स्थिति के और खराब होने की आशंका है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर में 112 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे से सर्वाधिक प्रभावित हैं।

कर्नाटक और तेलंगाना में कम वर्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के किसान और कृषि विशेषज्ञ भी अधिकारियों पर आपातकालीन उपायों में तेजी लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। दक्षिण के किसान विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि इनकी कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। चूंकि इन सूबों में गैर-भाजपा सरकारें हैं, इसलिए उन्हें सूखा राहत के लिए केंद्र से धन मिलने को लेकर आशंका है, क्योंकि मनरेगा की जगह आई 'वीबीजी रामजी' योजना में राज्यों को अपना 40 प्रतिशत योगदान देना होता है, जबकि मनरेगा में यह शून्य था।

भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून पर अल नीनो का बुरा असर पड़ा है। यही मानसून खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए जरूरी होता है। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से जलाशयों में पानी का स्तर कम होने, पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने, मवेशियों के लिए चारे की कमी और फसलों के खराब होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में, जिन किसानों ने मई के आखिर में बीज बोए थे, उनके सामने अब मुश्किल हालात हैं, क्योंकि उसके बाद बारिश नहीं हुई। हालत यह है कि सूखे के कारण पूरे कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जाने लगी है। चूंकि अगले दो महीनों में हालात सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए राज्य सरकार ने भी किसानों से कहा है कि पानी नहीं है, तो वे खेती न करें। ऐसे में, किसान 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा राहत व कर्ज-माफी की मांग कर रहे हैं।

अगले दो महीनों में हालात सुधरने की उम्मीद न देख कर्नाटक सरकार ने किसानों से कहा है कि पानी नहीं है, तो अभी खेती न करें।

आंध्र प्रदेश में तो लगभग 70 प्रतिशत कृषि भूमि में कोई खेती नहीं हो रही है। धान, कपास और मक्का वाले पारंपरिक इलाकों में सिर्फ 50 प्रतिशत खेतों में बुवाई हुई है। राज्य के 678 मंडलों में से 400 बुरी तरह सूखा प्रभावित हैं। वहां मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। राज्य के किसान इस बात से बेहद खफा हैं कि उप-मुख्यमंत्री और पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने इस संकट पर अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक के किसान नेता इस बात से नाराज हैं कि राजनेता अपना ज्यादातर समय दलीय राजनीति में बिता रहे हैं, लेकिन ग्रामीण संकट पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वह बड़े निवेश और वैश्विक विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन कृषि संकट जैसी आस-पास की बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते।

तेलंगाना में भी ज्यादातर जलाशयों में पानी का स्तर 30 प्रतिशत से नीचे गिर गया है। राज्य में पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 90 प्रतिशत कम बारिश होने की आशंका है। चूंकि मिट्टी में नमी का स्तर तेजी से कम हो रहा है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालयों और सरकार के कृषि विस्तार विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे कम पानी वाली फसलों पर ध्यान दें। जुलाई के मध्य तक तमिलनाडु में बारिश में 95 प्रतिशत की कमी देखी गई। नतीजतन, राज्य के अंदरूनी इलाकों में भीषण गर्मी है। अनोखी भौगोलिक स्थिति होने के कारण तमिलनाडु को दो मानसून प्रणालियों से बारिश मिलती है। अधिकारियों को चिंता है कि क्या मौजूदा अल नीनो का असर दिसंबर में आने वाले उत्तर-पूर्वी मानसून पर भी पड़ेगा? यहां के बागानों पर भारी खतरा मंडरा रहा है और मानसून वर्षा में 34 प्रतिशत की कमी है।

एक अच्छी बात यह है कि दक्षिणी राज्यों में जलवायु आपदा पर बात शुरू हो गई है, हालांकि ये प्रदेश देश के कुल अनाज उत्पादन में केवल 15 से 20 प्रतिशत का योगदान करते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने धान और दालों की जगह नगदी फसलों की खेती शुरू कर दी है, जिसमें उन्हें आर्थिक फायदा हो रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मनसा वाचा कर्मणा

मनुष्यता का कैसा विभाजन

पिछले दिनों एक सज्जन मिले और बोले, 'आपके कुछ व्याख्यान मैंने पढ़े और सुने हैं। मुझे आपका कहना बहुत निषेधात्मक लगा; उसमें कोई मार्गदर्शक सुझाव, जीवन का कोई विधायक मार्ग नहीं है। यह प्राच्य दृष्टिकोण (पूरब के देशों का नजरिया) अत्यंत विनाशकारी है और देखिए, इसने उसे कहां लाकर छोड़ा है? आपका निषेधात्मक रवैया और विशेष रूप से आपका यह आग्रह कि समस्त विचार से मुक्ति आवश्यक है, हम पश्चिमी लोगों को बहुत दिग्भ्रमित करता है, जो स्वभाव और आवश्यकता से उद्यमी रहे हैं। आप जो सिखा रहे हैं, वह हमारी जीवन-प्रणाली के पूर्णतया विरुद्ध है।'

मैंने उनसे कहा कि पूरब और पश्चिम के लोगों के बीच का यह विभाजन भौगोलिक और मनमाना है। उसका कोई मौलिक महत्व नहीं है। हम भले किसी एक रेखा के पूरब या पश्चिम में रहते हों; हम भूरे, काले, गोरे या पीले रंग के हों, फिर भी हम सब मनुष्य ही हैं, जो दुख भोगते और आशा रखते हैं; जो भयभीत हैं और श्रद्धालु भी; उल्लास तथा पीड़ा जैसे यहां हैं, वैसे ही वहां भी हैं। विचार कभी पूरब या पश्चिम का नहीं होता, परंतु मनुष्य इसको अपनी संस्कारबद्धता के अनुसार विभाजित कर लेता है। प्रेम भौगोलिक नहीं है, जिसे एक महाद्वीप में पवित्र माना और दूसरे में नकारा जाता है। मनुष्यों के बीच यह विभाजन आर्थिक और शोषण के प्रयोजन से किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति स्वभाव में या अन्य विशेषताओं में भिन्न नहीं होते; समानता होती है, तो भिन्नता रहती है। यह सब काफी स्पष्ट और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यात्मक है। है न?

विभिन्नता देखते हुए भी हमें समानता का भान रखना होगा। बाह्य अभिव्यक्तियां अलग हो सकती हैं और हैं भी, परंतु इन बाहरी रूपों और प्रकटन की पृष्ठभूमि में लालसाएं, दबाव, उत्कंठाएं और भय एक जैसे ही हैं। इसलिए शब्दों से हम ठगे न जाएं। सभ्यताओं में जलवायु, परिस्थिति, भोजन इत्यादि के अनुरूप भेद होता होगा, परंतु पूरे विश्व में संस्कृति मूलतः एक ही है- करुणावान होना, बुराई से दूर रहना, उदार होना, ईर्ष्यालु न होना, क्षमाशील होना इत्यादि।

इस मूलभूत संस्कृति के अभाव में यहां या वहां की कोई भी सभ्यता विघटित अथवा विनष्ट हो जाएगी। तथाकथित पिछड़े लोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वे बहुत जल्दी पश्चिम की तकनीकी जानकारी सीख सकते हैं; वे भी युद्ध-पिपासु, जनरल, वकील, पुलिस वाले और यातना गृहों तथा अन्य उपायों के साथ निरंकुश तानाशाह बन सकते हैं। संस्कृति एक पूरी तरह से अलग मसला है। ईश्वर का प्रेम या मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी आसानी से सुलभ नहीं है और इनके बिना भौतिक सुख-सुविधाओं का अधिक अर्थ नहीं रहता।

सभ्यताओं में जलवायु, भोजन इत्यादि के अनुरूप भेद होता होगा, परंतु पूरे विश्व में संस्कृति मूलतः एक ही है- करुणावान होना, बुराई से दूर रहना, ईर्ष्यालु न होना, उदार-क्षमाशील होना।

जे कृष्णमूर्ति

एंटोनियो गुटेरस | महासचिव, संयुक्त राष्ट्र

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में विकासशील देशों के पास नई प्रतिभा, नए आइडिया और युवा आबादी जैसे संसाधन प्रचुरता में हैं। हरेक देश को अपने कौशल, डाटा व भाषाओं का इस्तेमाल कर अपने हित में एआई का विकास करना चाहिए।

अनुलोम-विलोम
हाइड्रोजन ट्रेन

रेलवे में हरित ऊर्जा क्रांति की शुरुआत

भारत ने रेल परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। हमसे पहले से जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह उपलब्धि केवल रेलवे की सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में देश की बड़ी छलांग है।

इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन है। ट्रेन में लगभग 440 किलोग्राम हाइड्रोजन संग्रह कर सकते हैं और एक बार ईंधन भरने के बाद यह करीब 356 किलोमीटर तक चल सकती है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन का संचालन पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि इंजन से धुएं की जगह केवल जलवाष्प, यानी भाप और थोड़ा पानी निकलता है। इस कारण इसे शून्य उत्सर्जन वाली तकनीक माना जा रहा है। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है कि इससे कार्बन डाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन समाप्त हो जाता है। इस तरह, यह तकनीक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाती है और आयातित पेट्रोलियम पर खर्च कम करने में मदद करती है। जिन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइन बिछाना कठिन है, वहां हाइड्रोजन ट्रेन बेहतर विकल्प बन सकती है। इसका संचालन अपेक्षाकृत शांत होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है।

भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से इसकी लागत घटेगी और रेलवे के साथ अन्य परिवहन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ेगा।

हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के साथ हरियाणा देश में हाइड्रोजन तकनीक का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाते वक्त यह भरोसा दिया कि सरकार लागत कम करने और तकनीक को अधिक सक्षम बनाने के लिए लगातार अनुसंधान करेगी। इस परियोजना से जींद और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसका एक अहम पक्ष ऊर्जा सुरक्षा भी है। वर्ष 2014 से पहले रेलवे का बड़ा हिस्सा डीजल इंजनों पर निर्भर था, लेकिन पिछले बारह वर्षों में लगभग 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इससे डीजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और अब हाइड्रोजन जैसी नई तकनीक ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

इस राह में कई व्यावहारिक चुनौतियां

जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, तब परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को लेकर होड़ तेज हो गई है। भारतीय रेलवे ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कर दी है। यह केवल एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और भविष्य की ऊर्जा नीति की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। हालांकि, ऐसे समय में, जब यूरोप के कुछ देशों ने हाइड्रोजन ट्रेनों के अनुभवों के आधार पर अपने कदम धीमे कर दिए हैं और बैटरी आधारित ट्रेनों की ओर झुकाव बढ़ा दिया है, भारत का यह प्रयोग अनेक सवाल खड़े करता है। क्या हाइड्रोजन ट्रेनें वास्तव में भविष्य हैं या फिर ये केवल एक महंगा प्रयोग साबित होंगी? इन प्रश्नों का उत्तर केवल तकनीकी उत्साह में नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव, आर्थिक गणना और पर्यावरणीय दृष्टिकोण में छिपा है।

केवल उत्साह के आधार पर किसी तकनीक को भविष्य घोषित कर देना उचित नहीं होगा। दुनिया के कई विकसित देशों का अनुभव बताता है कि हाइड्रोजन ट्रेनों के सामने कई व्यावहारिक चुनौतियां हैं। जर्मनी ने बड़े उत्साह के साथ हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू किया था, लेकिन बाद में ईंधन सेल की कार्यक्षमता में गिरावट, हाइड्रोजन की आपूर्ति संबंधी कठिनाइयां, रखरखाव की जटिलता और अधिक लागत जैसी समस्याओं के कारण कई मार्गों पर बैटरी चालित ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाने लगी। जापान, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों ने भी अभी तक इस तकनीक को बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया है, बल्कि इसे छोटी परियोजनाओं तक सीमित रखा है। इसका मतलब है कि इस तकनीक को अभी और परिपक्व होने की आवश्यकता है।

भारत की स्थिति इन देशों से कुछ अलग भी है। भारतीय रेलवे का अधिकांश नेटवर्क पहले से ही विद्युतीकृत है। हाइड्रोजन ट्रेनों का मूल उद्देश्य उन क्षेत्रों में डीजल इंजनों का विकल्प बनना है, जहां बिजली की लाइनें उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन भारत में जिस मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, वह पहले से विद्युतीकृत है, इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बिजली उपलब्ध है, तब हाइड्रोजन ट्रेन की आवश्यकता क्यों? हालांकि, वास्तविक चुनौती केवल ट्रेन बनाने की नहीं है। प्रत्येक स्टेशन पर हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और ईंधन भरने की व्यवस्था तैयार करना महंगा और जटिल कार्य है। इन व्यवस्थाओं का खर्च बहुत अधिक होगा, तो पूरी परियोजना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रह पाएगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

सदाचार और सरलता के साथ जीवन जिएं

अध्यात्म
रामचंद्र डोंगरे

संसार में इतने आकर्षण बढ़ रहे हैं कि मन को पवित्र रखना कठिन हो गया है। किसी पर दृष्टि डालने से पहले विचार करें, मैं जिस दृष्टि से देखता हूं, वह कैसी है? मन और दृष्टि की दुर्बलता सहज मानवीय स्वभाव है। मनुष्य को इसी दुर्बलता पर विजय पानी है। इसके लिए सहज और सरल जीवन जीते हुए मन और दृष्टि को पवित्र रखना है।

परमात्मा के चौबीस अवतार हैं। सारे अवतारों की लीला का संवरण हुआ, पर नर-नारायण भगवान का तिरोभाव नहीं हुआ। भरतखंड के स्वामी नर-नारायण देव हैं। प्रभु नर-नारायण ने तपस्या का आदर्श बताया है। कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, फिर भी तप करता हूं।

अवतारों में सनत्कुमार ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध करो।

वराह भगवान संतोष के स्वरूप हैं। जो स्थिति रहे, उसी में संतोष मानो।

नारदजी भक्ति के स्वरूप हैं।

नर-नारायण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप हैं। भगवान की प्रतिष्ठा करना कठिन नहीं है, पर उन्हें अखंड रखना कठिन है।

शुकदेवजी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है, इसलिए वे उत्तम वक्ता हैं। व्यासजी और नारदजी में वैराग्य का अंश कुछ कम है। वे समाज सुधारक हैं। जो समाज का चिंतन करते हैं, उनमें थोड़ा अभिमान भी आ जाता है। वक्ता में पूरा वैराग्य नहीं हो, तो वह मध्यम कोटि का वक्ता है। किसी को छोटा समझने का नाम ज्ञान नहीं है। सबमें प्रभु का दर्शन करना ही ज्ञान है।

इच्छाओं पर नियंत्रण रखें

शुकदेवजी के दर्शन मात्र से अप्सराओं को विलासी जीवन से घृणा हो गई थी। शुकदेवजी ऐसे निर्विकार हैं कि उनके दर्शन से काम का नाश होता है।

जब तक कुछ करने की इच्छा रहती है, तब तक मन स्थिर नहीं होता। कुछ करने की वासना रहने तक परमात्म-रस का आनंद नहीं मिलता।

शुकदेवजी महाराज प्रवचन से ज्ञान देते हों, ऐसी बात नहीं है। उनके दर्शन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाज-सुधारक की आवश्यकता होगी, तो ईश्वर किसी को भेजेगा। दुर्योधन को समझाने के लिए श्रीकृष्ण ने अनेक प्रयत्न किए थे, पर क्या उसमें सुधार हुआ?

जिसकी कथनी और करनी एक है, वह श्रेष्ठ

वक्ता है। जो कहता तो है, पर जीवन में उतारता नहीं, उसकी वाणी में शक्ति नहीं आती। ज्ञान जब तक शब्दात्मक रहेगा, तब तक भार है। पर जब जीवन में उसे क्रियात्मक रूप में उतारते हैं, तो वह भारहीन हो जाता है।

शुद्ध मन और पवित्र दृष्टि रखें

चरणामृत पिपासा शांत करने के लिए नहीं है। उसे तो आचमन रूप में ही लो। इसी प्रकार सेवा करने के बाद आनंद की अनुभूति न हो, तो समझना चाहिए कि कहीं कमी है। सेवा करते हुए जिसे थकावट आए, झुंझलाहट आए, तो मनुष्य सेवा की बेगार उतारता है। मन को भगवान में लगाए रखना बड़ा कठिन है। सेवा में भी लगाए रखना बड़ा कठिन है। मन जितना शुद्ध होगा, सेवा में उतना ही आनंद मिलेगा।

संसार में इतने आकर्षण बढ़ रहे हैं कि मन को पवित्र रखना कठिन हो गया है। किसी पर दृष्टिपात करने के पहले विचार करो कि मैं जिस दृष्टि से देखता हूं, वह कैसी है? मन को शुद्ध रखना है, तो आंखों को पवित्र रखना होगा।

वंदन से प्रसन्न होते परमात्मा

सुखी रहना है, तो बहुत स्वतंत्रता नहीं लो। जो स्वतंत्र हैं, वे भी माता-पिता के अधीन हैं। वैष्णव कोई भी काम ठाकुरजी की आज्ञा लेकर ही करते हैं। भगवान के अधीन रहोगे, तो कल्याण करने हेतु वह तुम्हारे बंधन में आ जाएगा। वंदन भगवान को बंधन में डालता है। जो वस्तु से प्रसन्न होता है, वह जीवात्मा है। जो वंदन से प्रसन्न हो, वह परमात्मा है।

जो अति सुखी होता है, वह सब कुछ भूल जाता है। जीवन में एकाध दुख का आना जरूरी है। दुख में अनुभव होता है कि प्रभु के बिना मेरा कोई नहीं है। महात्मागण दुख को गुरु मानते हैं। जिस जीव को अपनी ओर खींचना होता है, उस जीव को परमात्मा बड़ा दुख देते हैं। भगवान शरीर का सौंदर्य नहीं देखते, स्वभाव की सुंदरता देखते हैं। आंखों में प्रेम रखो। आंगन में आने वाले का सत्कार करो, चाहे बैरी ही क्यों न हो। आंगन में आए हुए भिखारी को यदि कुछ नहीं मिलता है, तो वह घर का पुण्य ले जाता है।

भक्ति से मुक्ति

मरण और प्रयाण में अंतर है। बिस्तर पर दुखी होकर मरना 'मरण' है। परमात्मा की आरती उतारकर देह का त्याग 'प्रयाण' मंगल प्रयाण है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। हमेशा जप नहीं करोगे, तो मन संसार का चिंतन करेगा। एक बार मन के बिगड़ने पर उसको सुधारना कठिन है। आचार बिगड़ने से विचार बिगड़ते हैं। विचार बिगड़ने से वाणी बिगड़ती है। वाणी बिगड़ने से पुरुषार्थ बिगड़ता है। सदाचार की मर्यादा का जितना पालन करोगे, बुद्धि उतनी ही पवित्र होगी।

अंत समय में ज्ञान धोखा दे सकता है, पर भक्ति तो मरण सुधारती है। सुख और दुख दोनों में प्रभु का स्मरण करो। भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। कदाचित कोई दुख आ पड़े, तो धीरज रखो। प्रभु का साथ नहीं छोड़ो।

विचार

कभी-कभी खुद पर भी हंसना चाहिए

विडंबना न केवल दूसरों को ऊपर उठाने और प्रसन्न करने के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी एक औषधि है, क्योंकि स्वयं का उपहास करना आत्ममुग्धता के प्रलोभन पर विजय पाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आत्ममुग्ध लोग लगातार दर्पण में स्वयं को देखते रहते हैं। स्वयं का रंग-रोगन करते हैं, स्वयं को निहारते हैं, लेकिन दर्पण के सामने सबसे अच्छी सलाह है, स्वयं पर हंसना। यह हमारे लिए अच्छा है।

यह उस चीनी कहावत को सत्य सिद्ध करता है, जिसमें कहा गया है कि संसार में दो तरह के ही पूर्ण लोग होते हैं: जो मर चुके हैं और जिनका अभी जन्म नहीं हुआ। स्वयं पर हंसना सीखना उपहास से बचने का मार्ग है और उपहास से वापस लौटना संभव नहीं है। अगर आपको चिंता है कि लोग कल आप पर हंसेंगे, तो आज ही स्वयं पर हंसिए।

इस मामले में चर्च के पास चुटकुलों और व्यंग्य श्रेणियों की एक अनौपचारिक, लेकिन लंबी शृंखला है, जो इससे व्यक्तियों पर निर्भर करती है। साथ ही ये, यह भी दर्शाती है कि स्वयं पर हंसना हमें आत्ममुग्ध होने से बचाता है।

उदाहरण के लिए, मुझे एक चुटकला स्मरण हो रहा है, जो कैंटरबरी के पूर्व आर्कबिशप जस्टिन वेल्बी ने मुझे वेटिकन में एक बैठक में बताया था। उन्होंने पूछा, 'क्या आप जानते हैं कि एक लिथुर्जिस्ट (लिथुर्जिस्ट: ईसाइयों में धार्मिक कृत्य कराने वाले) और एक आतंकवादी के बीच क्या अंतर है?' फिर उन्होंने कहा, 'आतंकवादी के साथ आप सौदेबाजी कर सकते हो...' उनकी इस बात से मैं जोर से हंस पड़ा था।

जेसुइट्स के बारे में या स्वयं उनके द्वारा कहे गए चुटकुलों की अपनी अलग ही श्रेणी है, जिनकी तुलना शायद केवल इटली में कैराबिनिएरी या यहूदी माताओं के बारे में यिडिश हास्य में कहे गए चुटकुलों से की जा सकती है।

जहां तक आत्ममुग्धता के संकट की बात है, जिसे आत्म-व्यंग्य की उचित खुराक से टाला जा सकता है। मुझे एक घमंडी जेसुइट की कहानी याद

है, जो हृदय रोग से ग्रस्त था और उसे अस्पताल में उपचार करवाना पड़ा था। ऑपरेशन रूम में जाने से पहले उसने ईश्वर से पूछा, 'लॉर्ड, क्या मेरा समय आ गया है?'

ईश्वर ने उत्तर दिया, 'नहीं! तुम कम-से-कम चालीस वर्ष और जिओगे।' ऑपरेशन के बाद उसने अपने जीवन को जमकर जीने का निर्णय किया और हेयर ट्रांसप्लांट, फेसलिफ्ट, लिपोसक्शन तो करवाया ही, भौंहों और दांतों को भी दुरुस्त कराया। संक्षेप में यह कि वह बिल्कुल ही बदल गया। अस्पताल के बाहर ही उसे एक कार ने टक्कर मार दी और उसके प्राण पखेरू उड़ गए। जैसे ही उसको ईश्वर के सामने लाया गया, उसने विरोध किया, 'लॉर्ड, आपने तो कहा था कि मैं और चालीस वर्ष जिऊंगा!' ईश्वर ने उत्तर दिया, 'ऊप्स, सॉरी! मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।'

-जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो पोप फ्रांसिस

(साभार: 'पोप फ्रांसिस की आत्मकथा: आशाओं की एक विरासत', अनुवाद: मंजीत ठाकुर, मंजुल प्रकाशन, नोएडा)

सप्ताह के व्रत-त्योहार

21 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक

21 जुलाई (मंगलवार): आषाढ़ शुक्ल अष्टमी रात्रि 05.17 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। भद्रा सायं 04.40 मिनट तक। श्री दुर्गाष्टमी।

22 जुलाई (बुधवार): आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि (दिन-रात)। भढली नवमी। गुप्त नवरात्र समाप्त।

23 जुलाई (गुरुवार): आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि प्रात: 07.04 मिनट तक। शक श्रावण प्रारंभ।

24 जुलाई (शुक्रवार): आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि प्रात: 09.13 मिनट तक। भद्रा रात्रि 10.24 मिनट से। गंडमूल रात्रि 04.37 मिनट से।

25 जुलाई (शनिवार): आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रात: 11.35 मिनट तक। भद्रा प्रात: 11.35 मिनट तक। हरिशयनी एकादशी व्रत। चातुर्मास्य व्रत नियमादि प्रारंभ। श्री विष्णु शयनोत्सव। गंडमूल विचार।

26 जुलाई (रविवार): आषाढ़ शुक्ल द्वादशी तिथि दोपहर 01.58 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी तिथि। प्रदोष व्रत। गंडमूल विचार।

27 जुलाई (सोमवार): आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि सायं 04.15 मिनट तक पश्चात चतुर्दशी तिथि। गंडमूल प्रात: 10.29 मिनट तक।

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

बोधकथा

पुरुषार्थ से ही बनता भाग्य

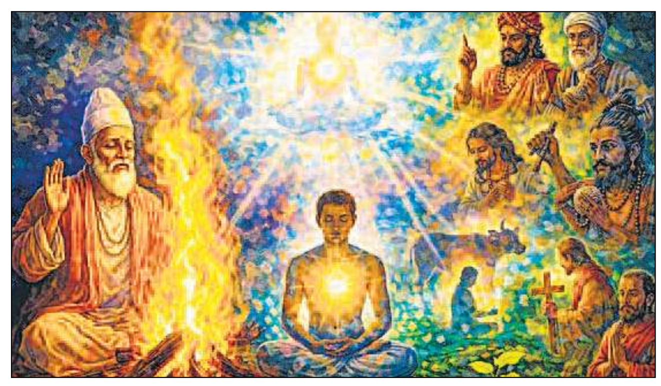

एक बार एक ऋषि भगवान के पास किसी कार्य से गए। उस समय भगवान मनुष्यों का भाग्य लिख रहे थे। ऋषि ने सोचा कि क्यों न अपने कुछ शिष्यों का भाग्य पूछ लूं। इससे मैं उनका मार्गदर्शन सही ढंग से कर सकूंगा।

जब ऋषि ने भगवान से अपने मन की बात कही, तो भगवान ने उत्तर दिया, 'ऋषिवर! यह सही है कि जिन लोगों का भाग्य लिखा जा रहा है, उनमें आपके कुछ शिष्य भी हैं, किंतु इस भाग्य को जानने पर मैंने रोक लगा रखी है।' ऋषि ने पूछा, 'भगवन भाग्य जानने पर रोक क्यों है?' भगवान ने कहा, 'जानने में अनर्थ ही अनर्थ है। किसी को अच्छा भाग्य बताया जाएगा, तो उसका पुरुषार्थ घट जाएगा। वह अहंकारी और आलसी बन जाएगा। वह सोचने लगेगा कि यह तो मेरे भाग्य में लिखा है, सो मिल ही जाएगा। फिर मैं काम क्यों करूं?

यदि किसी का भाग्य खोटा बताया जाएगा, तो वह व्यक्ति इस बात को जानकर निराश हो जाएगा कि मेरे भाग्य में निराशा और असफलता के सिवा कुछ है ही नहीं। वह किसी काम को करने से पहले ही सोचेगा कि जब मेरे भाग्य में यह मिलना नहीं लिखा है, तो फिर मैं इसे क्यों करूं? इस तरह जो व्यक्ति भाग्य का लेख अपने पक्ष में जान लेगा, वह भाग्यवादी बन जाएगा और इस तरह वह पुरुषार्थ विरोधी भी हो जाएगा। भाग्य अच्छा है या बुरा- दोनों ही बातें जानना मनुष्य के हित में नहीं है और इसी कारण मैंने इस रहस्य को अपने पास ही छिपा रखा है।'

ऋषि ने पूछा, 'भगवन! कृपया इतना और बता दीजिए कि क्या भाग्य-लेख मिट भी सकता है?' इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और बोले, 'जब तुम जानते ही नहीं कि भाग्य का लेख क्या है, तो उसके मिटने या बने रहने की बात कहां से आ गई। इसे यों समझो कि तुम अपने पुरुषार्थ से भाग्य का लेख लिखते हो और मिटाते हो। तुम कोई काम करते हो और उसमें सफलता न मिलने पर भाग्य को दोष देते हो- 'मेरे तो भाग्य में ही नहीं है' या 'मेरा तो भाग्य ही खराब है।' जब पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती है, तब यह याद करना भूल जाते हो कि भाग्य में तो सफलता लिखी थी, किंतु इतने प्रयत्नों के बाद। इसका अर्थ हुआ कि भाग्य परिवर्तनशील है, पत्थर की लकीर नहीं?'

भगवान ने कहा, 'मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही भाग्य बनाता और बिगाड़ता है।'

भाग्य की निर्भरता हमें कर्मठ नहीं, अकर्मण्य बनाती है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य सोया रहता है और हिम्मत बांधकर खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है।

-डॉ. हरिकृष्ण देवसरे

वक्री शनि से बदलेगी छवि, मिलेगी कामयाबी

आस्था-अनास्था
डॉ. संजीव कुमार शर्मा

शनि के वक्री होने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे? -राम, आगरा

शनि ग्रह 27 जुलाई, 2026 को मीन राशि में वक्री यानी उल्टी चाल से 138 दिनों चलेंगे। यह 11 दिसंबर, 2026 को मार्गी अर्थात सीधी चाल में हो जाएंगे। शनि के वक्री होने के कारण बारह राशियों पर पड़नेवाला प्रभाव:

मेष: व्यावसायिक मामलों में कठिन परिश्रम। व्यावसायिक मामलों में सुनहरा अवसर परिवर्तन का कारक बनेगा।

वृष: निजी और व्यावसायिक मामले सुलझेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

मिथुन: आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे।

कर्क: परिस्थितियों को सहजता से संभालेंगे। ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करेंगे।

सिंह: कार्यक्षेत्र में सावधान रहें। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें।

कन्या: आपकी नई सोच आपको प्रसिद्धि देगी। अपने मूल्यों से कोई समझौता नहीं करेंगे।

तुला: भावनात्मक उथल-पुथल

रहेगी। कार्यक्षेत्र में अत्यधिक प्रतिक्रिया देने से बचें। व्यापार में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक: सफलता की सीढ़ी पर कदम बढ़ाएंगे। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं आगे बढ़ेंगी।

धनु: किसी भी तरह के निवेश के प्रति सतर्क रहें। कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उस पर उचित सोच-विचार कर लें।

मकर: शांति और सद्भाव का समय है। कार्यक्षेत्र में सहज और रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा।

कुंभ: जीवन शैली और बाहरी छवि में सकारात्मक बदलाव आएगा। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे उतार-चढ़ाव ठीक होंगे।

मीन: रिश्तों में सकारात्मक खुशियां आएंगी। करियर में नए मौके आएंगे, जो खुशियां लेकर आएंगे। अवसर का लाभ उठाएं।

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें: धर्मक्षेत्र, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष: कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु खर्च भी बढ़ेंगे।

वृष: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता बनाए रखें। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। खर्च बढ़ेंगे। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन: मन प्रसन्न रहेगा। माता का सान्निध्य मिलेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार के लिए पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

कर्क: मन अशांत रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। माता-पिता से धन मिल सकता है। किसी मित्र का सहयोग भी मिलेगा।

सिंह: मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पिता का सान्निध्य मिलेगा। कारोबार के लिए किसी मित्र के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। लाभ के अवसर मिलेंगे।

कन्या: मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

तुला: मन परेशान रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।

धनु: आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध व वाद-विवाद से बचें। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ सकते हैं।

मकर: संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। पिता व संतान की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। किसी संपत्ति से आय में वृद्धि हो सकती है।

कुंभ: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। विदेशी कारोबार से आय में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।

मीन: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

21 जुलाई, मंगलवार, **शक संवत्**: 30 आषाढ़ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग**: 06 श्रावण मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 06 सफर, 1448, **विक्रमी संवत्**: आषाढ़ शुक्ल अष्टमी रात्रि 05.17 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। साध्य योग, विष्टि (भद्रा) करण सायं 04.40 मिनट तक। चंद्रमा कन्या राशि में प्रात: 07.55 मिनट तक उपरांत तुला राशि में। **सूर्य दक्षिणायन**। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा सायं 04.40 मिनट तक। श्री दुर्गाष्टमी।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

फार्म हाउस संबंधी वास्तु उपाय:

- फार्म हाउस पूर्व मुखी और घर पश्चिम दिशा में ठीक होता है। फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर केवल कॉलम खड़े हों और मुख्य द्वार नहीं लगा हो, तो गलत होता है। किवाड़ के बिना द्वार अशुभ होता है। वहां गेट लगवाएं।
- अगर आउट हाउस बनवाएं और वह पूर्व दिशा में हो, तो उसका मुख्य घर से ऊंचा होना गलत होगा, क्योंकि वह पूर्व दिशा में है। यह समस्या पैदा करता है। इसका उपाय है कि पश्चिम दिशा में आउट हाउस के मुकाबले कोई ऊंचा निर्माण करवाना लाभप्रद रहता है।
- फार्म की उत्तर पूर्व दिशा में एक लोटस पॉन्ड बनवाना ठीक रहता है।

वर्ग पहेली: 8396

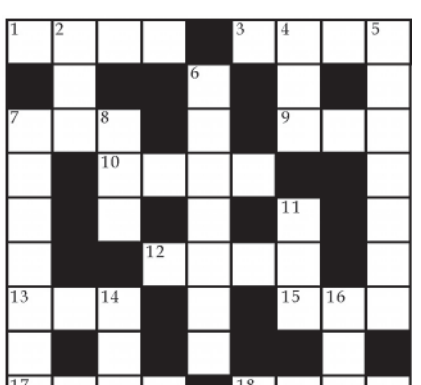

बाएं से दाएं

1. बिना विलंब किए; तत्काल; फौरन; शीघ्रतापूर्वक (4)
3. मोर के पंख से बना पंखा (4)
7. चारों ओर से घिरा हुआ मैदान; घेरा; बाड़ा (3)
9. पीलवान का पैर रखने के लिए हाथी के गले में लगी रस्सी; हाथ में हथेली के ऊपर का भाग; करमूल; पाणिमूल; मणिबंध (3)
10. उक्ति; कथन; कही हुई बात; मसल; लोकोक्ति (4)
12. पैर फैला कर सोना; फैलना; विस्तृत होना (4)
13. मांगने वाला; याचना करने वाला; भिक्षुक (3)
15. साल का बारहवां भाग; मास; माह (3)
17. डरना; भयभीत होना; सिमटना (4)
18. बिना थके; बिना रुके हुए; अनवरत; अविराम; तारतम्यपूर्वक; निरंतर; सतत (4)

ऊपर से नीचे

2. वियोग; गडरियों द्वारा गाया जाने वाला गीत (3)
4. धोने वाला; धोबी (3)
5. खटाई में डाला जाना; दुविधा में पड़ना; मामला लटक जाना; लंबित पड़ना (3,1,3)
6. एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक राज्य करने वाला सम्राट; महाराजाधिराज (4,3)
7. बुद्धि व धन की तुलना करने वाली एक लोकोक्ति (2,2,1,2)
8. क्षमता; बल; शक्ति; सामर्थ्य (3)
11. अज्ञात; अप्रसिद्ध; अविख्यात; नामहीन; बिना नाम का (3)
14. शपथ; सौगंध (3)
16. अभाव; कमी; तुच्छता; बुराई; निकृष्टता (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली: 8395

1 प्र	या	2 स	र	त		3 उ		4 अ
		र			5 रो	ब	दा	ब
6 त	था	क	थि	7 त		र		त
क		ना		ला		ना		ब
8 रा	ख		9 म	शी	न		10 पं	क
र		11 प		ले		12 अ		र
क		रा		13 ना	क	च	ढ़ा	ना
14 र	त	ज	गा			र		
ना		य		15 रं	ग	ज	म	ना

सुडोकू: 8350

* आसान

7								9
		9	8		4	5		
3			7		2			8
		7	5		3	2		
	3			2			5	
		8	6		9	4		
1			9		6			4
		4	2		8	1		
8								5

खेलने का तरीका: दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू: 8349

3	6	5	2	7	1	8	4	9
7	1	9	8	4	5	3	2	6
4	8	2	9	6	3	1	7	5
6	4	1	7	2	9	5	3	8
2	5	7	3	1	8	9	6	4
8	9	3	6	5	4	7	1	2
1	3	4	5	9	2	6	8	7
9	2	6	1	8	7	4	5	3
5	7	8	4	3	6	2	9	1

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार, 21 जुलाई, 2026

दैनिक जागरण

आत्ममंथन से ही आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है

दिशाहीन आयोजन

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की एक आहत करने वाली टिप्पणी की प्रतिक्रिया से उपजी काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च के समय दिल्ली में जिस तरह हंगामा और हिंसा हुई, उसकी आशंका पहले से ही थी, क्योंकि इस कथित राजनीतिक दल का धरना-प्रदर्शन पूरी तरह दिशाहीन था। सच तो यह है कि इस समूह का गठन ही हास-परिहास का परिणाम था। उसे खुद के एक राजनीतिक ताकत बन जाने का भ्रम इसलिए हो गया, क्योंकि इंटरनेट मीडिया पर उसके करोड़ों फालोअर्स हो गए थे। इस भ्रम ने ही एक दिशाहीन आंदोलन की नींव रखी। सीजेपी इसका उदाहरण है कि आनलाइन प्रसिद्धि धरातल पर कोई असर नहीं दिखाती। सीजेपी का धरना-प्रदर्शन न केवल मोदी सरकार के हर किस्म के विरोधियों और खासकर आंदोलनजीवियों का आसान मंच बन गया था, बल्कि हर कोई उसे अपनी तरह से भुनाने में लगा हुआ था। विपक्षी दलों ने भी उसके मंच का उपयोग बहती गंगा में हाथ धोने वाले अंदाज में ही किया। यह किसी से छिपा नहीं कि उसके मंच से किस तरह नीट पेपर लीक के साथ देश-दुनिया के अनगिनत मसलों को उठाया जा रहा था। सीजेपी का आयोजन विश्वसनीयता इसलिए नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि इस समूह के जो कर्ता-धर्ता इसके लिए व्यग्र दिख रहे थे कि उनके साथ आ गए लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपनी जान जोखिम में डालकर भी भूख हड़ताल जारी रखें, वे स्वयं अनशन करने और यहां तक कि धरना स्थल पर निरंतर उपस्थित रहने के लिए भी तैयार नहीं थे।

सीजेपी के संसद मार्च में भीड़ इसलिए जुट गई, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन यह भीड़ इसलिए पूरी तरह अनियंत्रित थी, क्योंकि कोई भी उसे दिशा देने वाला नहीं था। क्या यह विचित्र नहीं कि जब सीजेपी नेता अपना अनशन खत्म करने की घोषणा कर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे थे तो संसद मार्च में शामिल भीड़ संसद में घुसने की चेष्टा कर रही थी। आखिर इससे क्या हासिल होने वाला था? इस चेष्टा के बाद वह सब कुछ होना ही था, जो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। इसे रोका जा सकता था, यदि सीजेपी नेता किसी सुविचारित रणनीति के तहत अपना धरना-प्रदर्शन कर रहे होते। उन्हें यह आभास होना चाहिए था कि उनका अपने समर्थकों पर कोई नियंत्रण नहीं। चूंकि संसद के प्रत्येक सत्र के पहले ऐसा कुछ होता है, जिससे विपक्ष को पहले ही दिन सदन में हंगामा करने का अवसर मिल जाता है, इसलिए सरकार को भी चाहिए था कि वह संसद मार्च के पहले ही सीजेपी के नेताओं से संवाद-संपर्क की पहल करती। आखिर जो बातचीत अब हुई, वह पहले क्यों नहीं हो सकती थी?

विकास का नया रास्ता

हिमाचल प्रदेश में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। हर वर्ष मानसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ के कारण जानमाल की हानि हो रही है। डा. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक संस्थान की रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है कि आपदा के लिए केवल प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। अनियोजित शहरीकरण, अवैज्ञानिक ढंग से पहाड़ों का कटान, अनियंत्रित आधारभूत ढांचा निर्माण और पर्यटन का बढ़ता दबाव आपदाओं की गंभीरता बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं। सर्वविदित है कि जलवायु परिवर्तन ने हिमालयी क्षेत्रों के मौसम चक्र को बदल दिया है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर और बढ़ती ग्लेशियल झीलें भविष्य में गंभीर खतरे की चेतावनी दे रही हैं। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हिमाचल को और भी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में सुझाई स्माल इज ब्यूटीफुल अवधारणा दूरदर्शी समाधान साबित हो सकती है। पारंपरिक काष्ठकुणी शैली के भवन, ढलानों की सुरक्षा के लिए बायो-इंजीनियरिंग तकनीक व पर्यटन स्थलों की कैरिंग कैपेसिटी तय करना पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। विकास का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य भी है। विकास का ऐसा माडल अपनाना होगा, जो पर्यावरण के अनुकूल हो और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे सके।

> हिमाचल को ऐसा मार्ग चुनना होगा, जिसमें विकास के साथ प्रकृति का संरक्षण भी हो

तीन माह में बदल गई संसद की तस्वीर

राजकुमार सिंह

पिछले संसद सत्र में मोदी सरकार को परास्त करने में एकजुट एवं आक्रामक रहे विपक्षी दल आज अपनी एकता और रक्षा, दोनों के संकट से दो-चार हैं

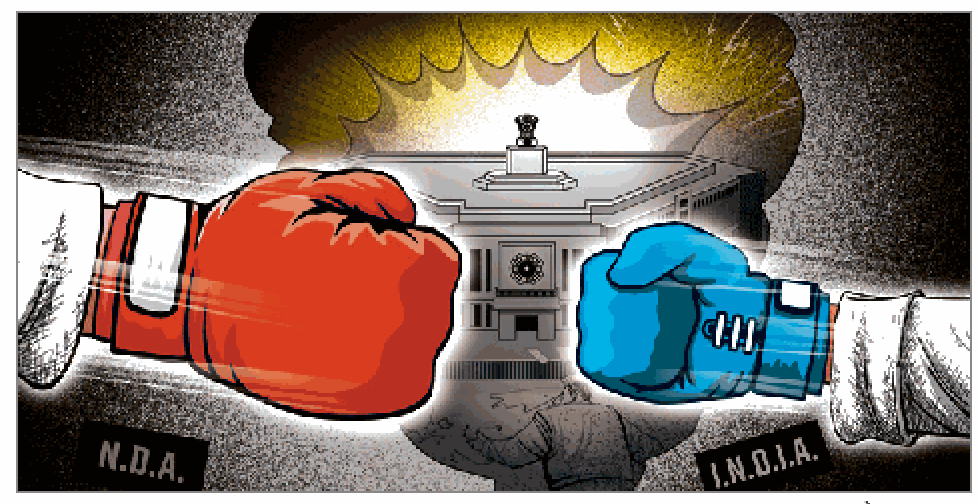

अवधेश राजपूत

नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा को सबसे बड़ा चुनावी झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा। 2019 में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 पर सिमट गई तो इसी साल बजट सत्र में उसे पहली बार संसद में विधेयक गिरने से शर्मसार होना पड़ा। परिसीमन विधेयक 54 वोटों की कमी से लोकसभा में गिर गया, लेकिन अब जबकि संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, तब परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। 2024 में अपने बेहतर चुनावी प्रदर्शन से उत्साहित विपक्षी गठबंधन को बीच-बीच में आंतरिक संकटों का सामना भी करना पड़ा, पर परिसीमन विधेयक गिरा कर मोदी सरकार को तगड़ा झटका जोर से ही देने से उसके हौसले फिर से बुलंद हो गए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरने तक विपक्ष के हौसले बुलंद थे, लेकिन परिणामों के बाद देश की राजनीति की तस्वीर और तेवर तेजी से बदले। भाजपा ने जहां बंगाल की सत्ता हासिल कर असंभव को संभव कर दिखाया, वहीं विपक्ष उसके बाद से एक के बाद एक झटके झेल रहा है।

गठबंधन के तौर पर विपक्ष केरलम के चुनाव परिणाम पर संतोष कर सकता है कि सत्ता एलडीएफ से यूडीएफ को ही हस्तांतरित हुई, लेकिन तमिलनाडु में हार के बाद तेजी से बदले समीकरणों में द्रमुक की विपक्षी गठबंधन से विदाई उसके लिए बड़ा झटका है और भाजपा के लिए मुंहमांगी मुराद। बंगाल में भाजपा को भले ही अपनी जीत का भरोसा रहा हो, पर ममता की हार की उम्मीद ज्यादातर लोगों को नहीं थी, लेकिन नतीजों ने सबको चौंकाया। कभी न कभी सत्ता से विदाई सबकी होती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में जैसा बिखराव हुआ, वह अप्रत्याशित है। इसी बिखराव ने देश की राजनीति की तस्वीर और तेवर बदलने की भूमिका भी लिखी। कांग्रेस से अलग अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाकर ममता ने जिस तरह साढ़े तीन दशक पुरानी वाम मोर्चा सत्ता को उखाड़ फेंका, वह उनके राजनीतिक कौशल और जुझारूपन की कहानी है। जब सत्ता खिसकते ही ऐसी नेत्री के सांसदों-विधायकों में भगदड़ मच गई, तब तमिल राजनीति में दशकों बाद तीसरा कोण उभरने से स्तब्ध द्रमुक तथा पहले भी विभाजन झेल चुकी शिवसेना और एनसीपी में पालाबदल पर ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

तृणमूल के 80 में से 60 विधायकों और 28 लोकसभा सदस्यों में से 20 की बगावत बहुत कुछ कहती है। बंगाल के राजनीतिक मिजाज और तृणमूल में बिखराव से ममता की सत्ता में वापसी आसान नहीं लगती। फिर अभी लोकसभा चुनाव लगभग ढाई और विधानसभा चुनाव पांच साल दूर हैं। इतने लंबे समय तक सड़क पर रहकर अगला चुनाव जीतना भी दूभर हो जाएगा, जबकि पालाबदल से सत्ता सुख की संभावनाएं हैं। तृणमूल छोड़ने वाले तीन राज्यसभा सदस्यों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दे ही दिया। चौथे का भी नंबर लग ही जाएगा। खुद को असली तृणमूल बता रहे 60 बागी विधायकों के नेता ऋतब्रत बनर्जी की मंजिल नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद दूर लगती है, लेकिन एक अल्पज्ञात क्षेत्रीय दल एनसीपीआइ में शामिल हो गए 20 सांसदों में से एक या दो को मोदी मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल में मौका मिल सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दूसरी बार बगावत के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में गए छह लोकसभा सदस्यों को सत्ता मिले या न मिले, पर उसका सान्निध्य तो तय है ही। शून्य सांसद-विधायक वाली एनसीपीआइ को अचानक 20 लोकसभा सदस्य मिल गए तो सात लोकसभा सदस्यों वाली शिवसेना का कुनबा रातोंरात 13 तक पहुंच गया। कोई नहीं बता सकता कि शरद पवार की एनसीपी के आठ लोकसभा सदस्य कब और किस रास्ते से राजग का कुनबा बढ़ा दें। भाजपा चाहती है कि पहले एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो और फिर वह राजग का हिस्सा बनें। एनसीपी का अजीत पवार गुट फिलहाल राजग में है। अजीत के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री भी हैं। दोनों गुटों के विलय की चर्चाएं विमान दुर्घटना में अजीत की मृत्यु के पहले भी चल रही थीं। अब सुनेत्रा और उनके राज्यसभा सदस्य पुत्र पार्थ को आशंका है कि विलय के बाद वे शरद पवार और सुप्रिया सुले की राजनीतिक बिसात के सामने टिक नहीं पाएंगे, पर उनके ज्यादातर विधायक विलय के पक्षधर हैं। जो भी हो, जिस मोदी सरकार को पराजित करने के लिए विपक्षी दल आक्रामक नजर आ रहे थे, आज वे एकता और रक्षा, दोनों के संकट से रूबरू हैं।

देश के राजनीतिक परिदृश्य, खासकर संसद की तस्वीर में यह बदलाव महज तीन महीने में आया है। एक और बड़ा बदलाव यह भी है कि 22 लोकसभा सदस्यों वाले द्रमुक ने विपक्षी खेमे से अलग बैठने का फैसला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्धव की शिवसेना के छह सदस्यों के शिंदे की शिवसेना में शामिल होने को मान्यता देने के साथ ही लोकसभा की संख्याबल में बड़ा बदलाव आ गया है। तृणमूल से बगावत कर एनसीपीआइ में शामिल हुए 20 सांसदों को भी अलग संसदीय पहचान मिल चुकी है। इस बड़े बदलाव के मूल में पिछले सत्र में विधेयक गिरने का बदला लेने के साथ ही विपक्ष को सबक सिखाने की रणनीति समझ पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि मानसून सत्र के घोषित एजेंडा में परिसीमन विधेयक नहीं है, पर उसे पारित करवाने की नए सिरे से कोशिशों की संभावनाएं नकारी नहीं जा सकतीं। 37 सांसदों वाली सपा को लुभाने की कोशिशें अभी तक सफल नहीं दिखतीं, लेकिन सरकार दो-तिहाई बहुमत के इतना नजदीक अवश्य पहुंच गई है कि मतदान से अनुपस्थिति और वाकआउट सरीखे विकल्पों से सदन में वह आंकड़ा हासिल कर सके। परिसीमन विधेयक के विरोध में दक्षिण के राज्यों की गोलबंदी कर रहे द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन अब सभी राज्यों में 50 प्रतिशत सीटों की वृद्धि के प्रविधान के साथ विधेयक के वैसे मुखर विरोधी नजर नहीं आते। दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। इसलिए दो-तिहाई आंकड़े के प्रति आश्वस्त हुए बिना मोदी सरकार परिसीमन विधेयक दोबारा तो संसद में नहीं लाएगी, लेकिन उसने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में अवश्य ला दिया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

और सुगम होगी छोटे उद्यमों की राह

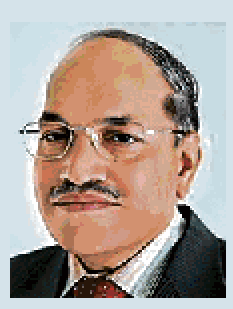

डा. जयंतीलाल भंडारी

देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान होने के बावजूद एमएसएमई को कई कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है

सरकार संसद के इसी सत्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास (संशोधन) विधेयक 2026' लाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के एमएसएमई के लिए बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप नीतियों और नियमों को कारगर बनाना है। इसके साथ ही कारोबारी सुगमता को बढ़ाना, लंबित भुगतानों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना और एमएसएमई क्षेत्र के लिए मध्यस्थता के फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। राज्य अधिक से अधिक 'सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद' (एमएसईएफसी) गठित कर सकें, इसके लिए विधेयक में अनुकूल प्रविधान किए गए हैं।

देश के आर्थिक ढांचे में एमएसएमई का योगदान महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक देश में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 7.86 करोड़ से अधिक है। ये उद्योग देश के दूर-दराज के कस्बों और छोटे शहरों में फैले हुए हैं, जिससे देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव हो पा रहा है। कृषि के बाद यह क्षेत्र भारत में आजीविका का दूसरा सबसे बड़ा आधार है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जहां हर साल लाखों नए युवा रोजगार की तलाश करते हैं, वहां बड़े उद्योगों की तुलना में ये छोटे उद्योग बहुत कम पूंजी में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से देश में लगभग 32.82 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इन उद्योगों की हिस्सेदारी लगभग 31.1 प्रतिशत है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश की कुल कमाई का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इन छोटे कारखानों, दुकानों और स्थानीय निर्माण इकाइयों से आता है। कुल विनिर्माण में इन उद्योगों की भागीदारी करीब 35.4 प्रतिशत तो निर्यात में योगदान लगभग 48.58 प्रतिशत है।

देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान होने के बावजूद इन छोटे उद्योगों को चलाने वाले उद्यमियों को कई कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। इनमें कार्यशील पूंजी और कोष की किल्लत प्रमुख है। छोटे उद्यमियों के पास सीमित परिसंपत्तियां होती हैं। बैंकों से ऋण लेते समय उन्हें लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे समय पर पूंजी न मिलने के कारण कई बार उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फंसा हुआ पैसा और भुगतान में देरी भी इस क्षेत्र की गंभीर समस्या है। जब छोटे उद्योग बड़ी कंपनियों या सरकारी विभागों को माल की आपूर्ति करते हैं तो उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता। नकदी के अभाव में वे न तो कच्चा माल खरीद पाते हैं और न ही कर्मचारियों को वेतन दे पाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में एमएसएमई जटिल कानूनी अड़चनों और मुकदमों के डर का सामना करते हैं। अनजाने में बहीखाते, कर दाखिल करने या किसी प्रशासनिक नियम के पालन में छोटी-मोटी चूक होने पर भी उद्यमियों को कानूनी कार्रवाई का डर सताता रहता है, जिससे वे खुलकर काम नहीं कर पाते। एमएसएमई के समक्ष आधुनिक तकनीक और बाजार की प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान दौर कंप्यूटर, आटोमेशन और एआइ का है। बड़ी कंपनियों के पास इन तकनीकों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रविधान होता है, जबकि छोटा उद्यमी महंगी तकनीक अपनाने में असमर्थ रहता है। इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है और वे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इन सभी चुनौतियों के मद्देनजर 'एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक, 2026' एक दूरगामी कदम है। पुराने नियमों में एमएसएमई की परिभाषा संकुचित थी। कारोबार या निवेश बढ़ते ही उद्योग इस श्रेणी से बाहर हो जाते थे और सरकारी लाभ बंद हो जाते थे। नए संशोधन में निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। इससे उद्यमी बिना किसी डर के अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। भुगतान में देरी से निपटने के लिए एक आधिकारिक आनलाइन विवाद निवारण प्रणाली और डिजिटल मध्यस्थता तंत्र को कानूनी ढांचा दिया जा रहा है। अब अदालतों के चक्कर काटे बिना डिजिटल माध्यम से तय समयसीमा के भीतर मामलों का निपटारा कर व्यापारियों को फंसा हुआ धन वापस दिलाया जाएगा। किसी विवरण को दाखिल करने में देरी या कागजी रिकार्ड में मामूली विसंगतियों जैसी मानवीय भूलों को भी अब आपराधिक मुकदमों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिससे कारोबारी सुगमता को वास्तविक बल मिलेगा। 'उद्यम आंकड़े' को केंद्रीय बैंकिंग प्रणालियों से जोड़ा जा रहा है। इससे बैंकों के लिए केवाईसी और आंकड़ों की सत्यता जांचना आसान हो जाएगा, जिससे कार्यशील पूंजी ऋण कुछ ही घंटों में स्वीकृत हो सकेंगे।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 10 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी स्वयं सरकार देगी, जिससे बैंक बिना झिझक उद्यमियों को ऋण दे सकेंगे। जब एमएमएमई को त्वरित ऋण मिलेगा, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी और तकनीकी रूप से वे सक्षम बनेंगे तो भारत के विनिर्म और सेवा क्षेत्र को एक अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी।

नए कानून से एमएसएमई के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। फाइल

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन-मृत्यु

जीवन और मृत्यु प्रकृति के दो शाश्वत सत्य हैं। जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन इस संसार से विदा होगा, फिर भी मनुष्य ऐसे जीता है मानो उसे मृत्यु कभी स्पर्श नहीं करेगी। यही विस्मृति उसे सत्य से दूर ले जाती है। यदि मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अवश्यंभावी तो उसका दृष्टिकोण, व्यवहार और कर्म स्वतः बदलने लगेंगे। भारतीय दर्शन जीवन को केवल भोग का अवसर नहीं, बल्कि आत्मोन्नति की दुर्लभ साधना मानता है। भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष भी इस धरती पर आए, अपना कर्तव्य निभाया और मानवता को धर्म, करुणा तथा सदाचार का संदेश देकर चले गए। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि शरीर नश्वर है, किंतु श्रेष्ठ कर्म अमर होते हैं। जब मनुष्य धर्म, नैतिकता, अनुशासन और सद्भाव से विमुख होकर अधर्म, छल, हिंसा और अनैतिकता का मार्ग अपनाता है, तब वह अपने जीवन के साथ-साथ समाज और संस्कृति को भी विषाक्त करता है। वास्तविक दुर्भाग्य मृत्यु नहीं, बल्कि यह है कि अमूल्य मानव जीवन प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य आत्मकल्याण की ओर ध्यान न दे। वह शरीर की आवश्यकताओं में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर स्थित आत्मा का स्मरण ही नहीं कर पाता। जबकि जीवन का उद्देश्य केवल धन और प्रतिष्ठा अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना और ऐसे कर्म करना है, जो मृत्यु के बाद भी समाज के लिए प्रेरणा बने रहें।

हम मृत्यु से भयभीत होने के बजाय उसे जीवन का गुरु मानें। यही जीवन को सार्थक, संस्कृति को जीवंत और आत्मा को प्रकाशमय बनाता है। अंततः मनुष्य के साथ उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके कर्म ही चलते हैं। वही उसकी वास्तविक पहचान और अमरता का आधार होते हैं।

मुकेश ऋषि

भरोसा बढ़ाते न्यायिक फैसले

डा. मोनिका शर्मा

फिरोजाबाद के मामले में रिकार्ड समय में आया फैसला बताता है कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सकता है

देश में जघन्य घटनाओं में भी तारीख पर तारीख मिलने की लचरता न्यायिक व्यवस्था से भरोसा डिगाने की सबसे बड़ी वजह है। बावजूद इसके बच्चों और महिलाओं के साथ हुई बर्बर घटनाओं में भी वर्षों फैसले नहीं आते। हमारे यहां आपराधिक घटनाओं के अलावा वैवाहिक अलगाव से लेकर पारिवारिक और जमीन जायदाद के विवादों तक, हर तरह के केस लंबित मामलों की सूची का हिस्सा हैं।

ऐसे में त्वरित कार्रवाई के बाद हाल में आए दो न्यायिक निर्णय सराहनीय हैं। देश को झकझोरने वाली उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की घटना और पुणे के नसरापुर के जघन्य मामले में आए फैसले बताते हैं कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सकता है। ध्यातव्य है कि फिरोजाबाद की वारदात में डेढ़ साल के मासूम बच्चे की जान सड़क पर पटक-पटक कर ले ली गई थी। इस बर्बर हत्याकांड में महज छह दिन में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 13 गवाहों के बयान हुए और 40 दिन के भीतर जिला अदालत का निर्णय आया है। रिश्ते की भाभी के बच्चे को गली में ले जाकर आठ बार पटकने के बाद निर्दयता से मौत के घाट उतारने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे के नसरापुर में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में विशेष पाक्सो अदालत ने भी दोषी को फांसी की सजा दी है। यह फैसला भी मात्र 60 दिनों के रिकार्ड समय में 'रेयरेस्ट आफ रेयर' श्रेणी के तहत सुनाया गया।

असल में न्याय मिलने में हुई देरी भी एक तरह का अन्याय ही तो है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भयावह से भयावह आपराधिक घटनाओं में भी फैसला आने की कोई समय सीमा नहीं है। यह सुस्त प्रक्रिया हर स्तर पर कायम कानूनी व्यवस्था की लचर स्थितियों को भी सामने रखती है। इतना ही नहीं, वर्षों तक चलने वाले मामलों में लोगों के लिए नियमों-कानून की पेचीदगियों से गुजरना भी बहुत पीड़ादायी होता है। दुखद है कि कभी अपने अधिकार के लिए तो कभी अपराध से लड़ते हुए लोगों की पूरी उम्र बीत जाती है। बहुत से लोगों को तो दुनिया छोड़ देने तक भी न्याय नहीं मिलता। यहां तक कि कुत्सित अपराधों को अंजाम देने वाले भी वर्षों सजा नहीं पाते।

यह स्थिति आपराधिक मानसिकता के लोगों का दुस्साहस बढ़ाती है। वहीं कानूनी प्रक्रिया में उलझे परिचितों-अपरिचितों के हालात को देख-जान रहे अन्य नागरिक भी अपने साथ हुए हादसों की शिकायत करने से बचते हैं। बावजूद इसके दुनिया में सबसे ज्यादा लंबित अदालती मामले हमारे देश में हैं। न्याय की आशा में कितने ही लोग बरसों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने को विवश हो जाते हैं। हालिया बरसों में मासूम बच्चों के शारीरिक शोषण ही नहीं, बर्बर हत्या के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में ये दोनों निर्णय रेखांकित करने योग्य हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मंदिर की संपत्ति

'सुनिश्चित हो दान का सदुपयोग' शीर्षक से प्रकाशित शिवकांत शर्मा का आलेख वर्तमान समय के एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय को रेखांकित करता है। लेखक ने अयोध्या से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों में वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो चिंता व्यक्त की है, वह समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह प्रासंगिक है। हालांकि इस समस्या का समाधान आत्मग्लानि या केवल व्यवस्था पर प्रश्न उठाने में नहीं है। वर्तमान में हमारे देश के प्रमुख मंदिर केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक और सामाजिक इंजन में परिवर्तित हो चुके हैं, जो लाखों परिवारों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। विडंबना यह है कि आधुनिक समाज मंदिरों को केवल पूजा-पाठ का स्थान मानता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से वे शिक्षा, कला, लोककल्याण और सामाजिक संगठन के जीवंत केंद्र रहे हैं। समस्या का मूल कारण सनातन धर्म या हिंदू समाज की अक्षमता नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ संस्थागत संरचना और आधुनिक शासन-पद्धति का अभाव है। विमर्श इस बात पर नहीं होना चाहिए कि नियंत्रण किसका हो, बल्कि यह होना चाहिए कि वित्तीय जवाबदेही किसके प्रति हो। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार, मंदिर की संपत्ति समाज द्वारा ईश्वर को समर्पित एक धरोहर है, जिसकी सुरक्षा और पारदर्शिता हमारा धार्मिक उत्तरदायित्व है। आज हमें परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जहां पूजा-पद्धतियों की पवित्रता अक्षुण्ण रहे, परंतु प्रशासनिक और वित्तीय आडिट पूरी तरह आधुनिक एवं पारदर्शी हो। जब श्रद्धालु जागरूक होकर पारदर्शिता की मांग को धर्मविरोध के बजाय एक नैतिक जिम्मेदारी मानेंगे, तभी हमारे मंदिर पुनः लोकमंडल के मार्गदर्शक और भारतीय सभ्यता के धड़कते हुए हृदय बन सकेंगे।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

मेलबाक्स

जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करें

एक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने सरकारी नौकरी न मिलने से आत्महत्या कर ली। यह मामला बहुत से सवाल खड़े करता है। ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी सी विफलता, हार या जिंदगी में ऊंचे-नीचे पड़ाव आने पर हम खुद को संभाल नहीं पाते? यहां माता-पिता की भी गलती है कि बच्चों को अपने दुख-दर्द बांटना नहीं सिखाते। उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं करते। हमारे शिक्षण संस्थान भी केवल अच्छे नंबर, रैंक और जीतना ही सीखाते है। फेल होने वाले को नीची दृष्टि से देखा जाता है, जो सरासर गलत है। इससे उनमें हीनभावना आ जाती है और वे आत्मविश्वास खो बैठते हैं। शिक्षण संस्थानों और माता-पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों को जिंदगी में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करें। उन्हें हार को स्वीकार करना सीखाएं, गिर कर दोबारा खड़ा होना बताएं।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

विज्ञानियों का त्याग पत्र

इसरो से सौ विज्ञानियों ने त्यागपत्र दिया है। इन त्याग पत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने एक नया आदेश दिया है कि अब महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े विज्ञानियों के इस्तीफे सीधे सेंटर डायरेक्टर अप्रूव नहीं कर सकते। हर त्यागपत्र को स्वीकृति करने का अधिकार अब अंतरिक्ष विभाग को होगा। त्यागपत्र कम वेतन, कैरियर में प्रोन्नति की कमी एवं ब्यूरोक्रेसी के ढीले-ढाले रवैए के कारण हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट स्पेस सेक्टर के खुलने से भी इसरो वगैरह सरकारी संस्थानों से विज्ञानी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे इन विज्ञानियों के त्यागपत्र के लिए छह माह का नोटिस अनिवार्य कर देना चाहिए। इस अवधि में त्यागपत्र देने वाले विज्ञानी के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वह अपने एक सहयोगी को अपनी विशिष्ट प्रतिभा में पारंगत कर दें।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

4,791 स्कूल बंद हुए हैं वर्ष 2025-26 के दौरान देश में, भारत में स्कूली शिक्षा पर आधारित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस- 2025-26 नामक रिपोर्ट के अनुसार।

अजय प्रताप तिवारी

शिक्षा मामलों के जानकार

सरकारी विद्यालय

शिक्षा के प्रति चिंता बढ़ा रहे घटते स्कूल

हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में देश में लगभग 94 हजार सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं या अन्य स्कूलों में विलय कर दिए गए हैं। आखिर जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तब स्कूलों की संख्या घट क्यों रही है? वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। देश में सरकारी स्कूलों का बंद होना केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर देगा। लिहाजा इस बारे में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है

ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में बसावट के निकट प्राथमिक विद्यालयों की अनिवार्यता को समझा जाना चाहिए। फाइल

स्कूल शिक्षा का केंद्र होने के साथ ही राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला होते हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, यहां पर जनसांख्यिकीय लाभ तभी संभव है, जब सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुलभ हो। सशक्त स्कूल ही जागरूक, कुशल, नैतिक और नवाचारी नागरिक तैयार करते हैं, जो राष्ट्र के समग्र विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत में स्कूली शिक्षा पर आधारित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस-2025-26 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान देश में कुल 4,791 स्कूल बंद हुए हैं तथा प्रत्येक दिन लगभग 13 स्कूल बंद हो रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में स्कूलों के आपसी विलय के कारण भी उनकी संख्या में कमी दर्ज की गई, जो आंकड़ों में अलग तथ्य दर्शाते हैं।

वस्तुतः देश में स्कूलों के बंद होने से शिक्षा तक पहुंच सीमित होगी, ड्रापआउट के मामले बढ़ेंगे, सामाजिक असमानता गहरी होगी और मानव पूंजी का विकास बाधित होगा तथा कुशल कार्यबल, उत्पादकता तथा राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि इस मामले में एक बेहतर प्रवृत्ति भी दिख रही है। जहां एक तरफ स्कूलों की संख्या घट रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में इसकी संख्या बढ़ी भी है, मसलन बिहार में 946, छत्तीसगढ़ में 234 और दिल्ली में 87 स्कूल बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तब स्कूलों की संख्या बढ़ने के बजाय घट क्यों रही है? जबकि निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। देश में सरकारी स्कूलों का बंद होना केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि यह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से भी वंचित कर देगा।

हालांकि नीति आयोग इस बात पर जोर देता है कि विकसित भारत के सपने को स्वीकार करने के लिए हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और आधुनिक कौशल आवश्यक है। भारत में कुल स्कूलों की बात करें तो वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 14,71,473 स्कूल थे, जबकि 2025-26 में ये संख्या घटकर 14,66,682 रह गई है। एक तरफ जहां देश में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं, जहां पर जीरो एनरोलमेंट हैं।

बंद होने का कारण : सरकार सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने का प्रयास तेजी से कर रही है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति के माध्यम से आर्थिक सहायता, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तथा शिक्षकों की नियुक्तियों जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहा है। पिछले दो वर्षों में 86 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों का साथ छोड़ा है, जबकि इसी अवधि में निजी विद्यालयों में 88 लाख नए छात्रों का प्रवेश हुआ।

अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? यह सरकारी और निजी स्कूलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत नहीं है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति अभिभावकों के घटते विश्वास को भी रेखांकित करती है। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा में केवल संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। अभिभावक अब ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जो उनके बच्चों को बेहतर सीखने का वातावरण, अनुशासन, अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी दक्षता और भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। इसलिए सरकारी स्कूलों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आधारभूत सुविधाओं की नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सीखने के बेहतर परिणाम और जवाबदेह जैसी व्यवस्था स्थापित करना है। सरकारी स्कूल तभी अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेंगे, जब वे सुविधाओं के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम और कौशल युक्त उत्कृष्ट शिक्षा का भी भरोसा दिला सकें। सरकारी स्कूलों में छात्र के अनुपात में अध्यापक की कमी और अध्यापकों पर अतिरिक्त कार्यों का दायित्व का निर्वहन भी एक बड़ी समस्या है।

आगे की राह : देश की एक बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहां लोग अनेक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन-यापन करने को विवश हैं। शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता भी आज करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों का बंद होना केवल बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करेगा, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। इसलिए स्कूलों को बंद करना एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कौशल और नवाचार के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी हमेशा बनी रहती है, इसे दूर करने के लिए शिक्षक भर्ती प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों को राज्य स्तरीय नवोदय जैसे माडल में तब्दील करने पर ध्यान देना चाहिए। वाद-विवाद, निबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सामुदायिक सेवा जैसे सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाए। आज स्कूल कमजोर होंगे तो कल राष्ट्र की मानव पूंजी भी कमजोर होगी। इसलिए आवश्यकता स्कूलों की संख्या घटाने की नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक, आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की है।

प्रगति की राह में खड़ी हो सकती नई बाधा

आदित्य कुमार

शिक्षा मामलों के जानकार

आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा जनसंख्या है। यही युवा शक्ति वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की आधारशिला बन सकती है। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब देश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तब देश में स्कूलों की घटती संख्या एक ऐसा प्रश्न बनकर उभर रही है, जिस पर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। वस्तुतः विद्यालय केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं होते। वे किसी भी समाज की बौद्धिक चेतना, सामाजिक समानता और आर्थिक प्रगति के केंद्र होते हैं। इसलिए यदि किसी देश में विद्यालयों की संख्या घटती है, तो उसका अर्थ केवल संस्थानों का कम होना नहीं, बल्कि शिक्षा की पहुंच, सामाजिक न्याय और मानव संसाधन विकास पर संभावित प्रभाव भी होता है।

हाल के वर्षों में विद्यालयों की संख्या में कमी आई है। सरकार का कहना है कि इसका बड़ा कारण कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का एकीकरण तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। निस्संदेह, यदि किसी क्षेत्र में दो या तीन विद्यालयों में पर्याप्त विद्यार्थी नहीं हैं और शिक्षकों की भारी कमी है, तो उनका समुचित पुनर्गठन प्रशासनिक दृष्टि से उचित माना जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हर क्षेत्र में यह नीति समान रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है? ग्रामीण भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हजारों गांव ऐसे हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक जीवन का आधार हैं। विद्यालय बंद होने या दूसरे विद्यालय में विलय होने के बाद बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में विद्यालय छोड़ने की आशंका बढ़ जाती है।

यह स्थिति केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि सामाजिक समानता का भी प्रश्न है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार निजी परिवहन या निजी विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं, किंतु गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा दूरदराज क्षेत्रों के परिवारों के सामने विकल्प सीमित होते हैं। यदि विद्यालय की दूरी शिक्षा में बाधा बनने लगे, तो संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। नई शिक्षा नीति गुणवत्ता पर विशेष बल देती है। परंतु आज भी देश में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, विज्ञान प्रयोगशालाएं नहीं हैं, पुस्तकालय नहीं हैं और डिजिटल संसाधनों का अभाव है। ऐसे विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाते।

भारत लंबे समय से शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत व्यय करने की जरूरत को स्वीकार करता रहा है। पर्याप्त सार्वजनिक निवेश के बिना विद्यालय व्यवस्था का निर्माण संभव नहीं है। विकसित देशों का अनुभव भी बताता है कि आर्थिक समृद्धि की सबसे मजबूत नींव शिक्षा में निवेश से ही तैयार होती है। स्कूलों की घटती संख्या को केवल प्रशासनिक सुधार मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विषय भारत की मानव पूंजी, सामाजिक न्याय और भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता से जुड़ा है। शिक्षा पर किया गया प्रत्येक निवेश आने वाली पीढ़ियों में निवेश होता है। इसलिए समय की मांग है कि विद्यालयों की संख्या, उनकी गुणवत्ता और उनकी भौगोलिक पहुंच- तीनों के बीच ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे देश का कोई भी बच्चा केवल दूरी या संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। विकसित भारत की राह सशक्त विद्यालयों से होकर गुजरती है, इसलिए सबसे पहले हमें स्कूलों को सक्षम बनाना होगा।

खरी-खरी

ट्रेन का किराया

विनय कुमार पाठक

गरीबदास को दिल्ली से मुंबई जाना था। कोई आपातकाल नहीं था। पूरे एक महीने का समय था। उन्होंने सोचा, "इतनी लंबी अवधि में तो रेलवे भी दया कर देगी।" पर यह उनका पहला भ्रम था।

नाम से तो वह गरीब थे ही, जेब भी इस नाम का पूरा सम्मान करती थी। हां, इतने भी गरीब नहीं थे कि जनरल डिब्बे में 18 घंटे तक दरवाजे से लटकते हुए राष्ट्रीय एकता का अनुभव कर सकें।

उन्होंने टिकट खोज अभियान शुरू किया। सबसे पहले सामने आई तेजस राजधानी। इसमें जनरल तो दूर, स्लीपर तक गायब था। मानो रेलवे ने घोषणा कर दी हो कि अब गरीबों का देश में स्वागत है, ट्रेन में नहीं। तीसरे एसी का किराया देखा तो तीन हजार रुपये पार था।

फिर कई ट्रेनें देखीं। अधिकांश में बिना एसी के डिब्बे ऐसे लापता थे जैसे चुनाव के बाद चुनावी वादे। एक दुरंतो मिली, जिसमें बैठने वाला साधारण डिब्बा था। किराया तो जेब के अनुकूल था, लेकिन 18 घंटे बैठने का विचार सुनते ही उनकी कमर ने अग्रिम विरोध दर्ज करा दिया। ऊपर से टिकट भी वेटिंग में।

स्लीपर की आशा लेकर स्वराज एक्सप्रेस पहुंचे। वहां प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी थी कि लगा, मुंबई पहुंचने से पहले नंबर आना मुश्किल है। गरीब रथ में टिकट उपलब्ध था, लेकिन किराया देखकर लगा कि शायद रेलवे का आशय गरीब यात्रियों से नहीं, गरीबों की यादों से था।

याद आया कि कभी घोषणा हुई थी- "हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा।" देखा तो पाया किराया पांच हजार रुपये से ऊपर था। गरीबदास ने मन ही मन सोचा, "शायद उस घोषणा में हवाई चप्पल चांदी की रही होगी।"

आखिरकार उन्होंने वेटिंग टिकट खरीद लिया और शेष जिम्मेदारी भगवान तथा रेलवे- दोनों के संयुक्त उपक्रम पर छोड़ दी।

अब वे रोज पीएनआर देखते हैं। टिकट कंफर्म हो गया तो रेलवे की कृपा, नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। आखिर हमारे यहां यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण आस्था होती है। रेलवे भी शायद इसी सिद्धांत पर चल रही है। आखिर विश्वास पर ही तो देश चल रहा है।

X पोस्ट

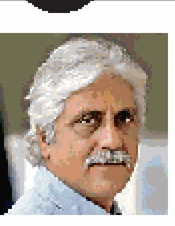

फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन शुरुआत से ही दबदबा बनाए रहा। उसकी जीत और बड़ी होनी चाहिए थी। अर्जेंटीना की टीम मैच को अतिरिक्त समय में ले जाकर किसी तरह मुकाबले में तो बनी रही, लेकिन कभी उसे अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाई। मेसी को अपना जादू दिखाने की जरा भी गुंजाइश नहीं मिली।

अयाज मेमन@cricketwallah

स्पेन की नागरिकता प्राप्त करने के बावजूद लियोन मेसी ने अपनी राष्ट्रीय निष्ठा अर्जेंटीना के प्रति बनाए रखी। यह दर्शाता है कि नागरिकता कानूनी अधिकार तो प्रदान कर सकती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद हृदय से जन्म लेते हैं। सच्चा देशप्रेम सुविधा या अवसर से नहीं, मातृभूमि के सम्मान, उसके ध्वज के प्रति समर्पण और उसके लिए किए गए कर्मों से परिभाषित होता है।

डा. अवनींद्र कुमार राय@avanindra43

इंस्टाग्राम रील्स, हैशटैग और आनलाइन हाइप से कोई पार्टी नहीं बन सकती। कुछ लाख फालोअर्स होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास देश चलाने के लिए आवश्यक समझ, अनुभव या विजन भी होगा।

मीरा चोपड़ा@MeerraChopra

जयकृष्ण वाजपेयी

राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

सख्त कानून, स्मार्ट सीमा और सत्ता का संदेश

बंगाल की तासीर, सियासत और सरहद इन दिनों एक युगांतरकारी बदलाव के दौर से गुजर रही है। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद जो प्रशासनिक और सामरिक सक्रियता दिखाई दे रही है, उसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सुरक्षा थिंक-टैंक को एक नए विमर्श में बांध दिया है। एक तरफ राज्य की नई भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए देश के कुछ सबसे कठोर आंतरिक सुरक्षा कानूनों को धरातल पर उतार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह की सिलीगुड़ी कारिडोर (चिकन नेक) में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीएसएफ और जिला पुलिस प्रशासन के साथ हुई उच्च स्तरीय सामरिक समीक्षा बैठक ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल अब आंतरिक अराजकता और बाहरी घुसपैठ के खिलाफ एक नए 'चक्रव्यूह' का निर्माण कर रहा है।

पिछले सप्ताह से राज्य में दो बेहद सख्त कानून प्रभावी हो गए हैं- पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 (एंटी-गुंडा एक्ट) और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026। इन नए प्रविधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस कमिश्नरों को असीमित अधिकार मिल गए हैं कि वे किसी व्यक्ति के असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका मात्र पर उसे बिना किसी अदालती मुकदमे के अधिकतम 12 महीने के लिए निवारक हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) में भेज सकते हैं।

इस कानून की सबसे बड़ी मार इसके व्यापक और समावेशी दायरे में छिपी है। अब 'गुंडा' और 'असामाजिक गतिविधियों' की परिभाषा केवल शारीरिक हिंसा या आदतन अपराधियों तक सीमित नहीं रह गई है। बंगाल की रीढ़ बन चुके जबरन वसूली के संगठित 'सिंडिकेट राज', तोलाबाजी, अवैध कोयला व बालू खनन, वन अपराध, साइबर ठगी और बड़े वित्तीय घोटालों के संरक्षकों को भी इसी कानून के तहत रगड़ा जाएगा।

सिलीगुड़ी में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ पोस्ट से अवलोकन करते अमित शाह। इंटरनेट मीडिया

हालांकि, कानून लागू होते ही इसे कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका के जरिये चुनौती दे दी गई है, जहां विपक्ष इसे लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों पर करारी चोट बता रहा है। लेकिन इस आंतरिक कड़ाई के साथ-साथ जो असली और बड़ा खेल चल रहा है, वह बंगाल की भौगोलिक और सामरिक सीमाओं पर है। आंतरिक मोर्चे पर इन कड़े कानूनों के लागू होने के ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय बंगाल दौरा और सीधे भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित सिलीगुड़ी के जूमागाछ बार्डर आउटपोस्ट पहुंचना बहुत कुछ बयां करता है। सिलीगुड़ी कारिडोर, जिसे सामरिक भाषा में 'चिकन नेक' कहा जाता है, भारत की अखंडता के लिए सबसे संवेदनशील नस है, जो मुख्य भू-भाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में तीस्ता नदी पर बैराज निर्माण की चीनी योजनाओं और चीनी इंजीनियरों की बढ़ती हलचल ने दिल्ली के कान खड़े कर दिए हैं। इसके पलटवार में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर खड़े होकर इसे एक 'अभेद्य किला' बनाने की दिशा में 77.06 करोड़ रुपये की विभिन्न बीएसएफ परियोजनाओं और चार किमी लंबी नई सीमा तारबंदी का शिलान्यास किया।

भारत अब 'स्मार्ट बार्डर' के कांसेप्ट पर काम कर रहा है। जूमागाछ में इन्फ्रा-रेड अलार्म सिस्टम, रेडियो-आधारित बाड़ भेदन पहचान प्रणाली और गेट मैनेजमेंट साफ्टवेयर जैसी स्वदेशी व अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया, जो किसी भी प्रकार की मानवीय या जलीय घुसपैठ की अग्रिम चेतावनी तुरंत सुरक्षाबलों को दे देंगी। महानंदा नदी और सुंदरबन के दलदली रास्तों से होने वाली घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए नदी क्षेत्रों में स्मार्ट वर्चुअल फेंसिंग और उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो अभूतपूर्व समन्वय दिख रहा है, उसने पुरानी सरकारों के दौरान फेंसिंग के लिए होने वाली राजनीति को हमेशा के लिए दफन कर दिया है।

गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी की बैठक में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, अवैध आधार व वोटर कार्ड के निर्माण और फर्जी पहचान पत्रों के सिंडिकेट को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 'फ्री हैंड' दे दिया है। सुदूर उत्तर के सीमांत क्षेत्रों में गूंजती अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की सायरन और कोलकाता की विधानसभा से निकले कठोरतम प्रशासनिक कानून- ये दोनों मिलकर यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि बंगाल अब तुष्टीकरण और राजनीतिक अराजकता के पुराने ढर्रे को छोड़ चुका है। आंतरिक मोर्चे पर सख्त प्रशासनिक नियंत्रण और बाहरी मोर्चे पर अभेद्य सामरिक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का यह दोहरा पहरा आने वाले समय में न केवल बंगाल की कानून-व्यवस्था की नई इबारत लिखेगा, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया कवच प्रदान करेगा।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सोनम वांगचुक के मामले में प्रशासन की कार्रवाई सही है?

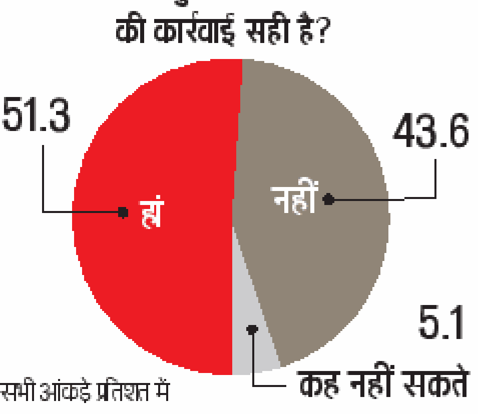

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या फीफा विश्व कप फाइनल में मेसी का फीका प्रदर्शन अर्जेंटीना की हार का मुख्य कारण बना?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

अर्जेंटीना भी भिड़ा खूब दिखाया खेल,
पर अबकी स्पेन का हुआ जीत से मेल।
हुआ जीत से मेल उठाई उसने ट्राफी,
मेसी हित स्थान दूसरा ही अब काफी।
बेशक हैं उस्ताद बहाया खूब पसीना,
लेकिन कप इस बार न पाया अर्जेंटीना!

-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

डा. वेदप्रकाश

असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

पौधरोपण के साथ संरक्षण भी

प्रत्येक वर्ष मानसून के आरंभ के समय बड़ी संख्या में पौधे लगाए तो जाते हैं, परंतु देखरेख के अभाव में उनमें से अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में इनके संरक्षण की भी आवश्यकता है

पौधरोपण के साथ ही उसके संरक्षण की भी पर्याप्त सुरक्षा पर देना होगा ध्यान। फाइल

केंद्र सरकार ने हाल ही में देशभर के लगभग 15 हजार पवित्र वन क्षेत्रों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए आस्था वन संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। ध्यातव्य है कि देश के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के आसपास वन क्षेत्र मिलते हैं जिनका संरक्षण वहां के स्थानीय समुदाय करते हैं, ऐसे में सरकार की यह योजना महत्वपूर्ण होगी। आज एक नागरिक के नाते हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति एवं पर्यावरण हम सभी के साझे हैं और जीवन की अनिवार्यता हैं। इसलिए इनकी चिंता भी हम सभी को मिलकर करनी होगी। पौधरोपण के साथ पौधों का संरक्षण या उन्हें जीवित रखना भी आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों में डीडीए, वन विभाग, एमसीडी एवं पीडब्ल्यूडी आदि विभागों ने दिल्ली में लगभग 40 लाख प्रतिवर्ष की औसत से दो करोड़ पौधे लगाए, जिनमें से वन विभाग के आडिट में 70 प्रतिशत तो वहीं स्वतंत्र संस्थाओं के सर्वे में 10 से 15 प्रतिशत पौधे ही अगले मानसून तक जीवित बचते हैं।

हमें समझना होगा कि तीन चार वर्ष तक पौधे का पालन-पोषण भी बच्चों की तरह करना पड़ता है। इस अवधि में उसे पर्याप्त खाद-पानी और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के विभिन्न राजमार्गों के आसपास पशु और पानी न मिलना पौधों के सूख जाने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। सरकारी संस्थाओं द्वारा पौधरोपण के नाम पर खानापूर्ति भी सामान्य बात है। क्या आज सरकारी संस्था और एक नागरिक के नाते हमें पौधरोपण व संरक्षण के लिए ईमानदार नहीं बनना चाहिए? क्या पौधों का ठीक रखरखाव और संरक्षण न होने पर संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

लापरवाही पर नियंत्रण : छोटी-छोटी मानवीय भूल से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जंगल की आग देखते-देखते बड़े वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है। वर्षों की मेहनत से तैयार हुए पेड़ और वनस्पतियां जलकर राख हो जाते हैं। क्या यह राष्ट्रीय और पर्यावरणीय क्षति नहीं है? क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए समुचित समन्वय और संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? ध्यान रहे, एक पेड़ मनुष्य सहित प्रत्येक जीवधारी को प्राणवायु आक्सीजन के साथ-साथ भोजन, फल, फूल, लकड़ी और औषधियां भी प्रदान करता है। ये पेड़ ही पर्यावरण में गैसों का संतुलन बनाते हैं और जलचक्र व ऋतुचक्र को संतुलित रखते हुए निरंतरता प्रदान करते हैं।

भारतीय जीवन पद्धति में पौधा लगाने एवं उसकी रक्षा करने को पुण्य कर्म माना गया है। पेड़ धरती के फेफड़े हैं। विकास और बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगल की आग जीवन की संभावनाओं को कम कर रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति पेड़ों का महत्व समझे। वह एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले? केंद्र और प्रत्येक प्रदेश वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को प्रभावी बनाकर इनके संरक्षण की दिशा में बड़ा काम कर सकते हैं। संविधान में दिए गए नागरिक कर्तव्य भी हमें वन, वन्य जीव एवं जल स्रोतों के संरक्षण-संवर्धन हेतु संदेश देते हैं।

जीवन के विकासक्रम के आरंभ से ही अग्नि, धरती, जल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, हवा, पेड़, पौधे, वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से मनुष्य का सहचर्य अथवा प्रगाढ़ परिचय रहा है। लेकिन कालांतर में औद्योगिक क्रांति और अधिकाधिक उत्पादन की लालसा मनुष्य को विभिन्न रूपों में पर्यावरणीय घटकों के दोहन की ओर लेकर जाने लगी। मनुष्य के बढ़ते हस्तक्षेप व पर्यावरणीय घटकों से छेड़छाड़ एवं प्रदूषण के कारण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। इसलिए पेड़-पौधों के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध को समझने और पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।

चिंताजनक यह है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की होड़ में घातक गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज देश की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी सैकड़ों नदियां कम जल अथवा सूखे का सामना कर रही हैं। कई नदियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। पेड़ हमें इन संकटों से बचा सकते हैं। पौधरोपण और संरक्षण का महत्व निर्विवाद है। पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर चलाए जाने वाले अभियानों के अलावा शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों के जरिये जागरूकता अभियान चलाने होंगे। इससे सघन वृक्षावरण तैयार हो सकता है।

एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट्स, जिंदल सुप्रीम को आइपीओ की मंजूरी

नई दिल्ली: सेबी ने एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड को आइपीओ के जरिये धन जुटाने की मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल-मई के दौरान आइपीओ की मंजूरी के लिए दस्तावेज दाखिल किए थे। बिजली पारेषण और वितरण अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी एब्सोल्यूट प्रोजेक्ट्स का आइपीओ पूरी तरह दो करोड़ नए इक्विटी शेयरों का निर्गम होगा। (प्रेट्र)

जीएसटी में कटौती के बाद बढ़ी घरेलू मांग, ग्रामीण बाजारों में तेजी और अंतरराष्ट्रीय कारोबार की मजबूत आर्डर बुक कंपनी की वृद्धि को गति देंगे। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी तनाव से कुछ बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है।

– अर्नब बनर्जी, एमडी और सीईओ, सिएट

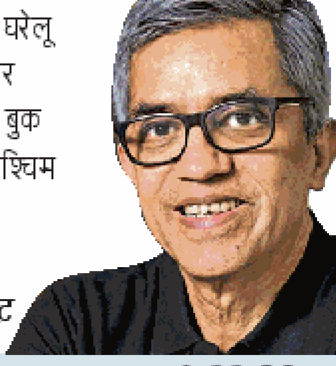

संसेक्स	77,708.52	▼ 442.93	
निफ्टी	24,238.50	▼ 95.80	
सोना प्रति दस ग्राम	₹1,46,900	▲ ₹1,400	
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,21,500	▼ ₹1,000	
डालर	₹ 96.36	▲ ₹ 0.06	
क्रूड प्रति बैरल	$ 88.06		

सरकार के पास लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं

संसद प्रश्नोत्तर

नई दिल्ली, आइएएनएस: वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में बताया कि फिलहाल सरकार के पास खुदरा और घरेलू निवेशकों द्वारा किए जाने वाले इक्विटी लेनदेन पर लगाए जाने वाले लांग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर किसी एसेट को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखा जाता है, तो उसे लांग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। इक्विटी लेनदेन पर एलटीसीजी टैक्स कलेक्शन 2024-25 में 72,249 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 1,29,158 करोड़ रुपये हो गया। सूचीबद्ध इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स 12.5 प्रतिशत तय किया गया है, जो हर वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा के मुनाफे पर ही लागू होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में कहा था कि सरकार कर प्रणाली के बारे में शेयर बाजार की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। इसमें एलटीसीजी और शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) टैक्स से जुड़े मुद्दे हैं।

सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि एलआइसी के पास 31 मार्च, 2026 तक 7,318.50 करोड़ रुपये बिना दावे वाली धनराशि थी।

पूंजीगत व्यय बढ़कर 90.87 लाख करोड़ हुआ

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद में बताया कि 2014-26 के दौरान केंद्र का पूंजीगत व्यय बढ़कर 90.87 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2004-14 के दौरान दर्ज 17.04 लाख करोड़ रुपये से पांच गुना से भी अधिक है। वहीं, इसी अवधि में सरकार का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय 12.39 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 64.70 लाख करोड़ रुपये हो गया। सरकार ने बताया कि प्रभावी पूंजीगत व्यय का अर्थ है संपत्ति निर्माण के लिए केंद्र सरकार का व्यय। इसमें राज्य सरकारों को संपत्ति बनाने के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान भी शामिल हैं। इसमें समग्र शिक्षा के तहत स्कूल भवन और पीएम आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए दिया जाने वाला धन भी शामिल है।

आयकर विभाग में अभी 26,997 पद खाली

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में बताया कि एक जनवरी, 2026 तक आयकर विभाग में ग्रुप ए, बी और सी के 26,997 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि खाली पदों का सृजन और उन्हें भरना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

यूपीआइ से 24,161 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन हुए

नई दिल्ली, आइएएनएस: सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि जून 2026 तक यूपीआइ प्लेटफार्म से लगभग 55.49 करोड़ यूजर्स जुड़ चुके थे। साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान यूपीआइ ने 314.23 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 24,161.69 करोड़ ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए। पिछले पांच वित्त वर्षों में ट्रांजेक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआइ ने 84.16 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 4,595.61 करोड़ ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए थे।

विदेशी निवेश के प्रवाह में आ सकती है तेजी

2025-26 में 16 अरब डालर की पूंजी निकासी के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में एफपीआइ प्रवाह में सुधार की उम्मीद है। केयरएज रेटिंग्स ने कहा है कि कुल आवक में अच्छी वृद्धि से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के वित्त वर्ष 2025-26 के सात अरब डालर से बढ़कर 2026-27 में 15 अरब डालर रह सकता है।

अप्रैल में 15.3 अरब डालर रहा सकल एफडीआइ

वित्त वर्ष 2025-26 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 94.8 अरब डालर हो गया और यह तेजी वित्त वर्ष 2026-27 में भी जारी रही। अप्रैल में सकल निवेश 65 प्रतिशत बढ़कर 15.3 अरब डालर हो गया।

पूंजी निकासी में लगातार आ रही कमी

निकाली जाने वाली पूंजी की वृद्धि दर पिछले दो सालों में लगातार कम हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह जहां 51.6 प्रतिशत थी वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 15.8 प्रतिशत रह गई। 2025-26 में यह मात्र पांच प्रतिशत रह गई।

60 अरब डालर का निवेश आकर्षित करने में मिलेगी मदद

रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआइ के हालिया नीतिगत उपायों से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (एफसीएनआर-बी), वाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी), विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) से 45-60 अरब डालर का बड़ा निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। आरबीआइ ने बताया है कि उसे अनिवासी भारतीयों की जमा से 17.41 अरब डालर मिले हैं। जबकि ईसीबी से 1.34 अरब डालर और ओएफसीबी से 1.97 अरब डालर मिले हैं।

एफपीआइ निवेश को मिलेगा बढ़ावा

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआइ के लिए टैक्स से जुड़े उपाय, भारतीय इक्विटी के कम मूल्यांकन और ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारत की सरकारी प्रतिभूतियों के संभावित तौर पर शामिल होने से एफपीआइ निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2025-26 के निराशाजनक अंत के बाद भारत का पूंजी खाता (कैपिटल अकाउंट) अब बेहतर स्थिति की ओर बढ़ता दिख रहा है। सकल एफडीआइ निवेश में अच्छी वृद्धि हुई है और निकाली जाने वाली पूंजी की वृद्धि दर में कमी के साथ-साथ नीतिगत उपायों के समर्थन से इसके वित्त वर्ष 2026-27 में 15 अरब डालर रहने की उम्मीद है।

रजनी सिन्हा, मुख्य अर्थशास्त्री, केयरएज रेटिंग्स

चालू वित्त वर्ष में सकारात्मक हो जाएगा भुगतान संतुलन

केयरएज ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि लगातार दो साल के घाटे के बाद वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का भुगतान संतुलन (बैलेंस आफ पेमेंट) सकारात्मक हो जाएगा। केयरएज ने रुपया मजबूत होने के अपने रुख को बरकरार रखा, लेकिन अपने अनुमान में मामूली बदलाव किया है और उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2027 में एक डालर 93-94 रुपये के बीच रहेगा।

इनपुट : आइएएनएस

एक नजर में

लोहिया कार्प के आइपीओ का मूल्य दायरा तय

नई दिल्ली: औद्योगिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लोहिया कार्प लिमिटेड ने अपने 1,102 करोड़ के आइपीओ के लिए 404-425 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन 4,500 करोड़ रुपये आंका गया है। आइपीओ 23 को खुलेगा और 27 जुलाई को बंद होगा। बड़े निवेशक 22 जुलाई को बोली लगा पाएंगे। यह आइपीओ पूरी तरह 2.59 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश पर आधारित है। इसलिए कंपनी को इस सार्वजनिक निर्गम से कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। कंपनी का शेयर 30 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होगा। (प्रेट्र)

इंडियन ओवरसीज बैंक का शुद्ध लाभ 49 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 49.3 प्रतिशत बढ़कर 1,659 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार से बैंक का लाभ बढ़ा है। पिछले साल 2025-26 की इसी तिमाही में बैंक को 1,111 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 10,938 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 8,866.47 करोड़ रुपये थी। बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) घटकर 1.33 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 1.97 प्रतिशत थी। (प्रेट्र)

अल्ट्राटेक सीमेंट के लाभ में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली: सीमेंट बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 17.23 प्रतिशत बढ़कर 2,603.72 करोड़ रुपये रहा है। आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की इसी तिमाही में कंपनी ने 2,220.91 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी की परिचालन आय वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में 15.85 प्रतिशत बढ़कर 24,648.20 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 21,275.45 करोड़ रुपये थी। कंपनी का कुल खर्च आलोच्य तिमाही में 15.65 प्रतिशत बढ़कर 21,286.19 करोड़ रहा। (प्रेट्र)

कर्ज वसूली में दिवालिया कानून का प्रदर्शन फिसड्डी

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा-शुरुआती दिनों में 54-55% तक हो रही थी वसूली, अब घटकर 20% रह गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दिवालिया व बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) यानी दिवालिया कानून का प्रदर्शन कर्ज वसूली के मामले में लगातार फिसड्डी साबित हो रहा है। पहले इस कानून के तहत जितने मामले आते थे उसमें कुल बकाये कर्ज का 54-55 प्रतिशत तक राशि वसूल हो जाती थी लेकिन अब यह रफ्तार घटते-घटते 20 प्रतिशत पर आ गई है। यह जानकारी वित्त व कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी है। वित्त मंत्री ने जो आंकड़ें दिए हैं वो बताते हैं कि आइबीसी के तहत आने आने वाले मामले तो बढ़ रहे हैं लेकिन इनसे कर्ज वसूली लगातार कम होती जा रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार मानती है कि आइबीसी अपने उद्देश्यों में सफल रही है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में आइबीसी में कुल 233 मामले आए और इनसे 42,003 करोड़ रुपये की वसूली हुई जो कुल बकाये राशि का सिर्फ 20 प्रतिशत थी। जबकि इसके पिछले वर्ष 259 मामलों में 54,604 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी और यह 37 प्रतिशत था। इसी तरह से वर्ष 2017-18 (जब आइबीसी की शुरुआत हुई) में सिर्फ 18 मामलों में 3,807 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी जो 54 प्रतिशत था। यहां बताते चलें कि जब कोई कंपनी अपनी देनदारियां चुकाने में असफल हो जाती है तो उस संबंध में दायर आरोप के आधार पर कर्ज वसूली प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके तहत कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच कर निवेशकों और कर्जदारों को लौटाया जाता है। सरकार ने यह फैसला तब किया था जब भारतीय बैंकिंग सेक्टर फंसे कर्जे की समस्या से बहुत ही ज्यादा जूझ रही थी।

- इसके बावजूद केंद्र सरकार मानती है कि आइबीसी अपने उद्देश्यों में अब तक सफल
- 2025-26 में आइबीसी में 233 मामले आए और इनसे 42,003 करोड़ रुपये की वसूली हुई

कानून में कई बार संशोधन के बावजूद स्थिति जस की तस

दिवालिया कानून में सरकार पिछले आठ वर्षों में कई बार संशोधन कर चुकी है, लेकिन इसके प्रदर्शन में कोई खास सुधार नहीं आया है। इसके तहत मामलों में समाधान में लगने वाला समय भी बढ़ता जा रहा है। इसके तहत किसी भी मामले को 180 दिनों में निपटाने का प्रविधान है। इसमें 90 दिनों का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। लेकिन ताजी जानकारी यह है कि वर्ष 2025-26 में हर मामले को निपटाने में औसतन 744 दिनों का समय लगा है। पिछले साल यह औसत समय 713 दिनों का था।

वर्ष	मामले	वसूली (करोड़ रु में)	(% में)
2017-18	18	3,087	54
2018-19	74	1,07,321	55
2019-20	131	39,043	27
2020-21	119	27,102	27
2021-22	141	46,198	24
2022-23	186	54,125	39
2023-24	258	44,736	28
2024-25	259	54,604	37
2025-26	233	42,003	20

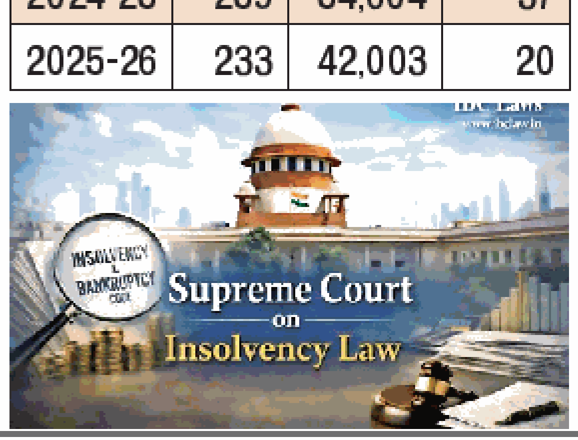

7.79 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पिछले 11-12 सालों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बकाये कर्ज की कुल 7,73,883 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाला है जबकि इस दौरान कुल 3,09,950 करोड़ रुपये की वसूली की है। ये आंकड़े बताते हैं कि कभी फंसे कर्जे की समस्या में गले तक डूबे सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अब अपने वित्तीय रजिस्टर को काफी साफ-सुथरा तो कर लिया है लेकिन इसके लिए उन्हें काफी ज्यादा बकाये कर्ज की राशि को एक तरह से माफ करना पड़ा है।

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि शुरुआती वर्षों (2014-15 और 2015-16) में राइट-आफ (लंबे समय तक कर्ज की वसूली नहीं होने पर उसको वित्तीय हिसाब-किताब में समायोजित करने की प्रक्रिया) की राशि अपेक्षाकृत कम थी (26,602 करोड़ और 32,595 करोड़ रुपये)। उस समय वसूली भी 20,028 करोड़ और 17,500 करोड़ रुपये रही। यह दौर एनपीए का शुरुआती चरण था। इसके विपरीत, 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः 1,20,735 करोड़ और 1,33,179 करोड़ रुपये की राशि बैंकों ने बट्टे खाते में डाली। इन दो वर्षों में वसूली भी अच्छी रही यानी क्रमशः 61,369 करोड़ और 50,156 करोड़ रुपये की।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि दर पांच माह के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश के नौ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जून में बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर पांच प्रतिशत पर पहुंच गया। सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। जून, 2025 में बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि 1.1 प्रतिशत और मई, 2026 में 3.2 प्रतिशत रही थी। आंकड़े 2011-12 के स्थान पर 2022-23 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए हैं। सरकार ने सूचकांक में लौह अयस्क को शामिल किया है जिससे बुनियादी उद्योगों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। जून में सीमेंट का उत्पादन 9.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि मई में संशोधित उत्पादन वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत थी। बिजली के उत्पादन की वृद्धि दर भी 9.8 प्रतिशत रही। वहीं नई सीरीज के तहत सूचकांक में शामिल किए गए लौह अयस्क के उत्पादन में 43.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में इन प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन 3.6 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की समान अवधि में यह वृद्धि एक प्रतिशत रही थी। जून में कोयले के उत्पादन की वृद्धि 1.4 प्रतिशत रही जबकि पिछले महीने उत्पादन में 9.5% की गिरावट आई थी।

सीमेंट, बिजली और लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि मुख्य वजह रही, 2022-23 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए आंकड़े

संसद में पेश हो सकता है एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एमएसएमई की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार मानसून सत्र में एमएसएमई विकास (संशोधन) बिल 2026 पेश कर सकती है। वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास बिल को पारित कराया गया था।

संशोधित बिल में एमएसएमई के भुगतान को लेकर नियम को और उनके पक्ष में बनाए जाने की बात है। अभी एमएसएमई से खरीदारी करने वालों को उन्हें अधिकतम 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का प्रविधान है। बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे एमएसएमई है जिन्हें उनके खरीदार से 45 दिनों में भुगतान नहीं मिलता है। इस प्रकार की शिकायत के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है जहां रोजाना शिकायतें दर्ज होती है। आपसी बातचीत से रोजाना शिकायतों का निपटान भी हो रहा है, लेकिन एक लाख से अधिक शिकायत लंबित है। भुगतान में देरी होने से एमएसएमई को कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है जिससे वे नए आर्डर नहीं ले पाते हैं।

एचडीएफसी व एक्सिस बैंक में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 443 अंक टूटा

मुंबई, प्रेट्र: स्थानीय शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट आई और दोनों मानक सूचकांक नुकसान में रहे। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ मार्जिन संबंधी दबाव को लेकर एचडीएफसी और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के शेयरों में बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 442.93 अंक टूटकर 77,708.52 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 95.80 अंक टूटकर 24,238.50 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में, एक्सिस बैंक सबसे अधिक नुकसान में रहा। बीते शनिवार को तिमाही नतीजों के बाद इसमें 5.48 प्रतिशत की गिरावट आई। वहीं एचडीएफसी बैंक में 5.12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रानिक्स में भी प्रमुख रूप से गिरावट रही। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 88.06 डालर प्रति बैरल पर पर रहा।

77,708.52 अंक पर बंद हुआ बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक

96 अंक टूटकर 24,238.50 पर आया एनएसई निफ्टी

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। इसका कारण पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी शेयरों की अगुआई में बिकवाली के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। एचडीएफसी बैंक में तेज गिरावट ने नुकसान को और बढ़ा दिया। उम्मीद से कमजोर शुद्ध ब्याज मार्जिन ने निवेशकों को निराश किया। इससे बैंक क्षेत्र और शेयर बाजार पर दबाव पड़ा।

-पोनमुडी आर. सीईओ, एनरिच मनी

रुपया 6 पैसे टूटकर 96.36 प्रति डालर पर: मुंबई, प्रेट्र: वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की धारणा और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपया सोमवार को छह पैसे की गिरावट के साथ डालर के मुकाबले 96.36 पर बंद हुआ।

10 जुलाई से अब तक चांदी 15,500 गिरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वैश्विक बाजार में मजबूती के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,400 रुपये बढ़कर 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। हालांकि, चांदी 1,000 रुपये घटकर 2,21,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। यह लगातार छठा सत्र है जब कीमती सफेद धातु में गिरावट दर्ज की गई है। 10 जुलाई से अब तक चांदी की कीमत में 15,500 रुपये या 6.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

आइएलएंडएफएस ने जून तक 50,387 करोड़ का कर्ज चुकाया

नई दिल्ली, प्रेट्र: कर्ज संकट से जूझ रहे आइएलएंडएफएस समूह ने जून, 2026 तक अपने लेनदारों को कुल 50,387 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। समूह की तरफ से किया गया यह भुगतान सितंबर, 2025 में दाखिल पिछली रिपोर्ट के मुकाबले करीब चार प्रतिशत अधिक है। उस समय तक 48,463 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

आइएलएंडएफएस ने बताया कि 50,387 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ ही उसका कुल ऋण समाधान 61,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य का करीब 82.6 प्रतिशत हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने में समूह ने बेहतर प्रगति की है। इन संस्थानों के कुल 91,000 करोड़ रुपये के कर्ज में से लगभग 88.4 प्रतिशत यानी करीब 57,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय फलक

डिजिटल सुविधा : राजमार्ग यात्रा एप से घर बैठे मिलेगा लोकल टोल पास

नई दिल्ली प्रेट्र: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब किसी भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही लोकल टोल पास खरीद सकेंगे। इस पास की मदद से संबंधित टोल प्लाजा से पूरे महीने असीमित बार आवाजाही की जा सकेगी।

अब तक स्थानीय पास बनवाने के लिए लोगों को संबंधित टोल प्लाजा पर स्वयं जाकर आवेदन करना पड़ता था और पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते थे। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में आनलाइन पूरी की जा सकेगी, जिससे समय की बचत होगी और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनएचएआइ के अनुसार, डिजिटल लोकल टोल पास की शुरुआत फिलहाल दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा से की गई है। आने वाले महीनों में इस सुविधा का विस्तार देशभर के अन्य पात्र टोल प्लाजाओं तक किया जाएगा। नई व्यवस्था में डिजिलाकर और वाहन जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफार्म के साथ सहमति-आधारित एकीकरण (इंटीग्रेशन) किया गया है। इसके माध्यम से आवेदक का पता, वाहन नंबर और उससे जुड़े फास्टैग का सत्यापित विवरण स्वतः प्राप्त हो जाता है। वहीं, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) आधारित सत्यापन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक वास्तव में संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है। इससे दस्तावेजों की मैनुअल जांच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा सटीक बनती है।

- टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे के निवासियों को बड़ी राहत
- पूरे महीने असीमित बार आवाजाही कर सकेंगे स्थानीय लोग

प्रतीकात्मक

यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 'मार्गमित्र' हेल्प सेंटर लांच : एनएचएआइ ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 'मार्गमित्र' हेल्प सेंटर भी लांच किया है, जिसे राजमार्ग यात्रा एप में ही शामिल किया गया है। यह एक इंटेलिजेंस डिजिटल सहायता प्लेटफार्म है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और विभिन्न सेवाओं से जुड़ी सहायता ले सकते हैं। मार्गमित्र की खास बात यह है कि यात्री अपनी समस्या या सवाल भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में टाइप या बोलकर पूछ सकते हैं। यह प्लेटफार्म फास्टैग रिचार्ज, केवाईसी, रिफंड की स्थिति, वार्षिक और लोकल पास जैसी सेवाओं से संबंधित तुरंत जानकारी उपलब्ध कराता है। यदि किसी मामले में विभागीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो शिकायत स्वतः संबंधित विभाग तक पहुंच जाती है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की प्रगति रियल टाइम में देख सकते हैं और समाधान से असंतुष्ट होने पर अपील भी दर्ज कर सकते हैं।

सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की कर सकते हैं रिपोर्ट

इसके अलावा, मार्गमित्र के माध्यम से फास्टैग ब्लैकलिस्ट स्थिति की जांच, लंबित ई-नोटिस देखना तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर खराब वाहन, अतिक्रमण या सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों की रिपोर्ट भी की जा सकती है। एनएचएआईई ने यात्रियों से अपील की है कि वे एंड्रायड और आइओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध राजमार्ग यात्रा एप डाउनलोड कर इसकी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा अधिक सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक बन सके।

'सीमा पार बीमा कवरेज को लेकर परिपत्र जारी करने पर विचार करे इरडा'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) को सलाह दी कि वह सभी मोटर बीमा पालिसियों में सीमा पार बीमा कवरेज संबंधी प्रविधानों को एकरूप बनाने के लिए मास्टर परिपत्र जारी करने पर विचार करे। बीमा पालिसी में भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। किसी पालिसी में भारत के बाहर के क्षेत्र में भी बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाना है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में ऐसा कोई स्पष्ट कानून या नियामक स्पष्टीकरण लागू नहीं है, जो सीमा पार यात्रा के लिए बीमा पालिसी के कवरेज को स्पष्ट करता हो। इस अनिश्चितता के कारण मोटर दुर्घटना दावों के समय पर और प्रभावी निपटारे में बाधाएं आती हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक बीमा कंपनी की उस अपील पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फरवरी, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कंपनी को नेपाल में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को 32.67 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि 2010 में दुर्ग से धार्मिक यात्रा पर नेपाल जा रही एक बस पहाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें चालक सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी। अंतरदेशीय परिवहन वाहन नियम, 2021 अब भारतीय वाहनों को वैध अंतरदेशीय परमिट के तहत अन्य देशों की यात्रा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

- शीर्ष अदालत ने कहा, बीमा पालिसी में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा स्पष्ट होनी चाहिए

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 21 जुलाई, 2026

कल्पमेधा

मनुष्य को विपत्ति काल का सामना करने में सहायता देने के लिए मुस्कान से बड़ी कोई चीज नहीं है।

– संत तिरुवल्लुवर

जवाबदेही के बरक्स

दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन सोमवार को जिस रूप में पहुंच गया, उससे बचने के लिए अगर सिर्फ बातचीत का रास्ता अख्तियार किया गया होता, तो शायद यह नौबत नहीं आती। दरअसल, काकरोच जनता पार्टी ने सरकार से तीन मुख्य मांगों के साथ 'चलो संसद' का आह्वान किया था। वहां बड़ी संख्या जमा हुए युवाओं को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, बल प्रयोग किया, जिसमें कई युवाओं के घायल होने की खबर आई। इस रुख ने एक बार फिर देश की लोकतांत्रिक परंपरा और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर चोट ही पहुंचाई है। संभव है कि इस तरह की सख्ती के जरिए आंदोलनकारियों की आवाज को फिलहाल शांत कर दिया जाए, लेकिन क्या इससे वे सवाल खत्म हो जाएंगे, जिन्हें लेकर युवाओं के सामने सड़क पर उतरने की नौबत आई? अगर सरकार की मंशा आंदोलनकारियों के मुद्दों को हंगामे की शोर में दफ्न करना नहीं है, तो क्या इसके लिए वक्त पर संवाद की पहल नहीं की जानी चाहिए थी?

इससे पहले शनिवार को इसी मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस जिस तरीके से उठा कर ले गई थी, उस पर भी सवाल उठे थे। मगर उसके बाद भी सरकार ने अपनी ओर से आंदोलनकारी युवाओं की मांगों पर विचार करना या उन पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। 'चलो संसद' के आह्वान के बाद एक तरह से पहले से ही सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था कि सोमवार को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन ज्यादा जटिल स्वरूप भी अख्तियार कर सकता है। सरकार ने उन्हें रोकने के लिए जिस शिद्दत से पुलिस बल को खुला छोड़ दिया, जो निर्देश दिए, क्या उतनी ही संजीदगी से आंदोलनकारी युवाओं से बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? हालांकि हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से काकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र उन्हें सौंपा, मगर यह समझना मुश्किल है कि आखिर सरकार ने किन वजहों से इस संदर्भ में शुरू से ही उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाए रखा।

गौरतलब है कि आंदोलनकारियों की ओर से मुख्य रूप से तीन मांग की जा रही है। इसमें सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी देने और उन पर कोई कार्रवाई न करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें बर्खास्त करने तथा नीट 2026 प्रश्नपत्र लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग शामिल है। ये ऐसी मांगें हैं, जिन पर संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टि के साथ विचार करना एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए जिम्मेदारी का भी मामला होना चाहिए। विडंबना यह है कि जब शांतिपूर्ण आंदोलन का दायरा फैलने लगा और उसके सवाल तूल पकड़ने लगे, तब भी सरकार को इस समूचे मुद्दे पर परिपक्व प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं लगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और आंदोलनकारियों की बात सुनना तथा उनसे संवाद करना सरकार का लोकतांत्रिक दायित्व है। इसके बजाय आंदोलनकारी युवाओं के खिलाफ सख्ती का रास्ता चुना गया। सरकार खुद शैक्षिक सुधार के दावे करती नहीं थकती। मगर विचित्र है कि शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उसके लिए गैर-महत्त्वपूर्ण हो जाता है!

कामयाबी का खिताब

अमेरिका के न्यू जर्सी में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फीफा के फाइनल मैच के साथ ही इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय फुटबाल आयोजन अपने पीछे खट्टी-मीठी यादें छोड़ गया है। फाइनल में स्पेन ने मैदान में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में एक गोल से हराया और फीफा विश्वकप 2026 अपने नाम कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्पेन और अर्जेंटीना ने अपना पूरा दम लगा कर एक-दूसरे से मुकाबला किया। निर्धारित समय में कोई फैसला नहीं हो सका, तो इसका मतलब यही है कि मैदान में दो बराबर क्षमता की टीमें थीं और यह तय होना मुश्किल था कि कौन दूसरे पर भारी पड़ेगा। मगर अतिरिक्त समय में आखिर स्पेन ने बाजी झटक कर यह साबित किया कि एक बार फिर वह फिलहाल सर्वश्रेष्ठ टीम है। हालांकि स्पेन ने दबदबा जरूर बनाए रखा, लेकिन अर्जेंटीना ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित तौर पर फुटबाल से प्रेम करने वालों को लियोनेल मेस्सी के चमत्कारिक खेल की उम्मीद रही होगी, लेकिन फाइनल सहित पिछले कई मैचों में उनकी चमक फीकी ही रही।

दरअसल, एक खिलाड़ी की क्षमता पर ज्यादा निर्भरता किसी भी टीम के बाकी मोर्चे को सुरक्षात्मक बना दे सकती है। अर्जेंटीना के साथ शायद ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर, स्पेन के सभी खिलाड़ियों ने पूरे मैदान में हर स्तर पर अपनी ठोस मौजूदगी का एहसास कराया और वैश्विक खिताब अपने नाम किया। जाहिर है, जिस अर्जेंटीना से वैश्विक फुटबाल प्रेमियों को किसी चमत्कार की आस रही होगी, अब उसकी टीम की उम्मीदें अगले आयोजन तक के लिए आगे खिसक गईं। यह किसी भी खेल प्रतियोगिता का एक सामान्य और स्वाभाविक चक्र है। मगर अफसोस की बात है कि फीफा के मैचों में जिस तरह लगातार कई विवाद सामने आए, उसने दुनिया भर के खेलप्रेमियों को निराश किया। कुछ मैचों के दौरान कई मौकों पर खिलाड़ियों ने जिस तरह नियमों को तोड़ने की कोशिश की, कई खिलाड़ियों के बीच अप्रिय टकराव की स्थिति देखी गई रेफरी की भूमिका पर सवाल उठे, उससे प्रतियोगिता के नियम-कायदे और उन पर सख्ती से अमल को लेकर सवाल उठे हैं।

पहाड़ी राज्यों में बढ़ता पर्यटन का बोझ

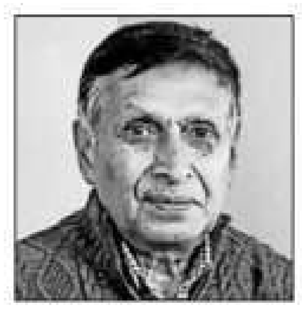

हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां तेजी बढ़ी हैं। इससे राजस्व और रोजगार के नए द्वार तो खुले हैं, लेकिन पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं।

चंद्रशेखर तिवारी

हिमालय केवल एक पर्वत-श्रृंखला नहीं है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की जल, जंगल, जैव-विविधता, संस्कृति और सभ्यता का आधार स्तंभ है। अपनी भौगोलिक विशिष्टता, लोक सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक आभा के कारण हिमालय सदियों से मानव समाज को आकर्षित करता रहा है। इसकी बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, कल-कल बहती नदियां, घने वन, प्राचीन तीर्थ स्थल और लोकस्मृतियां इसे विश्व की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहरों में स्थान दिलाती हैं। यही कारण है कि साधकों, श्रद्धालुओं, पर्वतारोहियों और प्रकृति-प्रेमियों का हिमालय के प्रति एक विशेष लगाव बना रहा है। मगर, वैश्विक ताप के असर से पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। निस्संदेह इससे राजस्व संसाधन के नए द्वार खुले हैं, लेकिन इससे पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं।

हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों का बेतहाशा विस्तार हुआ है। पर्यटन को अब विकास के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से पर्यटन के प्रचार से इन राज्यों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी, नैना देवी, चामुंडा देवी और मणिकर्ण के अलावा शिमला, डलहौजी, कुल्लू-मनाली, रोहतांग दर्रा, स्पीति घाटी और पार्वती घाटी जैसे स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इसी तरह उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और चारधाम यात्रा के अलावा औली, मसूरी, बुग्याल, हरकीदून, रूपकुंड, नैनीताल, सुंदरढूंगा, छोटा कैलाश तथा पिंडारी जैसे स्थलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। पर्यटन के ये ज्यादातर केंद्र अब केवल मौसमी गंतव्य नहीं रहे, बल्कि वर्ष भर व्यस्त रहने वाले आर्थिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में वर्ष 2025 में करीब सवा तीन करोड़ पर्यटक पहुंचे। इसी तरह, उत्तराखंड में वर्ष 2025 में रिकार्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। इस दौरान यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या छह करोड़ से अधिक रही, जिनमें 1.92 करोड़ पर्यटक विदेशी थे। इसमें से सबसे अधिक पर्यटक हरिद्वार, देहरादून और टिहरी क्षेत्रों में आए। पर्यटन के इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन ने आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए हैं। अनेक गांवों में घर पर पर्यटकों को ठहराने (होमस्टे) की संस्कृति विकसित हुई है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजनालय और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कई परिवार, जो पहले केवल पारंपरिक कृषि या सीमित आजीविका पर निर्भर थे, अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। इस दृष्टि से पर्यटन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है।

मगर इस उत्साहजनक परिदृश्य के बीच एक मूलभूत प्रश्न लगातार उभरता जा रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र विकास की वर्तमान गति और स्वरूप को वहन करने की क्षमता रखता है? यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यहां

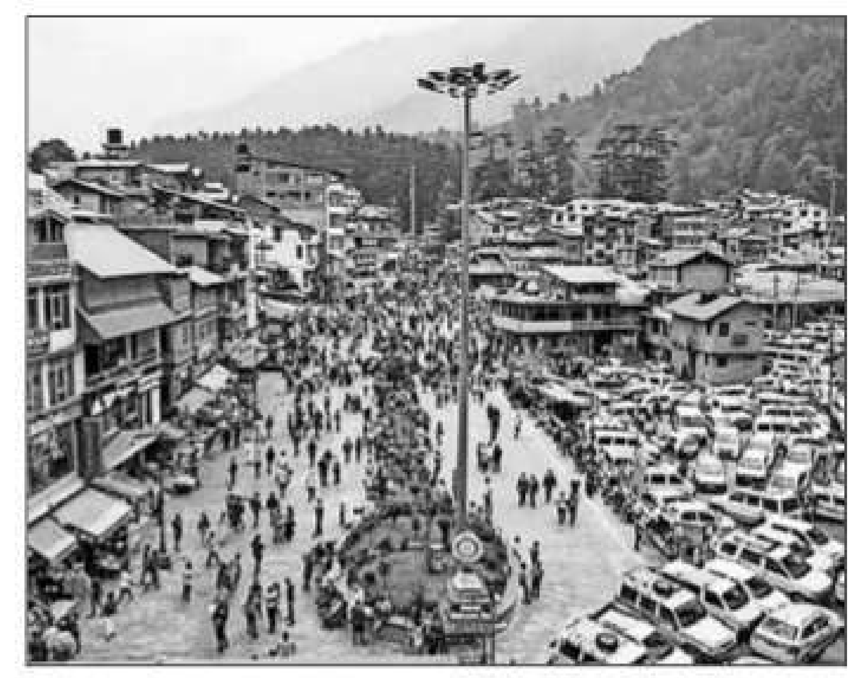

की ढलानें अपेक्षाकृत अस्थिर तथा जलस्रोत सीमित हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पिछले वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, जो ढांचागत विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यहां बार-बार होने वाले भूस्खलन और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न संकट हमें यह याद दिलाता है कि यदि

पहाड़ों की सीमित वहन क्षमता वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। कई स्थानों पर स्थानीय स्थापत्य शैली की जगह कंक्रीट आधारित निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है, निर्माण कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे न केवल इन क्षेत्रों का पारंपरिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से जल, भूमि और ऊर्जा संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के बढ़ते दबाव से यातायात और कचरे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है।

पर्यटन विकास की प्रक्रिया में स्थानीय पारिस्थितिकी की अनदेखी की जाती है, तो उसका परिणाम दीर्घकालिक संकट के रूप में सामने आ सकता है।

देश में पर्यटन विकास का मूल्यांकन प्रायः पर्यटकों की संख्या, होटल के कमरों की संख्या में वृद्धि, सड़क निर्माण और निवेश की मात्रा के आधार पर किया जाता है। यह पैमाना मैदानी क्षेत्रों में कुछ सीमा तक उपयुक्त हो सकता है, मगर हिमालयी क्षेत्रों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में वास्तविक प्रश्न यह होना चाहिए कि पर्यटन स्थानीय समाज, संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों को कितना सशक्त बना रहा है। यदि किसी क्षेत्र में पर्यटन के कारण जलस्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा हो, कचरे का संकट उत्पन्न हो रहा हो, स्थानीय स्थापत्य नष्ट हो रहा हो और सांस्कृतिक पहचान कमजोर पड़ रही हो, तो उस विकास की सफलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक पर्यटन स्थलों पर यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहाड़ों की सीमित वहन क्षमता वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो रहे हैं। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है, निर्माण कार्यों के लिए वनों को काटा जा रहा है। इससे न केवल इन क्षेत्रों का पारंपरिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से जल, भूमि और ऊर्जा संसाधनों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के बढ़ते दबाव से यातायात अव्यवस्था और कचरे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति संकेत देती है कि पर्यटन विकास की वर्तमान दिशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विशेष चिंता का विषय यह है कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास की अवधारणा अक्सर मैदानी माडल से प्रभावित दिखाई देती है। चौड़ी सड़कों, विशाल भवनों और बड़े होटल परिसरों को प्रगति का प्रतीक माना जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और पारिस्थितिक सीमाएं भिन्न हैं। हिमालय में विकास का अर्थ केवल भौतिक अवसंरचना का विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय संसाधनों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण होना चाहिए।

एक पहलू यह भी है कि यदि पर्यटन केवल प्राकृतिक दृश्यों के उपभोग तक सीमित रहेगा और स्थानीय संस्कृति को संरक्षण एवं सम्मान नहीं मिलेगा, तो वह धीरे-धीरे यह अपने ही आकर्षण के स्रोत को कमजोर कर देगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है कि पर्यटन को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जोड़ा जाए। स्थानीय स्थापत्य शैली पर आधारित होमस्टे, लोकभोजन, स्थानीय उत्पादों का विपणन, पारंपरिक कला एवं शिल्प का संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहरों का पुनर्जीवन पर्यटन नीति के अभिन्न अंग होने चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि आगंतुकों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर हिमालय की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक वहन क्षमता को केंद्र में रखा जाए।

पर्यटन योजनाओं में जलस्रोतों की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि नीति-निर्माण में स्थानीय लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वे ही क्षेत्र के भूगोल और उसकी संवेदनशीलता को सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। याद रखना होगा कि हिमालयी क्षेत्रों को यदि केवल बाजार और निवेश की भूमि के रूप में देखा जाएगा, तो उसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। तात्कालिक आर्थिक लाभ के लिए अगर हम उसकी पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक आत्मा की उपेक्षा करेंगे, तो आने वाले वर्षों में हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

व्यक्तित्व की बुनियाद

दीपिका शर्मा

हम अक्सर सुनते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा हम बोलते हैं। जैसा हम बोलते हैं, वैसा हम करते हैं। और जैसा हम करते हैं, वैसे हम बनने लगते हैं। यह कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारी सोच का हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिकता हमारे विचारों को दिशा देती है और वही विचार हमारे कार्यों तथा निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मकता, आशा और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगी, तो हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण, उत्साह और दृढ़ता का विकास होगा। ऐसे लोग चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयासरत रहते हैं।

इसके विपरीत, अगर हमारी सोच लगातार नकारात्मकता, भय या निराशा से घिरी रहे, तो उसका प्रभाव हमारे व्यवहार, निर्णयों और आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। नकारात्मक विचार हमें अवसरों को पहचानने से रोक सकते हैं और हमारी क्षमताओं पर संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि केवल सोच ही जीवन के हर परिणाम को निर्धारित नहीं करती। परिस्थितियां, अनुभव, सामाजिक वातावरण और हमारे कर्म भी उतने ही महत्त्वपूर्ण होते हैं। फिर भी, हमारी सोच इन परिस्थितियों को देखने और उनसे निपटने के तरीके को अवश्य प्रभावित करती है। इसलिए सकारात्मक, यथार्थवादी और संतुलित सोच का विकास करना व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

दुनिया मेरे आगे

माना जाता है कि व्यक्तित्व जन्म से तय होता है, लेकिन यह पूरी तरह स्थिर नहीं होता। नए अनुभव, वातावरण और प्रयासों से इसमें बदलाव आ सकता है। शिक्षा, संबंध, चुनौतियां और आत्मचिंतन व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं।

हमारी सोच और हमारे मस्तिष्क के बीच एक गहरा और अटूट संबंध है। हमारे विचार केवल मन में आने-जाने वाली प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के अनुसार, जब हम किसी विचार को बार-बार दोहराते हैं, तो मस्तिष्क में उससे संबंधित तंत्रिका मार्ग मजबूत होने लगते हैं। इसी क्षमता को 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' कहा जाता है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क नए अनुभवों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करता है।

मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बार-बार यह सोचता है कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता या स्वयं को असफल मानता है, तो ऐसी सोच उसके आत्मविश्वास और प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत, अगर वह यह विश्वास रखता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूं या मैं सीखकर इसे पूरा कर सकता हूं, तो उसका व्यवहार अधिक आत्मविश्वासी और सक्रिय हो सकता है तथा चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता बढ़ सकती है। ओशो का मानना था कि हमारे विचारों की ऊर्जा व्यापक प्रभाव डाल सकती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सकती है। चाहे इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण माना जाए या प्रेरणात्मक विचार, यह हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहने का संदेश अवश्य देता है।

दरअसल, हमारी सोच निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभाव डालती है। किसी परिस्थिति को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, तो वह इस स्थिति को दो अलग-अलग तरीकों से देख सकता है। एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि वह खुद को असफल मानकर निराश हो जाए, जबकि दूसरा दृष्टिकोण उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ने और बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार, हमारे विचार हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सकारात्मक, यथार्थवादी और रचनात्मक सोच महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल हमारी मनोदशा को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को भी आकार देती है।

मनोविज्ञान के अनुसार हमारा व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, बल्कि यह हमारी दैनिक सोच, आदतों और व्यवहारों का परिणाम होता है। अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना एक चुनौती के रूप में करता है, तो यह दृष्टिकोण धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाता है। समय के साथ यही आदत उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और वह एक जिज्ञासु, आत्मविश्वासी तथा विकासोन्मुख व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति हर असफलता में केवल अपनी कमियां खोजता है और भय या निराशा में घिर जाता है, तो उसके व्यक्तित्व में संकोच, असुरक्षा और निराशावाद जैसे अवगुण विकसित हो सकते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए यह क्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है- विचार- व्यवहार- आदत- व्यक्तित्व। अगर हम समय रहते अपने विचारों और व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो अपने व्यक्तित्व को और अधिक सशक्त तथा संतुलित बना सकते हैं। यानी आज हम जैसा सोचते हैं, वही कल हमारी आदतों और आखिकार हमारे व्यक्तित्व का आधार बन सकता है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह स्थिर नहीं होता। बल्कि नई सोच, नए अनुभव और जागरूक प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

माना जाता है कि व्यक्तित्व जन्म से तय होता है, लेकिन यह पूरी तरह स्थिर नहीं होता। नए अनुभव, वातावरण और प्रयासों से इसमें बदलाव आ सकता है। शिक्षा, संबंध, चुनौतियां और आत्मचिंतन व्यक्ति के सोचने तथा व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मसलन, भय से भरा व्यक्ति भी अभ्यास से अधिक आत्मविश्वासी और निडर बन सकता है। इसलिए व्यक्तित्व को विकसित होने वाली प्रक्रिया माना जा सकता है। अपनी आदतों और व्यवहार पर ध्यान देकर व्यक्ति इसे अधिक परिपक्व और संतुलित बना सकता है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

हताशा के बीच

देश में युवाओं के आत्महत्या करने की खबरें सामने आती रहती हैं। कोई परीक्षा में असफलता से, तो कोई अन्य परेशानी की वजह से गलत कदम उठाता है। अगर युवा हताश होकर आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाएंगे, तो यह देश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। युवाओं को चाहिए कि वे न तो किसी असफलता से निराश हों और न ही किसी अन्य कारण से हताश हों। उनको तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, देश और समाज के हित के लिए जुटना चाहिए। एक बात याद रखना चाहिए कि जिंदगी में सफलता और असफलता का दौर चलता रहता है। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, तो कई लोगों को अपने कामों में असफलता मिली है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न ही निराश हुए। उन्होंने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया और मेहनत कर सफलता हासिल की। अगर स्वतंत्रता सेनानी निराशा से घिर जाते, तो शायद वे आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेते, लेकिन वे सकारात्मक रहे और आज हम आजाद हैं।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

सुरक्षा का दायित्व

'सुरक्षा में सेंध' (संपादकीय, 17 जुलाई) पढ़ा। वर्तमान युग में किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता और परमाणु सामर्थ्य से ही निर्धारित नहीं होती। उसकी गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी क्षमता और संस्थागत सतर्कता भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। परमाणु ऊर्जा, रक्षा प्रणाली और सामरिक महत्त्व की सूचनाएं किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होती हैं। इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा में सेंध राष्ट्रहित के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। ऐसे समय में देश को अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है, ताकि संवेदनशील सूचनाओं और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

– अशोक, पटना, बिहार

गुणवत्ता की शिक्षा

भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। जिसमें छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने का दायित्व राज्यों को सौंपा गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार दस साल में करीब 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हो गए। सवाल उठता है क्या शिक्षा व्यवस्था 'वेंटिलेटर' पर आ चुकी है? इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों को एक दूसरे में मिलाने के बाद उनकी दूरी चार से पांच किलोमीटर पर हो गई है। अब प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा इतना दूर प्रतिदिन स्कूल कैसे पहुंचेगा? मेहनत-मजदूरी करने वाले अभिभावक वाहन के किराए का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? इसके साथ पढ़ाई की गुणवत्ता का भी असर पड़ा है। क्या सरकारी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है? आखिर क्या वजह हो सकती हैं?

– आलोक यादव, प्रयागराज

रेलवे की रफ्तार

भारतीय रेलवे देश की जीवनरेखा है। इसका विकास देश की आर्थिक प्रगति का आधार रहा है। शुरुआती दौर में रेलगाड़ियां कोयले वाले इंजनों से चलती थीं। इसके बाद डीजल इंजन आए, जिन्होंने रेल परिवहन को गति दी, लेकिन ईंधन आयात और प्रदूषण की चुनौती बनी रही। भारत में रेलवे का विद्युतीकरण 1925 में शुरू हुआ। वर्ष 1925 से 2014 तक लगभग 90 वर्षों में रेलवे नेटवर्क का केवल 30 फीसद ही विद्युतीकृत हो पाया था, जबकि 70 फीसद नेटवर्क डीजल इंजनों पर निर्भर था। यदि यही गति बनी रहती, तो सौ फीसद विद्युतीकरण में कई और दशक लग जाते। मगर पिछले एक दशक में अधिकतर रेल मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। वर्तमान में भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के विकास पर भी काम कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रेनें 'फ्यूल सेल' तकनीक से बिजली उत्पन्न करती हैं।

– मनीष कुमार, गोपालगंज, बिहार

जंतर-मंतर
जनसत्ता | 21 जुलाई, 2026

'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारे लगे

संसद मार्च के दौरान सोमवार को प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए, कुछ लोग काकरोच की वेशभूषा में संसद की ओर बढ़ते रहे। देश के लगभग हर हिस्से से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों में कुछ बच्चे काकरोच की वेशभूषा में थे, जबकि कई लोग महात्मा गांधी के रूप में भी नजर आए। 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्', 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' जैसे नारों से सड़कें गूंज रही थीं।

बरसती लाठियों के बीच युवक कहता रहा, और मारो

कुछ चोटें लगने के बाद, तिरंगा झंडा लिए एक महिला पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप किया और युवक को वहां से हटाने का प्रयास किया।

जनसत्ता ब्यूरो

सोमवार दोपहर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बीच, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति कई पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी उसे लाठियों से पीट रहे थे, जबकि वह बार-बार चिल्ला रहा था, 'मारो, मुझे और मारो।' उसपर कुछ लाठियां बरसने के बाद, तिरंगा पकड़े एक महिला पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप किया और उसे वहां से ले जाने का प्रयास किया।

बाद में उस व्यक्ति ने नागपुर निवासी भरत बनैत के रूप में अपनी पहचान बताई। उन्होंने बताया, 'मेरे सिर और शरीर के हर हिस्से पर चोटें आईं। लगभग 15-20 आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) अधिकारी मुझे पीट रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे शरीर के हर इंच पर मारा गया। लाठीचार्च के बाद एक प्रदर्शनकारी ने रोते हुए पुलिसकर्मी से पूछा, 'अगर आपके अपने बच्चे यहां होते, तो क्या आप तब भी ऐसा ही करते? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं?' जब सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, तो सुरक्षाकर्मियों द्वारा मार्च को रोके जाने और

उस व्यक्ति ने नागपुर निवासी भरत बनैत के रूप में अपनी पहचान बताई। भरत ने बताया, मेरे सिर और शरीर के हर हिस्से पर चोटें आईं। लगभग 15-20 आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) अधिकारी मुझे पीट रहे थे। मेरे शरीर के हर इंच पर मारा गया।

कनिष्का (16) नाम की अन्य एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वह स्कूल छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होने आई थी। उसने दावा किया कि झड़पों के दौरान वह घायल हो गई और उसका मोबाइल फोन भी टूट गया।

झड़पें शुरू होने के बाद, एक महिला प्रदर्शनकारी रोती हुई दिखी और उसने पुलिस से उसे तथा अन्य प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने देने की मिन्नत की। उसने रोते हुए कहा, कृपया हमें जाने दीजिए। क्या आपको हम पर दया नहीं आती? प्रदर्शनकारियों की भीड़ में दो दिव्यांग युवा भी शामिल थे, जिन्होंने सांकेतिक भाषा के जरिए अपनी बात रखी और साथी प्रदर्शनकारियों तथा स्वयंसेवकों का ध्यान आकर्षित किया।

कनिष्का (16) ने कहा कि वह स्कूल छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होने आई थी। उसने कहा कि झड़पों के दौरान वह घायल हो गई और उसका मोबाइल फोन भी टूट गया। अपने हाथ पर आए खरोंच के निशान दिखाते हुए उसने कहा, इन पुलिसकर्मियों के बच्चे भी भविष्य में परीक्षाएं देंगे, फिर भी वे हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ उनके माता-पिता भी शामिल हुए।

अपने छोटे बेटे के साथ जंतर-मंतर आई एक महिला ने बताया कि उसके पति पुलिस बल में कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी उसने इस प्रदर्शन में भाग लेने का फैसला किया। टकराव बढ़ने पर कुछ प्रदर्शनकारी मार्च और झड़प के दौरान बेहोश हुए लोगों को उठाते हुए देखे गए, जबकि स्वयंसेवकों ने उन्हें पानी और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया।

प्रदर्शनकारियों की भीड़ का अनुमान लगाने में चूका प्रशासन

चरमराई व्यवस्था, प्रतिबंधों के बावजूद जमा हो गया विशाल जनसमूह

राकेश शर्मा

संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ का सही आकलन कर पाने में प्रशासन की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। प्रदर्शन में 10 हजार से अधिक युवाओं के पहुंचने से नई दिल्ली क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर हो गई। जंतर-मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों से कई गुना ज्यादा भीड़ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची, जिसका अंदाजा सुरक्षा एजंसी नहीं लगा पाई थीं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे पुलिस के इंतजाम चरमरा गए।

पहले से ही यह संभावना जताई जा रही थी कि 20 जुलाई होने वाले संसद मार्च में दिल्ली और आसपास के राज्य ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से लोग इसमें भाग लेने आ सकते हैं। जंतर-मंतर और संसद भवन तक पहुंचने के लिए सभी साधनों, वैकल्पिक उपायों को अपना सकते हैं। इतना ही नहीं गुरिल्ला तरीके से भी वह संसद का घेराव कर सकते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस के अवरोधक थे। सभी रास्तों पर दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का जिक्र था। जंतर-मंतर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था, लेकिन जैसे-जैसे समय की सूई आगे बढ़ी पुलिस-प्रशासन के हड़बड़ाहट भरे निर्णय के आगे सब धरा का धरा रह गया।

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, रेल भवन, पटेल चौक और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा पूरी दिल्ली में प्रमुख मार्गों पर अवरोधक लगा दिए गए थे, ताकि

नई दिल्ली में लंबे समय बाद किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। जानकारों का कहना है कि निर्भया आंदोलन के बाद पहली बार राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव बन गया।

प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोका जा सके। पूरे नई दिल्ली क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं ठप की गई थीं और कई स्थानों पर मोबाइल डेटा सेवाएं बंद कर दी गईं। बावजूद इसके सोमवार सुबह करीब सात बजे से ही छोटे-छोटे समूहों में बड़ी संख्या में युवा जंतर-मंतर और उसके आसपास पहुंचने लगे। दोपहर तक यह भीड़ विशाल जनसमूह में बदल गई। संसद मार्ग और रेल भवन के आसपास भी हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए।

पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिबंधों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग नई दिल्ली क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी अवरोधक लांघकर संसद की तरफ जाने लगे। इसके बाद पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के लगातार बढ़ते दबाव के कारण कई स्थानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात काबू से बाहर होते देख जंतर-मंतर, रेल भवन और आसपास के क्षेत्रों में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।

नई दिल्ली में लंबे समय बाद किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। जानकारों का कहना है कि निर्भया आंदोलन के बाद पहली बार राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एक साथ सड़कों पर दिखाई दिए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव बन गया। हालांकि इस दबाव को रोकने के लिए प्रशासन ने पहले ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था।

छोटे-छोटे समूहों में युवाओं ने पांच जगह नाकेबंदी तोड़ी

गली-कूचे से होते हुए संसद की दहलीज तक पहुंचने में रहे सफल

उग्र प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग थाने के बाहर लगे अवरोधक को भी तोड़ दिया।

निर्भय कुमार पांडेय

काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के समर्थकों ने सोमवार को पुलिस की रणनीति नाकाम कर दी। छोटे-छोटे दल में बंटकर प्रदर्शनकारी गली-कूचे से होते हुए पांच नाकेबंदी (बैरिकेड्स) तोड़ते में सफल रहे। संसद की दहलीज तक पहुंच गए। पुलिस की रणनीति थी कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को संसद तक पहुंचने से रोका जाए। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने और अचानक से उग्र होने के कारण पुलिस की रणनीति धरी रह गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक नाकेबंदी को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों का धैर्य जवाब दे गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई।

सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बाद में प्रदर्शनकारियों ने अपनी रणनीति बदली और छोटे-छोटे दल के तौर पर पटेल चौक, प्रेस क्लब, संसद मार्ग, रायसिंहा रोड, परिवहन भवन, आरबीआइ होते हुए गली-कूचे से संसद भवन की दहलीज तक पहुंचे थे।

प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से मार्च शुरू करने के बाद सबसे पहले एनडीएमसी के सामने संसद मार्ग पर लगे नाकेबंदी को तोड़ा। उसके बाद वे संसद मार्ग पर पहुंचने में कामयाब रहे। उग्र प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण सुरक्षाबल के साथ एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग थाने के बाहर लगे अवरोधक को भी तोड़ दिया। तभी कुछ प्रदर्शनकारी पटेल चौक की ओर से संसद भवन की ओर मार्च शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे अवरोधक को भी तोड़ दिया। उसके बाद आरबीआइ के सामने को नाकेबंदी को तोड़े हुए प्रदर्शनकारी प्रेस क्लब तक पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं, अशोका रोड से प्रदर्शनकारियों का एक और दल पहुंचा, जिसने प्रेस क्लब के सामने लगे नाकेबंदी को तोड़ दिया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों का धैर्य जवाब दे गया और सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए।

संसद के पास सुरक्षा घेरा टूटा, अफरातफरी

जनसत्ता ब्यूरो

संसद के आसपास बना सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। इसका असर यह हुआ कि कुछ समय के लिए संसद के मुख्य द्वारा को बंद करना पड़ा और प्रवेश के लिए प्रयोग होने वाले दक्षिण व उत्तर द्वार को भी बंद कर दिया। इस वजह से संसद भवन के अंदर मंत्री, नेता से लेकर आम जनता तक फंस गई। कई नेता संसद से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से गेट बंद होने की वजह से उन्हें वापस अपने संसद कक्ष में लौटना पड़ा।

जैसे ही संसद परिसर के आसपास प्रदर्शनकारियों के आने वाली सूचना आई तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ की क्यूआरटी) मौके पर तैनात हो गए।

प्रदर्शनकारी साउथ ब्लाक की तरफ खुलने वाले गेट से आने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर इन सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। इसके अलावा मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी अंदर तैनात कर दिया था। संसद सत्र देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थी संसद में आते हैं, करीब दो बजे के आसपास ये सभी बाहर की ओर जाने के लिए परिसर में आ गए थे। लेकिन जब तक बाहर के हालात सामान्य होने के बाद ही छोड़ा गया। इसका हंगामें का असर संसद भवन के आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर भी नजर आया।

सांसद सागरिका घोष ने कहा कि सदन की कार्यवाही हर आधे घंटे में स्थगित की जा रही है। वे हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे अभी बताया गया कि गेट बंद हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। असल में, हम यहां कैदी की तरह हैं। यह साफ नहीं है कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। वे हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और उन्होंने सीजेपी प्रदर्शनकारियों को भी यहां पहुंचने से रोक दिया है। पुलिस की ओर से संसद भवन के बाहर छोड़े जा रहे आंसू गैस के गोलों की आवाजें संसद परिसर अंदर तक भी साफ सुनाई आ रही थी। बाद में संसद परिसर के गोल चक्कर का नजारा भी बदला हुआ था, वहां जगह- जगह प्रदर्शन कारियों की चप्पलें पड़ी हुई थी और पुलिसकर्मी बारिश में इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ाते नजर आ रहे थे।

पीछे नहीं रहीं महिलाएं, दिखा जोश

जनसत्ता ब्यूरो

सोमवार सुबह घर से निकलने से पहले 17 वर्षीय अंशिका ने अपने परिवार को बताया था कि वह स्कूल जा रही है, लेकिन वह परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए विरोध मार्च में शामिल होने मध्य दिल्ली पहुंच गई। संसद की ओर मार्च के दौरान, जब वह और अन्य प्रदर्शनकारी अवरोधकों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे खींच लिया।

दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली अंशिका ने अपने हाथ पर आए खरोंच के निशान दिखाते हुए कहा, हम अपने परिवारों से झूठ बोलकर यहां इसलिए नहीं आए थे कि हमें अपराधियों की तरह उठाया जाए और हिरासत में लिया जाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पैर पकड़कर

नीचे खींचा गया और दो महिला पुलिसकर्मियों ने मजबूती से पकड़ लिया।

अंशिका ने कहा कि वह न केवल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से नाराज थीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत न होने से भी आहत थीं। उन्होंने कहा, जब चुनाव का समय होता है, तो वे हमारे घरों पर आते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन नीट पर्चा लीक मामले पर बातचीत करने के लिए वे आगे भी नहीं आए। अंशिका ने सवाल किया, हम केवल बातचीत की मांग कर रहे हैं। क्या हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है?

कुछ महिला प्रदर्शनकारी तैयारी के साथ आई थीं। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, हम सब यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए थे। लेकिन हमें यह भी बताया गया था कि हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार होने की स्थिति में हमारे क्या अधिकार हैं जैसे अपने परिवार को सूचित करने का अधिकार, वकील तक पहुंच और अपने खिलाफ लगे आरोपों को जानने का अधिकार। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों की महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। इनमें से कई महिलाओं ने समूहों में दिल्ली की यात्रा की या वाट्सएप समूहों और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से अन्य प्रतिभागियों से संपर्क किया। इन नेटवर्कों ने उन्हें अपनी यात्रा के समन्वय, बैठक के स्थान तय करने और प्रदर्शन के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में रहने में मदद की।

हल्की बारिश के बीच नारे लगाती भीड़ के दिखे फौलादी हौसले

प्रियरंजन

हल्की बारिश के बीच नारे लगाती भीड़ का फौलादी हौसला दिखा जंतर-मंतर से लेकर संसद मार्ग तक। रुक-रुक कर हो रही बारिश में ढपली की थाप पर देश भक्ति गीतों और इंकलाब के नारों के साथ संसद की ओर बढ़े हजारों नौजवानों की भीड़ को जगह-जगह लगे बैरिकेड व दंगारोधी उपकरणों से लैस सुरक्षाबल नहीं रोक पाए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां बरसाईं तो प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का-मुक्का हुई और वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे।

कई जगह पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलती रही। इससे भीड़ तितर-बितर हुई। युवाओं की संसद मार्च की कोशिश को पुलिस की बहुस्तरीय रणनीति व प्रशासनिक सख्ती ने संसद के मुख्य द्वार तक पहुंचने से उन्हें नाकाम कर दिया, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए थे। काजपा के लोगों ने संसद मार्च को सफल बताया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से शांति की अपील हुई। इसमें संसद में घुसने की कोशिश न करने और लक्ष्मण रेखा ना

वर्ष 2011 में सामाजिक एवं गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन राजधानी के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। 13 दिन के अनशन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सशक्त लोकपाल कानून की मांग की गई।

2012 के निर्भया आंदोलन के दौरान हजारों छात्र, युवा पेशेवर और आम नागरिक इंडिया गेट तथा रायसीना हिल पर एकत्र हुई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लिया था।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक वर्ष तक चले आंदोलन में हजारों किसानों ने दिल्ली में प्रवेश से रोके जाने के बाद सिंघू, टीकरी और गाजीपुर सीमाओं पर डेरा डाल दिया था। यह आंदोलन तब तक जारी रहा, जब तक केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए।

लगने की अपील भी शामिल थी। दोपहर बाद करीब तीन बजने को थे, संसद के सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही थी। दो घंटे पहले तक जंतर मंतर पर मौजूद सुरक्षा बलों में से ज्यादातर को संसद भवन के बाहर चहारदीवारी के साथ तैनात कर दिया गया था।

भीड़ में महिला-बच्चों को अलावा हर वर्ग के लोगों की सहभागिता दिखी। कई राज्यों के लोगों ने इसमें शिरकत की। इसमें हाथों में तख्तियां लिए बड़ी संख्या में छात्र भी इसमें शामिल थे। भीड़ में स्कूली बच्चे, कालेज के छात्र, माता-पिता और बुजुर्ग शामिल थे। कुछ बच्चे स्कूल यूनिफार्म में आए थे, जबकि कुछ ने काकरोच की पोशाक पहनी हुई थी। कुछ ने मुखौटा लगाया था।

संसद की तरफ बढ़ती नारेबाजी करती प्रदर्शनकारियों की भीड़ को रोकने के लिए मध्य दिल्ली में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो कुछ जगहों पर लाठीचार्ज किया गया।

सुबह होते-होते जंतर मंतर सहित संसद मार्ग, कनाट प्लेस, रायसीना रोड लोगों से भर चुका था। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे और तख्तियां लिए समूहों में मार्च करते हुए और नारे लगाते हुए संसद की ओर जाने वाली सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे।

कई लोग रात भर ट्रेन और बस से यात्रा करने के बाद यहां पहुंचे थे और अपने बैग लिए घूम रहे थे, जबकि अन्य लोग बारिश से बचने के लिए छाता लेकर पैदल चल रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों की महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। इनमें से कई महिलाओं ने समूहों में दिल्ली की यात्रा की। साथ ही वाट्सएप समूहों और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से अन्य प्रतिभागियों से संपर्क किया। एक प्रदर्शनकारी पूर्वा ने बताया हम सभी ने पुणे से रात भर बस से एक साथ यात्रा की। हम एक वाट्सएप ग्रुप के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आए और फैसला किया कि दिल्ली पहुंचने के बाद हम कहां मिलेंगे। हमसे समूहों में यात्रा करने, महत्त्वपूर्ण फोन नंबर अपने पास रखने और समूह के संपर्क में रहने के लिए कहा गया था।

संसद मार्च ने कई जन आंदोलनों की याद दिलाई

काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के समर्थकों ने सोमवार को संसद की मार्च ने पिछले 15 सालों के दौरान दिल्ली में हुए उन प्रमुख जन आंदोलनों की यादें ताजा कर दी। 2021 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड उन सबसे बड़े प्रदर्शनों में शामिल थी, जिनमें प्रदर्शनकारियों ने मध्य दिल्ली की ओर कूच किया था। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चले एक वर्ष लंबे आंदोलन के तहत 26 जनवरी, 2021 को हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र होने के बाद ट्रैक्टरों के साथ राजधानी में दाखिल हुए थे।

संपादकीय

एका युगाचा अंत आणि उदय

२०२६ फिफा विश्वचषक केवळ स्पेनच्या दुसऱ्या विश्वविजेतेपदाचा साक्षीदार नाही, तर जागतिक फुटबॉलमधील एका युगाचा अंत आणि नव्या युगाच्या आरंभाचे प्रतीकही ठरला. हा इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वचषक, सहभागी ४८ देश, १०४ सामने आणि तीन यजमान देश. स्पेनने अर्जेंटिनावर १-० अशा फरकाने मात करत हा विश्वचषक जिंकला. पण हा विजय केवळ एका चषकापुरता मर्यादित नाही तर फुटबॉलच्या बदलत्या वारशाची घोषणाही आहे. फिफा विश्वचषक २०२६ने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की फुटबॉल हा केवळ एक खेळ नसून जगाला जोडणारी एक भावना आहे, जिथे प्रत्येक गोल, प्रत्येक बचाव आणि प्रत्येक अश्रू एक नवी कथा बनतो. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांचे संयुक्त यजमानपद, पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेला भव्य हाफटाइम शो आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे ही स्पर्धा आणखी खास झाली. मैदानाच्या आत आणि मैदानाबाहेरही दररोज नवा इतिहास लिहिला गेला. स्पेनने संपूर्ण स्पर्धेत ज्या शिस्तीचे, तंत्रज्ञानाचे आणि सांघिक खेळाचे प्रदर्शन केले, ते वर्षानुवर्षे लक्षात ठेवले जाईल. आठ सामन्यांमध्ये केवळ एक गोल खाणे आणि त्याच जोरावर जागतिक विजेता बनणे हा त्यांच्या मजबूत संरक्षण फळीचा पुरावाच म्हणायला हवा. कर्णधार रॉड्रीने मिडफिल्डमधून खेळाची दिशा ठरवली, तर गोलकीपर युनाई सिमोन संपूर्ण टूर्नामेंटमध्ये एक अभेद्य भिंत बनून राहिला. पाऊ कुबार्सी, एमेरिक लापोर्टे, मार्क कुकुरेला, पेड्रो पोरो, फॅबियन रुइझ, दानी ओल्मो, लामेन यामल आणि फायनलचा नायक फेरान टोरेस यांनी सिद्ध केले की, स्पेनची ताकद कोणत्याही एका सुपरस्टारमध्ये नसून संपूर्ण संघात आहे. परंतु या विश्वचषकाची सर्वात भावनिक गोष्ट म्हणजे पिढ्यांचे परिवर्तन. लिओनेल मेस्सी, ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि नेमार ज्युनिअर. या तीन महानायकांनी जवळपास दोन दशके जागतिक फुटबॉलवर राज्य केले. या विश्वचषकात त्यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला निरोप दिला. या दिग्गजांनी खेळाला एका नव्या उंचीवर नेले, परंतु प्रत्येक सुवर्ण अध्यायाचा अंत हा असतोच. फायनल सामन्यानंतर मेस्सीच्या डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रूंनीच एका युगाचा अंत आणि नव्या युगाची घोषणा केली. या विश्वचषकात अनेक उदयोन्मुख खेळाडूंनी आपली चमक जगाला दाखवली, युवा ताऱ्यांनी हे सिद्ध केले की फुटबॉलचे भविष्य उज्ज्वल आहे. छोट्या देशांच्या संघांनीही मोठ्या बलाढ्य संघांना तगडे आव्हान देऊन स्पर्धा अधिक रोमांचक बनवली. अद्भुत ड्रिबलिंग आणि परिपक्व खेळात पटाईत असलेल्या स्पेनच्या लमीन यमालने संपूर्ण स्पर्धेत आपल्या असामान्य प्रतिभेने एकच गोष्ट ठळक सांगितली, की आता जागतिक फुटबॉलचा नवा चेहरा तोच बनणार आहे. फायनलनंतर मेस्सी आणि लामेन यमालची भावनिक गळाभेट म्हणजे जणू एका पिढीने दुसऱ्या पिढीकडे वारसा सुपुर्द करण्याचाच क्षण होता. तथापि, हा विश्वचषक केवळ उत्कृष्ट फुटबॉलसाठीच नाही, तर अनेक वादांसाठीही लक्षात ठेवला जाईल. काही महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये व्हीएआरच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित झाले, अनेक संघांनी रेफरिंगच्या दर्जाबद्दल असंतोष व्यक्त केला आणि अतिरिक्त वेळेच्या (स्टॉपेज टाइम) कालावधीवरूनही वाद निर्माण झाला. खेळाडूंवर वाढणारा सामन्यांचा ताण, लांबचा प्रवास आणि तीव्र हवामानाची परिस्थिती यावरही टीका झाली. सर्वात मोठ्या विश्वचषकाच्या आयोजनाने जिथे नवे रेकॉर्ड बनवले, तिथेच हेदेखील दाखवून दिले की, स्पर्धेच्या विस्तारामुळे खेळाचा दर्जा आणि खेळाडूंचा फिटनेस यासमोरही नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. सर्वात मोठा वाद झाला तो यजमान अमेरिकेचाच. त्यांचा स्ट्रायकर फोलारिन बालोगुन मिळालेले रेड कार्ड आणि त्यानंतर त्याचे निलंबन मागे घेण्यावरून मोठा वाद उसळला. इतका की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो यांना त्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली! त्यानंतर फिफा शिस्तपालन समितीने बालोगुनच्या एका सामन्याच्या निलंबनाला स्थगिती दिली, ज्यामुळे तो पुढच्या सामन्यात खेळू शकला. मात्र राजकीय हस्तक्षेप, रेफरिंगची निष्पक्षता आणि फिफाच्या स्वायत्ततेवर या राजकीय हस्तक्षेपाने गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. युरोपियन फुटबॉल जगतातील अनेक अधिकाऱ्यांनी आणि तज्ज्ञांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत स्पर्धेच्या निष्पक्षतेविषयी चिंता व्यक्त केली. अंतिम सामन्यात तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि फिफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो यांना प्रेक्षकांच्या हूटिंगचा सामना करावा लागला. एकीकडे ही स्पर्धा जगभरात माणसांना जोडत होती, दुसरीकडे राजकीय वाद आणि मत्सराच्या अनेक पाऊलखुणाही जगासमोर उघड्या पडल्या..!

'त्या' बाळाची आई आज कुठे असेल? कशी असेल?

'त्या' रात्री वेल्हात जन्मलेले ते बाळ आज २६ वर्षांचे असेल. त्या बाळाच्या आईला तिच्या आईपेक्षा चांगले जीवन मिळाले असेल, अशी आशा करते!

व्ही. राधा
भा.प्र.से., अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, महाराष्ट्र

१९९९ साली, पुणे जिल्ह्यातील दुर्गम आणि त्यावेळी महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मागास अशा वेल्हे तालुक्याहून मी परत येत होते. त्या संध्याकाळी मी जे पाहिले, ते आजही माझ्या स्मरणातून गेलेले नाही.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून तीन जणांचे एक कुटुंब चालत येत होते. पती-पत्नी आणि त्यांची दिवस गेलेली मुलगी, कदाचित आठ महिन्यांची गरोदर. प्रसूतिवेदनांनी विव्हळणारी ती मुलगी हळूहळू चालत होती. चेहऱ्यावर प्रसूतिवेदना आणि असह्य थकवा.

मी माझी गाडी थांबवली. त्यावेळी मी जिल्हा परिषदेची मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे माझ्या कार्यक्षेत्रात येत होती. प्रसूतीच्या अवस्थेत असलेल्या एका तरुणीला शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून परत पाठवले जात असल्याचे पाहून धक्का बसला. विचारणा केल्यावर तेथील परिचारिकेने शांतपणे खरे काय ते सांगितले. मुलगी सोळा वर्षांपेक्षाही लहान, गंभीर रक्तक्षयाने ग्रस्त आणि शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती करावी लागणार होती. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर उपलब्ध नसताना तिथे त्या मुलीची प्रसूती करणे आई आणि बाळ दोघांसाठीही धोकादायक ठरू शकले असते. मी निरुत्तर झाले.

तेवढ्यात आई-वडिलांनी रस्त्यावरून जाणारा एक वाळूचा ट्रक हात दाखवून थांबवला. धुळीने माखलेला आणि हेलकावे घेणारा उघडा ट्रक. उपलब्ध असलेले तेच एकमेव वाहन.

मला खरे तर स्वतःची लाज वाटली. मी त्या मुलीला आणि तिच्या आई-वडिलांना माझ्या गाडीत बसण्याची विनंती केली आणि ड्रायव्हरला जवळच्या ग्रामीण रुग्णालयात शक्य तितक्या वेगाने पोहोचण्यास सांगितले. ते जवळपास पन्नास किलोमीटर दूर होते. चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आणि एक लाखाहून अधिक लोकसंख्येला सेवा देणारी एक संदर्भ सुविधा म्हणजे ग्रामीण रुग्णालय. येथे आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी अधिक सुसज्ज सुविधा असतात.

माझ्या स्वतःच्या बाळाच्या जन्माच्या वेळी अनुभवली होती, त्याच तीव्र व्याकुळतेने मी प्रार्थना करत होते. त्या बाळाने थोडा धीर धरावा, थोड्या वेळाने जन्म घ्यावा आणि हा पन्नास किलोमीटरचा प्रवास लवकर संपावा! संध्याकाळी साडेआठच्या सुमारास आम्ही रुग्णालयात पोहोचलो. सुदैवाने, तिथे डॉक्टर हजर होते.

मध्यरात्रीनंतर एका नवजात बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला, तीव्र, संतप्त असा आक्रोश. जगावर संतापलेला; पण अनभिज्ञ असा.. बाळ सुखरूप जन्माला आलं या विचाराने मला शांत वाटलं; पण अस्वस्थता संपली नाही. ती किशोरवयीन तरुण आई एका स्थलांतरित मजुराची मुलगी होती.

२०११च्या जनगणनेनुसार, ४५० दशलक्षाहून अधिक भारतीय आपला मूळ गाव सोडून दूर राहतात. ही जगातील सर्वांत मोठी स्थलांतरितांची लोकसंख्या आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधील वीटभट्टी कामगार, ओडिशा, झारखंड आणि छत्तीसगडमधील बांधकाम कामगार, गुजरातमधील मिठागर मजूर, प. बंगालमधील तांदूळ गिरणी कामगार, तसेच मराठवाड्यातील ऊसतोड मजूर, असे असंख्य लोक रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी आपली गावे सोडतात.

एखादे कुटुंब स्थलांतराची तयारी करते, तेव्हा घरातील किशोरवयीन मुलगी ही एक चिंता बनते. तिला घरी एकटी ठेवता येत नाही. तिला मजुरांच्या तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये घेऊन जाणेही सुरक्षित वाटत नाही. मग तिचे लग्न लावून देण्याचाच पर्याय उरत नाही. या मुली अनेकदा वयाशी आलेल्या नसतात; पण समोर दुसरा पर्याय दिसत नसल्यामुळे स्थलांतरण करण्यापूर्वीच मुलीच्या 'सुरक्षिततेसाठी' म्हणून हा निर्णय घेतला जातो.

'त्या' किशोरवयीन मुलींचे प्राक्तन आपोआपच ठरते. बालवयात लग्न झाल्याने शाळा सुटते, शारीरिक परिपक्वता येण्याआधीच ती गर्भवती होते आणि सासरी जेवणाच्या पंगतीत सर्वांत शेवटी जेवल्यामुळे ती रक्तक्षयाची (ॲनिमिया) शिकार होते.

वयाच्या सोळाव्या वर्षी प्रसूतिकळा सुरू असताना ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचते, तेव्हा तिच्या आयुष्याशी संबंधित सर्व निर्णय आधीच घेतलेले असतात. अशा वेळी 'शासन व्यवस्था' ही तिला निराश करणारी केवळ शेवटची ठरते.

१९९९ मध्ये प्रशासकीय सेवेतल्या पहिल्या नियुक्तीपासून ते आजपर्यंतच्या प्रवासात आकडेवारी समोर आली, की मला ती मुलगी आठवते. महाराष्ट्राने २० ते २४ वयोगटातील आणि १८ वर्षांच्या आधी विवाह झालेल्या महिलांचे १९९८-९९च्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणातले (NFHS-2) प्रमाण ५८.७% वरून २०२३-२४ मध्ये (NFHS-6) १९.७% पर्यंत खाली आणले आहे; म्हणजेच गेल्या २५ वर्षांत यात ३९ टक्के घट झाली आहे.

यातील काहीही योगायोगाने घडलेले नाही. दीड शतकाहून अधिक काळापूर्वी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या समाजसुधारकांनी या प्रथेविरोधात आवाज उठवला होता. १८९१ मध्ये 'संमती वय कायदा' करण्यात आला. पुढे २००६ मधील 'बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'ने मुलींसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वर्षे निश्चित केले आणि बालविवाहाविरुद्धच्या संरक्षणात्मक कायदेशीर तरतुदी अधिक बळकट झाल्या. या चळवळीत प्रत्येक पिढीने आपली भर घातली. मात्र, अजूनही खूप मोठा पल्ला गाठायचा बाकी आहे.

त्या रात्री वेल्हात जन्मलेले ते बाळ आज साधारणपणे सव्वीस वर्षांचे असेल. त्याची आई आज कुठे आहे, तिचे आयुष्य कसे घडले, हे मला माहीत नाही; पण तिला तिच्या आईपेक्षा अधिक चांगले आयुष्य जगायला मिळाले असेल, अशी आशा मात्र आहे!

अन्वयार्थ

उपोषणकर्त्यांना सरकार सक्तीने अन्न-औषधे देऊ शकते का?

उपोषण हा निषेधाचा मार्ग असू शकतो; पण तो जीवन नाकारण्याचा अधिकार ठरत नाही, असे आपल्या न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी जंतर-मंतरवरून रुग्णालयात हलवले. 'ही जबरदस्ती आहे' असे समर्थक आंदोलनकर्ते म्हणतात, तर सरकार म्हणते, 'हे जीव वाचवण्यासाठी उचललेले पाऊल!' हायकोर्टाने सरकारची भूमिका योग्य ठरवली. या घटनेमुळे महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला - उपोषणाचा अधिकार कुठपर्यंत आहे? जीव धोक्यात आला तर राज्याने काय करायचे?

उपोषण हा भारताच्या लोकशाही संस्कृतीचा भाग राहिला आहे. महात्मा गांधींनी उपोषणाला नैतिक शक्ती दिली. गांधींपाठोपाठ अनेकांनी हा मार्ग स्वीकारला. भगतसिंग यांनी तुरुंगातील राजकीय कैद्यांना मानवी वागणूक मिळावी म्हणून ११६ दिवसांचे उपोषण केले होते. जतीन दास यांनी ६३ दिवसांच्या उपोषणानंतर लाहोर तुरुंगात प्राण सोडले.

स्वातंत्र्यानंतरही उपोषणाची परंपरा थांबली नाही. स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या निर्मितीसाठी पोट्टी श्रीरामुलू यांचा ५८ दिवस उपोषणानंतर मृत्यू झाला. त्यांच्या बलिदानानंतरच आंध्र राज्याची निर्मिती झाली.

यानंतरच्या काळात अण्णा हजारे यांचे १३ दिवसांचे उपोषण, विस्थापितांच्या प्रश्नावर मेधा पाटकरांचे, अवैध खाणकामाविरोधात स्वामी निगमानंद यांचे, तसेच काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर बाबा रामदेव यांचे उपोषण देशाने पाहिले.

या सर्वांमध्ये सर्वात वेगळे आणि विलक्षण नाव आहे आयरोम चानू शर्मिला यांचे. मणिपूरमध्ये सैन्याच्या गोळीबारात झालेल्या दहा नागरिकांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी २ नोव्हेंबर २००० रोजी सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कायदा रद्द करण्यासाठी उपोषण सुरू केले. चारच दिवसांत त्यांना 'आत्महत्येचा प्रयत्न केल्या'च्या आरोपावरून अटक करून रुग्णालयात नाकावाटे नळीतून कृत्रिम आहार देण्यात आला. या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त शिक्षा १ वर्षापर्यंत असल्याने प्रत्येक वर्षी सुटका व पुन्हा अटक व्हायची. जवळपास सोळा वर्षे चाललेले हे उपोषण जगाच्या

इतिहासात अभूतपूर्व मानले जाते. उपोषणाला नैतिक आणि राजकीय महत्त्व असले तरी कायदा त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतो. प्रश्न केवळ आंदोलनाचा नाही, तर जीवनाच्या अधिकाराचाही आहे.

राज्यघटनेत 'उपोषणाचा' असा स्वतंत्र मूलभूत अधिकार नसला तरी मत मांडण्याचा आणि आंदोलनाचा अधिकार आहे (अनुच्छेद १९). उपोषण हे निषेध व्यक्त करण्याचे मान्य साधन मानले जाते, तरीही हा अधिकार पूर्णपणे अमर्यादित नाही. उपोषणामुळे जीव धोक्यात येऊ लागला, तर अनुच्छेद २१ पुढे येते. हे व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार देते. म्हणजेच राज्याने माणसाचा जीव वाचवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच डॉक्टरांनी उपोषणकर्त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले, तर सरकार त्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करू शकते, उपचार आणि कृत्रिमरीतीने आहारही देऊ शकते.

अशी कारवाई आंदोलन मोडण्यासाठी नसून जीव वाचवण्यासाठी असते. त्यामुळे उपोषणाचा अधिकार आणि जीवनाचा अधिकार यांच्यातील समतोल राखणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य ठरते.

'ग्यान कौर विरुद्ध पंजाब' खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने जगण्याच्या अधिकारात मरण्याचा अधिकार समाविष्ट नसल्याचे स्पष्ट केले. यातून व्यक्तीचा स्वतःच्या शरीरावर अधिकार असला, तरी तो अधिकार जीवन संपवण्यापर्यंत विस्तारत नाही. त्यामुळे उपोषण निषेधाचा मार्ग असू शकतो; पण तो जीवन नाकारण्याचा अधिकार ठरत नाही. भारतीय न्याय संहितेत आत्महत्येच्या प्रयत्नाचे जुने ३०९ कलम रद्द झाले. त्यामुळे उपोषण करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होत नाही. पण यामुळे सरकारची जीव वाचवण्याची जबाबदारी कमी होत नाही.

तुरुंगात मात्र नियम थोडे वेगळे आहेत. तुरुंगात उपोषणार्थी कैद्याला आधी समज दिली जाते. तरीही तो अन्न घेण्यास नकार देत राहिला, तर कैद्याला वैद्यकीय निरीक्षणात ठेवले जाते. त्याचा जीव धोक्यात आला, तर जबरदस्तीने आहार देण्याची तरतूद तुरुंग मॅन्युअलमध्ये आहे. उपोषण भारतीय लोकशाहीतील प्रभावी निषेधाचा मार्ग आहे; परंतु तो कोणत्याही परिस्थितीत जीवनाच्या अधिकारावर मात करू शकत नाही. म्हणजेच जीव वाचवण्यासाठी केलेली कारवाई दडपशाही नसून घटनात्मक कर्तव्य असते. शेवटी भारतीय कायदा जीवनाचे संरक्षण हेच अंतिम, सर्वोच्च आणि अपरिहार्य घटनात्मक मूल्य मानतो.

जगभर

राजकुमाराच्या प्रेमात तरुणींनी गमावलं सर्वस्व!

शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम. दुबईचे ते क्राऊन प्रिन्स आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री म्हणूनही ते जबाबदारी सांभाळतात. ही झाली त्यांची अधिकृत ओळख; पण घोडेस्वारी, स्कायडायव्हिंग, गिर्यारोहण, इतर साहसी खेळ, एवढंच नाही, फोटोग्राफी आणि कवितेचेही ते शौकीन आहेत. 'फज्जा' या टोपणनावानं ते कविता लिहितात. इन्स्टाग्रामवर त्यांचे १.७ कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तरुणाई, विशेषत: तरुणी त्यांच्या प्रेमात आहेत.

याच दुबईच्या क्राऊन प्रिन्स यांचा फिलिपिन्सच्या मारियाला एक दिवस व्हिडीओ कॉल आला. दोघांनी थोडा वेळ गप्पा मारल्या. नंतर त्यांचं सतत ऑनलाइन चॅटिंग सुरू झालं. थेट दुबईचा क्राऊन प्रिन्स आपल्याशी बोलतो, स्वत:हून फोन करतो, प्रेमाच्या गप्पा मारतो, हे पाहून मारियाही भारावली.

पण, असे व्हिडीओ कॉल आणि मेसेजेस येणारी मारिया एकटीच होती का? - जगभरात अशा अनेक तरुणी होत्या, ज्यांना क्राऊन प्रिन्सचे फोन यायचे, त्याही भारावून जायच्या आणि त्याच्या प्रेमात पडायच्या. तो सांगेल तसं करायच्या. आपण दुबईच्या राजघराण्यात जाणार या मोहात, त्या आनंदात आणि प्रिन्सला खुश करण्याच्या नादात त्यांनी किती पैसा खर्च केला, किती जणी कंगाल, कफल्लक झाल्या, हे त्यांचं त्यांनाच माहीत!

पण, हा खराखुरा दुबईचा क्राऊन प्रिन्स होता का? - अर्थातच नाही. दुबईच्या राजकुमाराचं डीपफेक तयार करून सायबर भामटेच या तरुणींना जाळ्यात ओढत होते. या माध्यमातून अनेक तरुणींना त्यांनी अक्षरश: कफल्लक केलं!

ग्लोबल अँटि-स्कॅम अलायन्सच्या अंदाजानुसार, गेल्यावर्षी जगभरात फसवणुकीमुळे अनेकांचं सुमारे ४४२ अब्ज डॉलर इतकं नुकसान झालं. यामध्ये प्रेमसंबंधांच्या नावाखाली होणाऱ्या ऑनलाइन फसवणुकीचा मोठा समावेश आहे.

दुबईच्या राजकुमारासह अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींची डीपफेक (कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं तयार केलेली बनावट प्रतिमा किंवा व्हिडीओ) तयार करून भामटे लोकांना गंडा घालत आहेत. दुबईच्या राजकुमाराचं आकर्षक हास्य, थेट व्हिडीओ कॉलदरम्यान त्यानं व्यक्त केलेलं प्रेम आणि आपुलकी यामुळे अनेक तरुणी भारावल्या आणि फसवणुकीच्या बळी ठरल्या.

मारिया सांगते, राजकुमाराच्या प्रेमात मी इतकी वेडी झाले की, आपली फसवणूक होत असल्याचा मला जरासुद्धा संशय आला नाही. या फसवणुकीत माझ्या वर्षभराच्या बचतीवर पाणी फेरलं. भामट्यानं तिला फसवून १,००,००० पेसो, म्हणजेच सुमारे १६२५ डॉलर भरायला लावले. हे पैसे विवाह प्रमाणपत्र आणि 'रॉयल मेंबरशिप कार्ड' मिळवण्यासाठी असल्याचं तिला सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे दुबईत जाणं, तिथे गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळणं आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे राजकुमाराशी प्रत्यक्ष भेटीगाठी होणं. या सगळ्याच गोष्टी अतिशय सहज आणि सोप्या होतील, असं आमिष तिला दाखवण्यात आलं.

यानंतर त्या भामट्यानं एका हॉटेलमध्ये भेटण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि हॉटेल आरक्षणासाठी आणखी ६०,००० पेसो म्हणजेच सुमारे ९७४ डॉलर मागितले, तेव्हा मारियाला संशय आला. तपासात हे फेसबुक अकाउंट नायजेरियातून चालवलं जात असल्याचं तिच्या लक्षात आलं.

लोकांचा विश्वास बसावा, यासाठी सोशल मीडियावर अगदी खरी वाटणारी छायाचित्रं प्रसिद्ध केली जातात. एका छायाचित्रात राजकुमार एका गुडघ्यावर बसून अंगठी देताना दिसतात, तर दुसऱ्या छायाचित्रात ते लाल गुलाब देताना दिसतात. त्यासोबत, 'स्विटहार्ट, मला व्हॉट्सॲपवर 'आय लव्ह यू' म्हणशील का?' यासारखा मजकूर! प्रेमाच्या याच जाळ्यात जगभरात तरुणी गंडवल्या गेल्या.

जनमन

आमिषाच्या योजना राबविल्या जाऊ नयेत

२८ जून २०२४ ला महाराष्ट्र शासनाची 'लाडकी बहीण' योजना कल्याणकारी योजनांच्या निधीत कपात करून सुरू झाली आणि त्याचा फायदा जवळजवळ २ कोटी ४० लाख महिलांनी उत्पन्नाचे खोटे दाखले, बोगस आधार कार्ड दाखवून घेतला. अगदी सरकारी नोकरदारांच्या नातेवाइकांनीसुद्धा. हे पैसे सरकार कसे वसूल करणार? आधार लिंक, प्राप्तिकर माहिती किंवा रेशन कार्ड प्रणाली बघून ही योजना अंमलात आणणे जरुरीचे होते. तसे न होता अगदी जलद गतीने या योजनेची अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतील जवळजवळ १४ ते १५ हजार कोटी लाभार्थींनी लुटले, असेच म्हणावे लागेल. आता पडताळणी करून अंदाजे एक कोटी महिला अपात्र ठरवून गेलेली रक्कम परत कशी मिळवणार? त्यासाठीसुद्धा उपाययोजना व कडक कारवाई राज्य सरकारने करण्याची गरज आहे. कारण तो पैसा सामान्यांच्या करप्रणालीतून गेला आहे. सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा पैसा असा वाया जाणार असेल तर त्याला काय अर्थ आहे? याच पैशाचा आणखी चांगल्या कामासाठी विनियोग करता आला असता. इतर राज्यांतही काही योजना राबिवल्या गेल्या.

गरजूंसाठी कल्याणकारी योजना राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या अत्यंत कटाक्षाने राबवल्या गेल्याच पाहिजेत. पण, त्याचवेळी त्या व्यवहार्य आहेत का, त्यात काही त्रुटी तर राहिलेल्या नाहीत ना, योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत जातो आहे ना, याचीही काटेकोर काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यात पारदर्शीपणा असणेही तितकेच गरजेचे आहे. आमिषाच्या कोणत्याही योजना सरकारने राबवू नयेत, हीच अपेक्षा आहे. नाहीतर लोकांनाही त्याची सवय लागते.

- अमोल करकरे, खेड-रत्नागिरी

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

शहर नोंदी

शहरीकरण होतंय की जंगलचा कायदा पुन्हा अवतरतोय..!

सगळ्यांनी मिळून नियमसंच ठरवणं आणि मग कोणत्याही थेट शिक्षेच्या धाकाशिवाय ते पाळणं हीच नागर सभ्यता आणि तोच नागर समाज.

मेघना भुस्कुटे
ब्लॉगर, भाषांतरकार

परदेशात मित्राच्या गाडीतून भटकत असतानाचा हा किस्सा. चौकात एक सर्कल होतं. मित्र सर्कलच्या अलीकडे थांबला. दोन्ही बाजूंनी जाणाऱ्या गाड्यांचा अंदाज घेतला. लोकांना जाऊ दिलं. मगच गाडी पुढे गेली. सगळ्यांत चांगली तीनेक मिनिटं गेली.

आमची गाडी पुढे जात असताना डावीकडच्या रस्त्यावरची एक गाडी आमच्यासारखीच शांतपणे थांबलेली. ते बघताना कौतुक वाटलं. पण मग मनात आलं, मी भारतातल्या एखाद्या शहरात- उदा. बेंगळुरूमध्ये जर अशाप्रकारे थांबले तर पुढचे दोनेक तास बहुधा तिथेच थांबून राहावं लागेल. तिथे आक्रमकपणा दाखवला नाही, तर मला टिकावच धरता येणार नाही. अशा परिस्थितीत बेशिस्त आणि आक्रमक रहदारीच्या वर्तनाला दोष कसा द्यावा, या प्रश्नाचं उत्तर समजून घ्यायला आपल्याला नागरी वर्तनाच्या व्याख्येकडे जावं लागेल. एखादा नियम किंवा सामाजिक सभ्यतेचा संकेत पाळला गेला पाहिजे, असं सगळ्या लोकांना वाटत असेल, तरच तो पाळला जाण्याची शक्यता वाढते. निव्वळ दंडुक्याच्या धाकानं सगळ्यांना त्याचं पालन करायला लावणं जवळजवळ अशक्यच असतं.

सगळ्यांनी मिळून नियमसंच ठरवणं आणि मग ते सगळ्यांनी मिळून, कोणत्याही थेट शिक्षेच्या धाकाशिवाय पाळणं, म्हणजे काय? - त्यालाच तर नागर सभ्यता म्हणतात! हे का करायचं? कारण ते आपल्या फायद्याचं आहे म्हणून. ही जाणीव ज्या समाजाच्या हाडीमाशी भिनलेली, रुजलेली असते, तो

नागर समाज. कोविड काळात मुंबईमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी लोक मास्क बांधूनच वावरायचे. कुणी मास्क घातला नसेल, तर हटकायला पुरेसं मनुष्यबळ नव्हतंच. शिवाय, इतर अनेक ठिकाणी लोक बिनदिक्कत विनामास्क फिरायचे हे आपण अनुभवलेलंच आहे. पण मुंबईत निदान दुसऱ्या लाटेदरम्यान तरी सहसा असं दिसलं नाही. शहरं अशाप्रकारे स्वयंशिस्त पाळतात, किंबहुना जे समाज अशी शिस्त पाळतात, तेच नागर असतात.

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न टाकणं, फिरत्या जिन्यावर डाव्या बाजूची जागा चढून जाणाऱ्यांसाठी मोकळी ठेवणं, मोठ्या आवाजात संगीत लावून वा पार्ट्या करून शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना त्रास न देणं, रस्त्यांवर आडवंतिडवं पार्किंग न करता सुरळीत रहदारीला जागा ठेवणं, सार्वजनिक अवकाशात पचापच न थुंकणं, फुटपाथवरून दुचाक्या न दामटणं, खासगी कार्यक्रमांचे मांडव रस्त्यांवर न ठोकणं.. फार काय, भेटीगाठींची आणि कार्यक्रमांची ठरलेली वेळ पाळणं, त्यातून इतरांच्या वेळेची आणि अवकाशाची बूज राखणं हेही या नागरी जाणिवेतच मोडतं. सार्वजनिक अवकाश आणि शांतता यावर सगळ्यांचा हक्क आहे, या हक्काची कदर केली तर(च) आपल्यालाही त्याचा फायदा होईल याचं भान ज्याला आहे, तो नागर समाज. मग हा समाज शहरात राहणारा असो, वा गावात राहणारा असो. गावच्या जत्रेत वेडंवाकडं वागणाऱ्या एखाद्या मवाल्यावर डाफरणारे गावचे वृद्ध पाटील हे नागर भानच रुजवत असतात. आपल्यातलं हे नागर भान संपून गेलं असेल, तर आपलं शहरीकरण होतंय म्हणायचं की जंगलचा कायदा पुन्हा अवतरतोय म्हणायचं?

meghana.bhuskute@gmail.com

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८९८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

प्रेरणा

प्यार के बिना जीवन उस वृक्ष की तरह है जिस पर कभी फल नहीं लगते। –खलील जिब्रान

संपादकीय

विचारों में टकराव से समाज की सोच बाधित ही होती है

देश की सोच दो विरोधी विचारधाराओं में बंटती जा रही है। जो एक विचारधारा और उसके प्रतीकों को नहीं मानता, उसे इस विचारधारा को मानने वाले स्वतः विरोधी खेमे का मान लेते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि संभव है वह व्यक्ति दोनों को अपनी सोच के अनुसार समय-समय पर सही या गलत मानता हो या अपने विवेक से लेकिन बिना पूर्वाग्रह के फैसले करता हो। पर लगता है अब बीच का मार्ग नहीं बचा है। ऐसे में अगर कोई सोशल मीडिया यूजर किसी एक पक्ष की खबरें ज्यादा और कई बार देखता है, तो एआई एल्गोरिदम चिह्नित कर उसे बार-बार उसी प्रकृति की खबरें भेजने लगती है। प्रजातंत्र जनमत से चलता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि यह जनमत स्वस्थ, तार्किक, पूर्वाग्रह-शून्य और वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकी लाभांश के काल में है। इसका यह भी अर्थ है कि आज देश के युवाओं के कंधों पर बढ़ते बुजुर्गों का भार है। एआई, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो चिप्स और मैक-5 (ध्वनि से पांच गुना तेज गति) और चांद पर घर बनाने की अभिलाषा का दौर है। ऐसे में वैचारिक द्वंद्व अगर समाज की सोच और गति को बाधित करता है तो वह अंततः एक ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पीढ़ियों तक भरपाई नहीं हो सकेगी। समाज के सही और तार्किक सोच वाले लोगों को आगे आना होगा।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

माताएं-बहनें जहां काम करती हैं, आंगन-सा माहौल बन जाता है

भारत में आंगन पारिवारिक सामूहिकता का प्रतीक है। साहित्यकारों ने तो आंगन को नारियों की दुनिया कहा है। तुलसी तो आंगन की महारानी है ही। कुछ ऋषियों ने मन को भी आंगन का रूपक दिया है। तुलसीदास जी लिखते हैं- बरनि न जाइ रुचिर अँगनाइ, जहँ खेलहिं नित चारिउ भाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। यह बात काकभुशुंडि जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। श्रीराम का आंगन में खेलना तुलसीदास जी को अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए उन्होंने वह चौपाई लिखी थी- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी। हे दशरथ के आंगन में विहार करने वाले राम जी, आप हमारे आंगन में भी पधारें। महिलाओं की उपस्थिति से कार्यस्थल की संस्कृति भी बदल जाती है। माताएं-बहनें जहां काम करती हैं, आंगन-सा माहौल बन जाता है। पर भारत के कार्यबल में पुरुषों के मुकाबले 10% ही महिलाएं हैं। आंगन से प्रेरित होकर हम संकल्प लें कि देश में महिला वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • याद रहेगा 2026 का फीफा विश्व कप...

यह नए चेहरों और छोटे लेकिन जुझारू देशों का टूर्नामेंट था

फुटबॉल

बोरिया मजुमदार
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के सहलेखक और खेल पत्रकार

फीफा विश्व कप की शुरुआत विवादों के साथ हुई थी। ईरानी खिलाड़ियों को वीसा मिलेगा या नहीं, यह मसला सुर्खियों में रहा। उनके साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भी अनेक सवाल खड़े किए। रेफरियों के निर्णय किस तरह एक टीम (अर्जेंटीना) के पक्ष में जा रहे थे, यह भी चर्चा का विषय बना। बालोगुन विवाद को लेकर ट्रम्प भी इसमें शामिल हो गए और ट्रम्प तथा फीफा प्रेसिडेंट इन्फैन्तीनो के बीच हुई बातचीत को लेकर भी काफी चर्चा हुई। वीएआर प्रणाली लगातार बहस का विषय बनी रही। इसमें तीनों आयोजक देशों के बीच यात्राओं से जुड़ी समस्याओं और उस पर आने वाले भारी-भरकम खर्च को भी जोड़ दें। लेकिन इसके सबके बावजूद विश्व कप को असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें फुटबॉल का स्तर और मुकाबलों की इंटेंसिटी दोनों ही सर्वोच्च दर्जे के रहे थे।

फाइनल मैच भले ही स्पेन के पक्ष में पूरी तरह से एकतरफा रहा हो, लेकिन उसके विपरीत इस विश्व कप में कई ऐसे क्लासिक मुकाबले हुए, जो लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में बने रहेंगे। चाहे फ्रांस के खिलाफ स्पेन का शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन हो या इंग्लैंड के विरुद्ध अर्जेंटीना की दमदार वापसी- यह टूर्नामेंट रोमांच से भरपूर रहा। सेमीफाइनल का ही उदाहरण लीजिए, जिसकी चर्चा अब भी लंदन में हो रही है। इंग्लैंड 1-0 से आगे था और पूरे ब्रिटेन ने सपना देखना शुरू कर दिया था कि ट्रॉफी आखिरकार घर लौटने वाली है। तभी उनके कोच ने रक्षात्मक रणनीति अपनाने की गलती कर दी और 39 वर्षीय मेसी को जैसे नया जीवन मिल गया। अर्जेंटीना ऐसी टीम की तरह खेलने लगी, मानो उस पर जुनून सवार हो। इंग्लैंड बिखर गया और अटलांटा के विशाल स्टेडियम में अर्जेंटीनी समर्थकों की आवाज गूंजने लगी। उस समय मैं लंदन के एक पब में मौजूद था, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था।

पलभर को अफ्रीका के बारे में सोचिए। इस महाद्वीप की ओर से पहली बार इस टूर्नामेंट में नौ टीमें उतरी थीं और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। चाहे केप वर्डे की वह प्रेरक कहानी हो- जिसमें पांच लाख की आबादी वाले इस देश ने अर्जेंटीना को हार के कगार तक पहुंचा दिया, या मिस्र- जो अंत तक 2-0 से आगे रहने के बावजूद आखिरकार 2-3 से हार गया- अफ्रीकी टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। मोरक्को ने अब एक नया मानक स्थापित कर दिया है। कतर विश्व कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद इस विश्व कप में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर उसने अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अफ्रीकी खिलाड़ियों को दुनिया की प्रमुख लीगों में निश्चित रूप से अधिक अवसर मिलेंगे और इस विश्व कप से उनके लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी की बात करें। पहले दो मामलों में यह देखना अद्भुत था कि दोनों सितारों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए सब कुछ झोंक दिया। रोनाल्डो ने पुर्तगाल को आगे ले जाने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता की सीमाएं लांघ दीं, लेकिन अंततः स्पेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हार गए। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद आंसुओं के साथ विश्व कप से विदा लेते रोनाल्डो यह बताते हैं कि खेल कई बार कितना निर्मम हो सकता है। नेमार ने भी अपने प्रशंसकों के लिए ब्राजील के अंतिम मैच में एक पेनल्टी गोल किया, लेकिन उनकी विदाई वैसी नहीं रही, जैसी किसी दिग्गज खिलाड़ी के साथ अपेक्षा की जाती है। लेकिन यही खेल है। और जहां तक मेसी की बात है तो बहस समाप्त हो चुकी है। हर सवाल का जवाब मिल चुका है। हर आलोचक निरुत्तर है। जिस तरह उन्होंने खेला और अर्जेंटीना का नेतृत्व किया, फाइनल में हार के बावजूद उन्होंने स्वयं को सर्वकालिक महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है।

यह एक शानदार विश्व कप रहा। तमाम विवादों के बावजूद मैदान पर देखने को मिला फुटबॉल हर प्रशंसक की उम्मीदों पर खरा उतरा। और जिस तरह का जुनून प्रशंसकों में देखने को मिला, वह इस बात का प्रमाण है कि फुटबॉल दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल क्यों है।

यह एक शानदार विश्व कप रहा। तमाम विवादों के बावजूद मैदान पर देखने को मिला फुटबॉल हर प्रशंसक की उम्मीदों पर खरा उतरा। और जिस तरह का जुनून प्रशंसकों में देखने को मिला, वह इस बात का प्रमाण है कि फुटबॉल दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल क्यों है।

हम बार-बार यह शिकायत सुनते रहे हैं कि 1.4 अरब की आबादी वाला देश होने के बावजूद हम विश्वस्तरीय फुटबॉलर क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) और पीआईओ (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) खिलाड़ियों का उपयोग करें, तो हम भी विश्व कप में जगह बना सकते हैं। तब हम अपनी टीम के बारे में भी लिख रहे होंगे। फिलहाल तो स्पेनिश आर्माडा का ही दबदबा है। नेतृत्व की मशाल मेसी से लमीन यमाल के हाथों में पहुंच चुकी है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

दूरदृष्टि • एक्ट-ईस्ट 2.0 नीति के संकेत मिल रहे हैं...

हम एक बार फिर स्पष्ट उद्देश्य से 'पूर्व' की ओर देख रहे हैं

भू-राजनीति

सैयद अता हसनैन
बिहार के राज्यपाल और कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा को हमें उस रणनीतिक बदलाव की शुरुआत का संकेत समझना चाहिए- जिसे एक्ट-ईस्ट 2.0 कहा जा सकता है। यह ऐसा परिवर्तन है, जिसमें हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को आकार देने में भूमिका निभाने पर ज्यादा जोर दिखता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत का रणनीतिक ध्यान स्वाभाविक रूप से अन्य क्षेत्रों की ओर केंद्रित रहा है। यूक्रेन में संघर्ष, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उत्तरी सीमाओं पर जारी सुरक्षा चुनौतियों में भारत की कूटनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश संकटों के एक समूह को अपनी रणनीतिक सोच पर स्थायी रूप से हावी नहीं होने दे सकता। उभरती ताकतों को भविष्य के अवसरों के लिए भी तैयारी करनी होती है।

इसलिए प्रधानमंत्री का पूर्वी देशों की ओर यह कूटनीतिक अभियान रणनीतिक संदेश देने का भी माध्यम है। देश अपनी प्राथमिकताओं का संकेत केवल आधिकारिक घोषणाओं से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी देते हैं कि उनके सर्वोच्च स्तर के राजनयिक दौरे किन देशों की ओर होते हैं। संदेश स्पष्ट है- भारत एक बार फिर स्पष्ट उद्देश्य के साथ पूर्व की ओर देख रहा है।

मूल एक्ट-ईस्ट नीति ने सम्पर्क, व्यापार, संस्थागत साझेदारियों और आसियान देशों से संबंधों के जरिये पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को दिशा दी थी। इस नीति ने यह स्वीकारा था कि भारत की समृद्धि इस क्षेत्र की गतिशीलता से अलग नहीं है। इसने अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन आज परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ चुका है।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र अब दुनिया की प्रमुख भू-राजनीतिक धुरी बनकर उभरा है। समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, समुद्र के भीतर का बुनियादी ढांचा, ऊर्जा आपूर्ति अब वैश्विक शक्ति-संतुलन को उतना ही प्रभावित करते हैं, जितनी सैन्य क्षमता। आर्थिक कूटनीति और सुरक्षा को अब अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। यदि एक्ट-ईस्ट के पहले चरण ने भारत को पूर्वी एशिया से जोड़ा था तो दूसरे चरण का उद्देश्य हिन्द-प्रशांत के रणनीतिक परिदृश्य को आकार देने में योगदान होना चाहिए।

अब भारत के पूर्वी हितों को क्वाड की गति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह समूह सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है, लेकिन यह न तो कोई सैन्य गठबंधन है और न ही हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति को आगे बढ़ाने का एकमात्र माध्यम। ऐसे समय में, जब अमेरिका का ध्यान चीन के साथ अपनी द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा और विशेष रूप से ताइवान के मुद्दे पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है और क्वाड पर अपेक्षाकृत कम राजनीतिक जोर नजर आता है, तब भारत को अपनी पूर्वोन्मुख रणनीति स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ानी होगी। इसका अर्थ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय साझेदारियों को मजबूत करना तथा एक्ट-ईस्ट 2.0 के केंद्र में आसियान को स्थापित करना।

बदलता क्षेत्रीय परिदृश्य भारत की अधिक सक्रिय भागीदारी की भी मांग करता है। यद्यपि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अब भी प्रमुख सैन्य शक्ति बना हुआ है, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों को लगता है कि उसका राजनीतिक ध्यान अब अधिक सिलेक्टिव हो गया है। चीन ने आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, समुद्री उपस्थिति और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों के जरिये अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया है। इस विस्तार का बड़ा हिस्सा उस ग्रे-जोन में होता है, जो खुले टकराव की सीमा से नीचे रहता है, लेकिन जिसके दीर्घकालिक रणनीतिक परिणाम होते हैं।

हिन्द-प्रशांत क्षेत्र 21वीं सदी के रणनीतिक शक्ति-संतुलन को परिभाषित करेगा। भारत अब इस क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक्ट-ईस्ट 2.0 नीति बताती है कि भारत का रणनीतिक क्षितिज अब पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

समय आ गया है कि हम रणनीतिक क्षमता के साथ रणनीतिक आत्मविश्वास का भी समुचित मेल करें। फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भारत की बढ़ती साझेदारियां- जिनमें रक्षा निर्यात भी शामिल है- यह संकेत देती हैं कि रक्षा साझेदारियां अब कूटनीति का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। ग्रेट निकोबार के विकास जैसी परियोजनाओं को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे केवल बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत के एक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने की प्रतीक हैं। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर
अब आप NYT के सभी आर्टिकल **DB एप** पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

फाइनेंस 2027 तक निवेश को 115 लाख करोड़ तक ले जाने की योजना बना रहीं अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, ब्याज दर बढ़ने से बिगड़ सकती है स्थिति

एआई में इस वर्ष 77 लाख करोड़ का दांव, डॉट कॉम बबल जैसे जोखिम की आशंका भी

जेफ सोमर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दौड़ में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां डेटा सेंटर और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका योगदान करीब 1.1% आंका जा रहा है, लेकिन अब तेजी से हो रहे विस्तार के पीछे बढ़ते कर्ज और अनिश्चित रिटर्न को लेकर चिंता बढ़ने लगी है।

अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा और ओरेकल ने इस साल एआई डेटा सेंटरों पर 77 लाख करोड़ रु. से अधिक निवेश किया है। कंपनियों की योजना 2027 तक इसे बढ़ाकर 115 लाख करोड़ रु. से ऊपर ले जाने की है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इतना बड़ा निवेश अपेक्षित मुनाफा देगा या नहीं। यदि एआई से अनुमानित कमाई नहीं हुई तो भविष्य में इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। इस जोखिम के शुरुआती संकेत शेयर बाजार में दिखाई देने लगे हैं। लंबे समय से स्थापित पांच बड़ी टेक कंपनियों में से चार का इस साल एसएंडपी 500 सूचकांक में प्रदर्शन कमजोर रहा है। सबसे ज्यादा दबाव ओरेकल पर दिखा, जिसके शेयर पिछले शुक्रवार तक 35% गिर चुके थे। वहीं, आईपीओ के बाद पहली बार स्पेसएक्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। आईबीएम के शेयर भी पिछले सप्ताह एक दिन में 25.2% टूट गए, जो 1960 के बाद उसकी सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट मानी जा रही है। कंपनी के सीईओ अरविंद कृष्णा ने इसके कारणों में एआई पर बढ़ते खर्च का भी उल्लेख किया। वित्तीय स्थिति के लिहाज से फिलहाल ओरेकल सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रही है। उसकी क्रेडिट रेटिंग में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की एएए रेटिंग अमेरिकी सरकार से भी बेहतर मानी जाती है। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि डेटा सेंटरों पर भारी पूंजी खर्च के बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपनी मजबूत साख कितने समय तक बनाए रख पाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा अकाउंटिंग नियमों के कारण कंपनियां इन भारी पूंजीगत निवेशों को सीधे खर्च के रूप में नहीं दिखातीं। इससे फिलहाल उनकी आय और बैलेंस शीट पर दबाव उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जितना वास्तविकता में हो सकता है।

बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार, जो टेक कंपनियां पहले कम पूंजी निवेश वाले मॉडल पर चलती थीं, वे अब एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी पूंजी-प्रधान कंपनियों की श्रेणी में पहुंच रही हैं। इसके कारण वे तेजी से बॉण्ड बाजार पर निर्भर हो रही हैं, जहां बढ़ते जोखिम के चलते निवेशक अब अधिक प्रीमियम मांगने लगे हैं। डेटा सेंटरों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा फिलहाल ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी एआई कंपनियों से जुड़ा है। लेकिन ये कंपनियां भी बड़े पैमाने पर कर्ज, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेश पर निर्भर हैं। ऐसे में एआई पर जारी रिकॉर्ड निवेश आखिरकार कितना लाभ देगा, इस पर अभी निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

भारी कर्ज ने डॉट कॉम दौर की याद दिलाई

बैंक ऑफ अमेरिका की रणनीतिकार सविता सुब्रमण्यम ने इस स्थिति की तुलना 1990 और 2000 के दशक के डॉट कॉम बबल वाले दौर से की है। तब इंटरनेट कंपनियां भारी उछाल के बाद ध्वस्त हो गई थीं। वे कहती हैं, बड़ी टेक कंपनियों का बिजनेस मॉडल कई पुरानी इंटरनेट कंपनियों के मुकाबले बहुत मजबूत है, लेकिन कर्ज चिंताजनक है। यदि एआई निवेश से उन्हें रिटर्न नहीं मिला या ब्याज दर बढ़ी तो स्थिति बिगड़ सकती है।

कई कंपनियों के बॉन्ड के मूल्यों में भारी गिरावट

अधिक पूंजी के लिए टेक कंपनियां मुख्यतः बॉन्ड बाजार में जा रही हैं, जिसने बढ़ते जोखिम की वजह से प्रीमियम लेना शुरू कर दिया है। उधर ओरेकल और अमेजन के बॉण्ड मूल्यों पर उल्टा असर पड़ा है। एआई डेटा सेंटर बना रही स्पेसएक्स की भी यही स्थिति है। उसके बॉन्ड कम कीमतों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिलहाल, एक समस्या है कि डेटा सेंटरों से अब तक निश्चित आमदनी होने जैसी स्थिति नहीं बन सकी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनाफे से अधिक हो रहा खर्च

दिग्गज टेक कंपनियां एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी-भरकम खर्च कर रही हैं। यह खर्च उनके मुनाफे से भी काफी ज्यादा हो रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट और मेटा का कुल पूंजी खर्च उनकी नगद आय से ज्यादा हो चुका है। इसका अर्थ है कि निवेश बनाए रखने के लिए इन कंपनियों को अधिक उधारी लेनी पड़ सकती है।

© The New York Times

इस हफ्ते चर्चा में...

इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में अमेरिका बहुत पीछे

25 प्रतिशत

है दुनियाभर में पिछले साल बिकी कारों में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या। यह नार्वे में 97%, चीन में 53 तो अमेरिका में 10% रही।

4500

से अधिक ब्रांड ने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हुए वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचों में विज्ञापन किए हैं।

960 करोड़ रु.

खर्च करेगी ताइवान की कंपनी टीएसएमसी एरिजोना, अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण पर।

नया ट्रेंड सामाजिक जुड़ाव के तरीके खोज रहे हैं युवा

नई अमेरिकी पीढ़ी कढ़ाई, बुनाई जैसी पारंपरिक स्किल सीख रही है

केट ब्रेनन

अमेरिका के कई राज्यों में युवाओं के शौक तेजी से बदल रहे हैं। पहले जहां इस मौसम में बैचलर पार्टियां और मनोरंजन गतिविधियां लोकप्रिय थीं, वहीं अब बड़ी संख्या में युवा बुनाई, कढ़ाई, बुक बाइंडिंग, पेपरमेकिंग और गलीचा बुनने जैसे पारंपरिक कौशल सीख रहे हैं। विशेषज्ञ इसे एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच मानवीय अनुभव और सामुदायिक जुड़ाव की तलाश से जोड़ रहे हैं।

मिशिगन के ग्रीन डोर फोक स्कूल में हाल में आयोजित गलीचा बुनने की कार्यशाला में अधिकांश प्रतिभागी 35 वर्ष से कम उम्र के थे। उत्तर कैरोलिना के एक फोक स्कूल में दाखिले के लिए तो वेटिंग लिस्ट तक बन रही है, जबकि कुछ वर्ष पहले वहां पर्याप्त छात्र नहीं मिलते थे। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट के अनुसार, ये पारंपरिक शौक लोगों को फिर से खुद से जोड़ रहे हैं। इनमें समय, धैर्य और एकाग्रता की जरूरत होती है, जो डिजिटल जीवन में कम होती जा रही है। फोक स्कूल अलायंस की

संचार समन्वयक मैरी सैनबोर्न का कहना है कि हस्तशिल्प सीखना लोगों को समुदाय और पारंपरिक कौशल से दोबारा जोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लोग अपने बुनाई और हस्तशिल्प प्रोजेक्ट साझा कर रहे हैं। पिनटेरेस्ट के अनुसार, सिलाई सीखने से जुड़े सर्च पिछले एक वर्ष में चार गुना बढ़े हैं, जिनमें अधिकांश उपयोगकर्ता 34 वर्ष से कम उम्र के हैं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की बेटी एला एमहॉफ ने भी न्यूयॉर्क में कम्युनिटी बुनाई क्लब शुरू किया है।

© The New York Times

अभियान

ईरान विरोधी मुहिम में इजराइली धर्मगुरु भी जुड़े

इसाबेल कर्शनर

इजराइल में यहूदी धर्मगुरु (राबी) अपने अनुयायियों को अस्वाभाविक संदेश दे रहे हैं। इन दिनों धार्मिक प्रवचन के साथ लोगों को ईरान के लिए जासूसी न करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। प्रमुख राबिनिकल काउंसिल के सदस्य यिगल कोहेन ने लोगों से कहा है कि ईरान के लिए जासूसी करने वालों को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। राबी कोहेन के अनुसार, इजराइली सैन्य अधिकारियों ने उनसे लोगों को आगाह करने का अनुरोध किया है, क्योंकि ईरानी एजेंट इजराइल में नागरिकों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत कई अन्य धर्मगुरुओं को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने ईरान के लिए कथित जासूसी के आरोप में 60 से अधिक लोगों पर मुकदमे चलाए हैं। इनमें सैनिक, आम नागरिक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इजराइल का मानना है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद ईरान ने देश के भीतर जासूसी नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है।

© The New York Times

सिनेमा ओडिसी को मिली 1200 करोड़ की ओपनिंग

3 हजार साल पुरानी कहानी से नोलन ने दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचा

ब्रुक्स बार्न्स

करीब दो दशक तक फ्रेंचाइजी फिल्मों और पहले से सफल कहानियों पर दांव लगाने वाले हॉलीवुड में क्रिस्टोफर नोलन ने अलग राह अपनाकर बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रीक कवि होमर की तीन हजार वर्ष पुरानी महाकाव्यात्मक कविता पर आधारित उनकी फिल्म 'ओडिसी' ब्लॉकबस्टर बनने की ओर बढ़ रही है।

फिल्म ने गुरुवार से रविवार के बीच अमेरिका और कनाडा में टिकट बिक्री से करीब 1200 करोड़ रु. की कमाई की है। दुनियाभर में इसकी शुरुआती कमाई 2540 करोड़ रु. रहने का अनुमान है। 2400 करोड़ रु. की लागत से बनी यह फिल्म 2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन सकती है। इससे आगे केवल टॉय स्टोरी (1540 करोड़ रु.) और सुपर मारियो गैलेक्स मूवी (1270 करोड़ रु.) हैं। यह ऐसे दौर में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब हॉलीवुड में फिल्मों से ज्यादा फ्रेंचाइजी किरदार दर्शकों को आकर्षित करते रहे हैं।

फिल्म में मैट डेमन, ऐन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, जेंडाया, टॉम हॉलैंड, चार्लीज थेरॉन, लुपिटा न्योंगो और एलियट पेज सहित कई बड़े कलाकार हैं। कुल कमाई का 24% हिस्सा आईमैक्स थिएटरों से आया है। करीब तीन घंटे लंबी फिल्म का निर्माण नोलन और उनकी पत्नी एमा थॉमस ने किया है। ओपेनहाइमर के लिए सात ऑस्कर जीत चुके नोलन एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि हॉलीवुड में आज भी कुछ फिल्में निर्देशक के नाम पर दर्शकों को थिएटर तक खींच सकती हैं।

© The New York Times

ट्रेंड • 2025-26 के लिए सेबी की रिपोर्ट... अमीर डरते हैं तो रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं

शेयर बाजार 1 साल में 5% गिरा तो अमीर भारतीयों ने प्रॉपर्टी निवेश 80% बढ़ाया

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शेयर बाजार में भारी उठापटक से घबराए अमीर भारतीयों (यूएचएनआई) ने निवेश की रणनीति बदल दी। बाजार नियामक सेबी के आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश 80% से भी ज्यादा बढ़ा दिया। यह बदलते हुए हालात में सुरक्षित निवेश की दिशा में अमीरों के बढ़ते कदम का साफ संकेत है।

इस साल अप्रैल तक एक साल में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) के जरिए अमीर भारतीयों ने रियल एस्टेट में 1.28 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। सिर्फ एक साल पहले यह निवेश 70,000 करोड़ रुपए था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सेंसेक्स में 5.2% गिरावट और दुनियाभर में अनिश्चित महौल के बीच धनाढ्य निवेशकों ने शेयर बाजार की जगह स्थिर आय वाले हार्ड एसेट्स (जैसे प्रॉपर्टी) को तरजीह दी। इस दौरान कुल एआईएफ (खास तौर पर अमीरों के लिए निवेश प्लेटफॉर्म) निवेश 25% बढ़कर 6.76 लाख करोड़ रुपए हो गया।

दिलचस्प है कि एआईएफ ने बीते वित्त वर्ष अलग-अलग सेक्टरों में कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम निवेश किया। इसमें से 42% यानी 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में गया।

अमीरों के पोर्टफोलियो की प्राथमिकता में इक्विटी अब भी तीसरे नंबर पर

धनाढ्य परिवारों ने फाइनेंशियल सर्विसेज में ₹65,000 करोड़ लगाए

सेक्टर	2024-25	2025-26	बढ़ोतरी
रियल एस्टेट	70,000	1,28,000	80%
फाइनेंशियल सर्वि.	27,000	65,000	140%
आईटी	35,000	40,000	14%
फार्मा	20,650	21,000	1.7%
कुल निवेश	5,38,000	6,76,000	25%

नोटः आंकड़े करोड़ रु में, निवेश AIF के जरिये, स्रोतः सेबी

निवेश के मामले में अमीरों का रुख बदलने के बड़े कारण

1. शेयर बाजार में कमजोरीः 2025-26 के दौरान सेंसेक्स में 5.2 फीसदी गिरावट आई। ट्रंप टैरिफ और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी वैश्विक अनिश्चितताएं इसकी सबसे बड़ी वजह रही।

2. मकानों की जोरदार मांगः देश के बड़े शहरों में मकानों की डिमांड मजबूत बनी रही। ग्रेड-ए ऑफिस और डेटा सेंटर के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री में भी तेज वृद्धि देखी गई।

3. ब्रांडेड प्रॉपर्टी पर जोरः ग्राहकों के बीच ब्रांडेड प्रॉपर्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऐसे में बेहतर बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से कंपनियों का जोखिम और रिटर्न का अनुपात सुधर गया है।

भास्कर नॉलेज ₹289 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले भारतीय अमीर परिवार, 5 साल में 63 फीसदी बढ़ गए

- 3 करोड़ डॉलर (₹289 करोड़) से ज्यादा संपत्ति वाले निवेशकों को यूएचएनआई (अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल) की श्रेणी में रखा जाता है।
- नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट, 2026 के मुताबिक, भारत में करीब 19,877 यूएचएनआई हैं। यह संख्या पूरी दुनिया में छठी सबसे बड़ी है।
- 2021 से लेकर 2026 के बीच भारत की यूएचएनआई आबादी में 63% का भारी-भरकम इजाफा हुआ है। नाइट फ्रैंक का अनुमान है कि साल 2031 तक भारत में अति अमीर परिवार 25,000 तक पहुंच जाएंगे।
- मुंबई में 35.4% और दिल्ली 22.8% यूएचएनआई हैं। इस हिसाब से इन दोनों शहरों में देश के आधे से ज्यादा (58.2%) हैं।

निवेश में प्राथमिकता इन एसेट क्लास को

1. रियल एस्टेटः सबसे ज्यादा निवेश, कुल एआईएफ निवेश का करीब 19%; ज्यादातर डेट (बॉन्ड) रूट से, फिक्स्ड इनकम के लिए।

2. फाइनेंशियल सर्विसेजः एनबीएफसी और प्राइवेट क्रेडिट में उछाल; बैंकों की ब्याज दर, प्राइवेट क्रेडिट रेट में अंतर का फायदा उठाने का प्रयास।

3. इक्विटी/आईटीः पारंपरिक रूप से निवेश में बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन एआई से जुड़ी अनिश्चितताओं से निवेश की रफ्तार धीमी पड़ी।

4. फार्मा/हेल्थकेयरः अमीर परिवारों के निवेश के मामले में सबसे सुस्त बढ़ोतरी। यह पूंजी बचाने को तरजीह देने के रुख का साफ संकेत।

सप्लाई घटी • होर्मुज जलमार्ग में नाकेबंदी से तेल की कीमतों में उछाल, डरे शेयर निवेशक

क्रूड 91 डॉलर पार, सेंसेक्स 443 अंक गिरा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार फिर 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 7.25% बढ़कर 91.42 डॉलर प्रति बैरल का स्तर छू गई। यह 11 जून के बाद का उच्चतम स्तर है। पिछले सप्ताह इसमें 15.9% की तेजी आई थी, जो अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त थी। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार नौवें दिन हमले किए गए। कुवैत और बहरीन ने भी ईरानी हमलों की सूचना दी है।

ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म आईएनजी के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। होर्मुज जलमार्ग से तेल की आवाजाही बाधित होने का डर निवेशकों में बना हुआ है। यही वजह रही कि घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान 783 अंक के दायरे मे घूमा। अंत में 443 अंकों के नुकसान के साथ 77,709 पर बंद हुआ। निफ्टी में 96 अंकों की गिरावट रही। यही 24,238 पर बंद हुआ। इससे पहले यह ट्रेडिंग के दौरान 130 अंकों के दायरे में घूमा। बाजार में यह गिरावट मार्जिन संबंधी चिंताओं और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आई। एचडीएफसी बैंक के कमजोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन (एनआईएम) ने बैंकिंग सेक्टर पर दोहरा दबाव बनाया है। इससे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। एक्सिस बैंक के शेयर 5.48% और एचडीएफसी बैंक के शेयर 5.12% गिरकर बंद हुए।

तंगी : दुनिया में भंडार पांच साल के निचले स्तर पर

ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म बार्कलेज के एनालिस्ट अमरप्रीत सिंह के मुताबिक, तेल बाजार स्टॉक की कमी को लेकर जरूरत से ज्यादा निश्चिंत है। लेकिन हकीकत यह है कि युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक तेल भंडार पांच साल के निचले स्तर पर आ गया है। रविवार को होर्मुज जलमार्ग से सिर्फ चार जहाज गुजर पाए, जबकि पिछले दिन यह संख्या आठ थी। शुक्रवार से अब तक तेल लोड करने के लिए तीन टैंकर और एक बड़ा क्रूड कैरियर ही इस रास्ते में दाखिल हो सके हैं।

भास्कर एक्सपर्ट

नरेंद्र तनेजा
ऑयल एक्सपर्ट

100 डॉलर प्रति बैरल की ओर बढ़ रहे क्रूड के दाम

अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की उम्मीद खत्म हो चुकी है। जुबानी जंग के बीच दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर के पार निकल गया है। यदि अगले चार-पांच दिन में मध्यस्थता नहीं हुई, तो तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच सकती हैं। यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि देश अपनी खपत का 90 फीसदी तेल आयात करता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से 'इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन' का खतरा बढ़ जाएगा।

रिटर्न फाइलिंग का सीजन अभी पीक पर, लेकिन इनकम टैक्स विभाग में 27,000 स्टाफ कम

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सीजन के बीच एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। 1 जनवरी तक की स्थिति के मुताबिक, आयकर विभाग में अधिकारियों और सहायक स्टाफ के 26,997 पद खाली हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

चौधरी ने बताया कि विभाग में ग्रुप ए, बी और सी श्रेणियों में करीब 27 हजार रिक्तियां हैं। पद खाली होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों को यूपीएससी या एसएससी के जरिए सीधी भर्ती और पदोन्नति के जरिए नियमित रूप से भरा जाता है। मंत्री ने बताया कि नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू होने से भाषा सरल हुई है, पुराने प्रावधान हटाए गए हैं और नियमों में सुधार हुआ है। साथ ही रिटर्न की तेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स और फेसलेस असेसमेंट जैसी डिजिटल पहल से टैक्स प्रशासन को आधुनिक बनाया जा रहा है।

एक अन्य सवाल के जवाब में चौधरी ने बताया कि 2024 से अब तक 11 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और इनकी ₹1,303 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इनमें से 8 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और 4 के प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं।

बिजनेस ब्रीफ

इक्विटीः टैक्स खत्म करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली| सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (एलटीसीजी) टैक्स खत्म करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2024-25 में एलटीसीजी से सरकार को ₹2.01 लाख करोड़ का राजस्व मिला, जो पिछले साल से 78% ज्यादा है।

वाडिया रियल्टी की 95 एकड़ जमीन की नीलामी करेंगे बैंक

मुंबई| सेंट्रल बैंक के नेतृत्व में बैंकों ने गो फर्स्ट (गो एयरलाइंस) के ₹3,918 करोड़ बकाया वसूलने के लिए वाडिया रियल्टी की ठाणे की 95 एकड़ जमीन नीलाम कर रहे हैं। इसकी न्यूनतम कीमत ₹1,375 करोड़ रखी गई है। 20 अगस्त को सरफेसी एक्ट के तहत इसकी नीलामी की जाएगी। यह प्रॉपर्टी संपत्ति गो एयरलाइंस के कर्ज के लिए गिरवी रखी गई थी।

कोर इंफ्रा सेक्टर की ग्रोथ 5 महीनों के ऊंचे स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली| जून में देश के नौ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का उत्पादन 5% बढ़ा, जो 5 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। बीते माह सीमेंट और बिजली उत्पादन 9.8% और लौह अयस्क 43.9% बढ़ा। नई सीरीज (बेस ईयर 2022-23) में लौह अयस्क शामिल किया गया है। अप्रैल-जून में ग्रोथ 3.6% रही। क्रूड ऑयल, गैस के उत्पादन में कमी आई।

अबु धाबी से अब 22 भारतीय शहरों के लिए सीधी फ्लाइट

अबु धाबी| जायेद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगस्त से 22 भारतीय शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स तक बढ़ाएगा। अभी यहां से 17 भारतीय शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नवी मुंबई, इंदौर, लखनऊ से नई सर्विस शुरू की। इंडिगो और अकासा एयर भी उड़ानें संचालित कर रही हैं। भारत अबू धाबी का मजबूत टूरिज्म मार्केट है।

आईएलएंडएफएस ने ₹50 हजार करोड़ कर्ज चुकाया

मुंबई| आईएलएंडएफएस ग्रुप जून तक ₹50,387 करोड़ कर्ज चुकाक लक्ष्य (61,000 करोड़) के 82.6% तक पहुंच गया। अब तक सरकारी बैंकों के 88.4% लोन चुका दिए गए हैं। एसेट मॉनेटाइजेशन से ₹26,027 करोड़ वसूले गए। एनसीएलएटी को दिए हलफनामे में यह जानकारी दी गई। ग्रुप ने अब तक कुल ₹99,377 करोड़ के बकाए में से काफी हद तक कर्ज उतार दिया है।

तैयारी • चीन पर निर्भरता घटाने की बनी रणनीति

ईवी की बैटरी भारत में बनेगी, ₹18,100 करोड़ की योजना

अक्षिता सिंह | नई दिल्ली

देश में ₹18,100 करोड़ की पीएलआई योजना से ईवी बैटरियों का निर्माण शुरू हो रहा है। इसके तहत अब असेंबलिंग के बजाय देश में ही लिथियम-आयन सेल बनाए जाएंगे। थिंक टैंक आईसीआरआईईआर के अनुसार ईवी की आधी लागत केवल बैटरी से आती है। हालांकि, केवल सेल बनाने से गाड़ियां तुरंत सस्ती नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की पॉलिसी रिसर्चर रिझुल लाढ़ा के मुताबिक, भारत 99% से अधिक सेल आयात करता है। देश में सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन और पीएम ई-ड्राइव योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार के 50 गीगावाट आवर क्षमता के लक्ष्य में से अक्टूबर 2025 तक 1.4 गीगावाट आवर क्षमता ही चालू हो पाई है। इसे गति देने के लिए 10 गीगावाट का नया टेंडर जारी किया गया है।

चुनौतीः खनिजों के लिए चाहिए रीसाइक्लिंग ढांचा

बैटरी रीसाइक्लिंग फर्म लोहम के फाउंडर व चीफ एग्जीक्यूटिव रजत वर्मा कहते हैं, 'रीसाइक्लिंग से 40-50% खनिज मिल सकते हैं।' हालांकि ब्रिकवर्क के नीरज राठी और बी-गॉस के अंकित गागर का मानना है कि केवल बैटरी नहीं, बल्कि पूरे कल-पुर्जों का घरेलू निर्माण जरूरी है।

पानी में बसी समृद्धिः बांस के पिंजरों में पल रहीं महंगी ईल मछलियां, ये चीन के किसानों की आय का अतिरिक्त स्रोत

बीजिंग| चीन के जियांग्शी प्रांत के नानचांग की इस तस्वीर में एक किसान बांस के पिंजरों में पल-बढ़ रहीं ईल मछलियों की देखभाल करता नजर आ रहा है। इस इलाके में मीठे पानी की भरमार का फायदा उठाते हुए स्थानीय प्रशासन ने पर्यावरण के अनुकूल एक्वाकल्चर बेस बनाए हैं। इससे किसानों को खेती के अलावा आय का नया जरिया मिल गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईल उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया को करीब 85% ईल सप्लाई चीन से होती है।

उलटफेर • चार साल में बदली तस्वीर

गांवों में बैंक जमा 41% बढ़ा, शहरों में 11% घटा

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

बड़े शहरों में बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ रही है। दूसरी तरफ गांव और छोटे कस्बों में यह तेजी से बढ़ रही है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं, जनधन खातों और सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की स्कीमों ने ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग को नई रफ्तार दी है।

सोमवार को जारी रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमा वृद्धि 4 साल में करीब 41% बढ़ी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि करीब 20% रही। इसी दौरान महानगरों में यह वृद्धि 21% प्रतिशत रही। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों (छोटे-मझोले शहर) में बैंक डिपॉजिट वृद्धि करीब 11% घट गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जनधन योजना के 58 करोड़ खातों में से 45 करोड़ गांव और छोटे शहरों की बैंक ब्रांच में हैं।

मार्च-22 से मार्च-26 के बीच डिपॉजिट ग्रोथ 15%

इलाके	जमा वृद्धि
ग्रामीण	+41%
महानगर	+21%
अर्ध-शहरी	+20%
शहरी	-11%
कुल वृद्धि	+15%

स्रोतः एसबीआई रिसर्च

शहर जैसी सुविधाओं वाले गांव-कस्बे नए जमा केंद्र

- कुल बैंक डिपॉजिट में परिवारों की हिस्सेदारी 2021-22 के 62.6% से घटकर 2025-26 में 59.3% रह गई।
- चार वर्षों में गैर-वित्तीय संस्थाओं (ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल-कॉलेज खाते) की हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 18.5% हो गई।
- सेंसस टाउन (गांव जैसा दर्जा पर शहर जैसी सुविधाओं वाले कस्बे) 2001-2011 के बीच 185% की दर से बढ़े, ये नए जमा केंद्र बनते जा रहे हैं।
- कुल 58 करोड़ जनधन खातों में से 45 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में हैं।

शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश 3 साल में 5.5 गुना

एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में परिवारों ने बैंक जमा से पैसा निकालकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर में लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में परिवारों ने करीब ₹1.8 लाख करोड़ निवेश के इन साधनों में लगाए थे। 2024-25 में यह बढ़कर ₹9.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यानी तीन साल में करीब 5.5 गुना उछाल आया। 2025-26 में यह आंकड़ा थोड़ा घटकर ₹8.9 लाख करोड़ रहा, फिर भी यह 2022-23 के मुकाबले करीब 5 गुना ज्यादा है। इसी दौरान रिटेल डिपॉजिट में शेयर-म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़कर 6% हो गई, जो पहले सिर्फ 1% थी।

साइबर सुरक्षा में गंभीर चूक भारी पड़ी

रिस्की सिस्टम, सेबी ने CDSL पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

सेबी ने नवंबर 2022 के मालवेयर हमले से जुड़ी साइबर सुरक्षा चूक के मामले में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस हमले से सेटलमेंट प्रक्रिया 46 घंटे और इंटर-डिपॉजिटरी ट्रांसफर प्रक्रिया 54.5 घंटे बाधित रही थी। बाजार नियामक के मुताबिक, इस रुकावट का पूरे सिक्युरिटी मार्केट पर व्यापक असर हुआ था। यह हमला लंबे समय से नियमों की अनदेखी और सुरक्षा उपायों की कमी का नतीजा था। आदेश के मुताबिक, हमलावर ने नवंबर, 2021 में ही सर्वर में सेंध लगा ली थी, जिसकी जानकारी नवंबर, 2022 में मिली। सीडीएसएल ने 2021 में एक ऐसा एडमिन अकाउंट बनाया था, जिसका पासवर्ड कभी बदलना ही नहीं पड़ता था। इसके अलावा, तीन बार गलत पासवर्ड डालने पर अकाउंट लॉक होने वाला सुरक्षा नियम भी लागू नहीं था। सेबी के आदेश में कहा गया कि डिपॉजिटरीज सीडीएसएल और एनएसडीएल का आपस में जुड़ा होना साइबर हमले के खतरे को बढ़ा देता है।

वैश्विक विस्तार की तैयारी में कंपनी

इंडिगोः सीएफएम से 1,000 इंजन का ऐतिहासिक करार

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

बजट एयरलाइन इंडिगो ने अपने आगामी 510 एयरबस ए320नियो विमानों के लिए 1,000 से ज्यादा सीएफएम लीप-1ए इंजन खरीदने को लेकर सीएफएम इंटरनेशनल के साथ करार किया है। यह लीप इंजनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है। यह सीएफएम इंटरनेशनल के लिए भी एक रिकॉर्ड है। इस डील में इंडिगो के आगामी इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) सेंटर की स्थापना में सीएफएम का सहयोग भी शामिल है। साथ ही स्पेयर पार्ट्स सप्लाई के लिए एक लंबी अवधि का करार भी हुआ है। इंडिगो के सीईओ विली वॉल्श ने कहा कि कंपनी अब वैश्विक एयरलाइन बनने की दिशा में अगले चरण में कदम बढ़ा रही है। कंपनी का बेड़ा फिलहाल 375 से ज्यादा ए320/321 विमानों तक पहुंच चुका है। यह करार इंडिगो की भारत और दुनियाभर में अपने नेटवर्क को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।

इंडेक्स 26% चढ़ने का दिखा असर

स्मॉल-कैप फंड्स से निकासी अब 28 माह में सबसे आसान

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा फंसने की चिंता कर रहे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। टॉप-10 स्मॉल-कैप फंड्स को आधे शेयर बेचने में अब औसतन 27 दिन लग रहे हैं। यह मार्च 2024 के बाद यानी 28 महीने में सबसे कम समय है। जनवरी 2026 में इसमें 44 दिन लग रहे थे। दरअसल, मंदी या सुस्ती के समय खरीदार न मिलने से फंड मैनेजरों को शेयर बेचकर पैसा लौटाने में बहुत समय लगता है। इसे पैसा फंसा होना या लिक्विडिटी की कमी कहा जाता है। अधिकांश स्मॉल-कैप फंड्स के लिए बेंचमार्क निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स अप्रैल 2026 से अब तक 26% चढ़ चुका है। इसके चलते अग्रणी फंड्स में शेयरों की बिक्री का समय काफी कम हुआ है। क्वांट फंड में आधा पोर्टफोलियो बेचने का समय 102 दिन से घटकर 45 दिन, टाटा में 69 से घटकर 36 दिन और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में 75 से घटकर 46 दिन रह गया है। इसके अलावा 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है।

बिजनेस एंकर दुनिया में हर जॉब पर औसतन 250 आवेदन, रेफरल से चयन की संभावना 18 गुना ज्यादा

सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गूगल ने 12, माइक्रोसॉफ्ट ने 16 रिजेक्शन के बाद चुना; सबक...जितने प्रयास करेंगे, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ेगी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

नौकरी की तलाश करते समय बार-बार रिजेक्शन ज्यादातर लोगों को हतोत्साहित कर देता है। लेकिन इस मामले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी ने साबित किया है कि लगातार कोशिश आखिरकार रंग लाती है। सौम्यदीप पॉल (27) फिलहाल अमेजन में काम करते हैं। लेकिन यह नौकरी उन्हें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए संघर्ष और अनुभव को उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया।

पॉल ने बताया कि गूगल में उनका सिलेक्शन 13वें प्रयास में हुआ। उन्होंने लिखा, 'मुझे 12 बार रिजेक्ट किए जाने के बाद गूगल में नौकरी मिली। 13वें प्रयास में बात बनी।' उनके मुताबिक, यह सिर्फ गूगल की कहानी नहीं थी। अमेजन ने उन्हें तीन बार ठुकराने के बाद नौकरी दी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने 16 बार रिजेक्ट करने के बाद ऑफर भेजा। दिलचस्प है कि एपल और ओरेकल जैसी कंपनियों से उन्हें कभी कॉलबैक तक नहीं मिला। अपने अनुभव के आधार पर पॉल का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी पाना काफी हद तक 'नंबर्स का खेल' है। यानी जितनी बार आप कोशिश करेंगे, सफलता की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। उन्होंने सलाह दी कि उम्मीदवारों को लगातार आवेदन करते रहना चाहिए। कंपनी के भीतर मौजूद कर्मचारियों से रेफरल लेने की कोशिश करनी चाहिए और रिजेक्शन से निराश होने के बजाय अपने स्किल्स सुधारते रहना चाहिए। हालांकि, पॉल ने आगाह भी किया कि आवेदन बिना सोचे-समझे नहीं भेजना चाहिए। उनके मुताबिक, रिज्यूमे को नौकरी की जरूरतों के हिसाब से ठीक से मिलाना जरूरी है। अगर किसी की कंपनी के भीतर जान-पहचान हो, तो आवेदन जमा करने के बाद रिक्रूटर का ईमेल पता लेकर जॉब आईडी और रिज्यूमे के साथ सीधे मेल भेजना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हायरिंग मैनेजरों से सीधे संपर्क करने का सुझाव भी दिया, हालांकि माना कि उन्होंने खुद यह तरीका इस्तेमाल नहीं किया, पर दूसरों को इससे फायदा होते जरूर देखा है। पॉल की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई। एक यूजर ने असहमति जताते हुए लिखा कि बड़ी टेक कंपनियों में सफलता सिर्फ बार-बार कोशिश से नहीं, बल्कि उम्मीदवार के बैकग्राउंड पर भी निर्भर करती है। रिज्यूमे में बड़े ब्रांड नाम होना भी मायने रखता है।

प्रोफेशनल्स को जॉब ऑफर मिलने से पहले 200 तक आवेदन करने पड़ रहे

रिजेक्शन की तकलीफ झेलने वाले पॉल अकेले नहीं हैं। करिअर प्लेटफॉर्म 'द इंटरव्यू गाइज' के मुताबिक, 2025 में नौकरी तलाशने वाले हर प्रोफेशनल को ऑफर मिलने से पहले 32 से 200 तक आवेदन करने पड़े। ग्लोबल हायरिंग प्लेटफॉर्म 'हायरिंगथिंग' के आंकड़े कहते हैं कि हर जॉब पोस्टिंग पर औसतन 250 आवेदन आते हैं, पर सिर्फ 2-3% को ही इंटरव्यू कॉल मिलती है। वहीं रिक्रूटमेंट डेटा कंपनी 'जेम' की रिपोर्ट बताती है कि रेफरल से आवेदन करने वालों के सिलेक्ट होने की संभावना सीधे आवेदन करने वालों के मुकाबले 18 गुना ज्यादा होती है।

कंपनियों ने पर्यावरण पर खर्च किए ₹17,377 करोड़

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय कंपनियों ने बीते एक दशक में पर्यावरण से जुड़े कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) से जुड़े काम पर ₹17,377 करोड़ खर्च किए हैं। यह कुल सीएसआर खर्च का सिर्फ 8.4% है। बेंगलुरु स्थित सत्व कंसल्टिंग की रिपोर्ट 'अ डिकेड ऑफ ग्रीन स्पेंडिंग' के मुताबिक, यह खर्च भारत के 2030 जलवायु लक्ष्यों के लिए जरूरी करीब ₹240 लाख करोड़ के मुकाबले बेहद कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर पैसा पानी प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा और पौधरोपण जैसे छोटे प्रोजेक्ट में लगा, जबकि हवा की गुणवत्ता को महज 5% हिस्सा मिला। सिर्फ 22% कंपनियां ही पर्यावरण पर खर्च करती हैं। 68 बड़ी कंपनियां कुल पर्यावरण सीएसआर में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती हैं।

रणनीति • बड़े कॉरपोरेट का पसंदीदा एसेट क्लास

एलएंडटी, अजीम प्रेमजी ने इनविट में ₹4,800 करोड़ निवेश किया

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश के बड़े कॉरपोरेट समूह अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट में भारी निवेश कर रहे हैं। एलएंडटी ग्रुप और विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के फैमिली ऑफिस प्रेमजी इनवेस्ट ने इस एसेट क्लास में कुल ₹4,822 करोड़ निवेश किया है। यह दिखाता है कि कॉरपोरेट ट्रेजरी और फैमिली ऑफिस अब पारंपरिक निवेश से आगे बढ़कर इस नए एसेट क्लास में दिलचस्पी ले रहे हैं।

प्रेमजी इनवेस्ट ने क्यूब हाइवेज के ₹5,000 करोड़ के आईपीओ में करीब ₹950 करोड़ का रणनीतिक निवेश किया। दूसरी तरफ एलएंडटी ने जून में ब्रुकफील्ड समर्थित अल्टियस इनविट में करीब ₹627 करोड़ की यूनिट्स खरीदे हैं। पिछले दो वर्षों में एलएंडटी करीब एक दर्जन इनविट्स में ₹3,500-4,000 करोड़ लगा चुकी है।

डेट, शेयर निवेश के बीच का विकल्प बने इनविट

इनविट्स डेट (बॉन्ड) और शेयर निवेश के बीच का विकल्प बनते जा रहे हैं। ये नियमित कैश के साथ सालाना 12-15% रिटर्न देते हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितता के बीच फैमिली ऑफिस और कॉरपोरेट निवेशकों को यह एसेट क्लास स्थिर आय के लिए आकर्षक लग रहा है। देश का रीट-इनविट बाजार करीब ₹10 लाख करोड़ का है।

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]

📍 Hindi Editorials PDF

📍 Daily Vocabulary PDF

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world. Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Click below to Join this Community 👇

Click Here